राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 194

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 22 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज जीतने उतरेगी विराट की सेना

>> 14

उत्तर प्रदेश में फिर भड़की हिंसा, बिहार में भी उपद्रव

सीएए का विरोध ▸ रामपुर और कानपुर में उपद्रवियों ने की आगजनी, 124 मुकदमे दर्ज, 705 गिरफ्तार, पटना में 12 घायल

बिहार में बंद के दौरान कई जगह तोड़फोड़, पुलिस और मीडियाकर्मियों पर हमला

जेएनएन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शनिवार को जहां दिल्ली सहित अन्य राज्यों में आमतौर पर शांति रही, वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कड़े रुख के बाद भी कई जिलों में हिंसक घटनाएं हुईं। राजद के राज्यव्यापी बंद के आह्वान पर बिहार में भी हिंसा हुई। पटना के फुलवारीशरीफ में विरोध प्रदर्शन के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए जिसमें 12 लोग घायल हो गए जिसमें दो की हालत गंभीर है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में उपद्रवियों ने वाहनों में आगजनी के साथ पुलिस को निशाना बनाया। कानपुर में शुक्रवार को भड़की हिंसा में दो की मौत के बाद शनिवार दोपहर बाद उपद्रवियों ने यतीमखाना पुलिस चौकी पर पेट्रोल व देसी बम से हमला कर दिया। उपद्रवियों ने चौकी के बाहर खड़ी दो बाइक व दो कारें फूंक दीं। फायरिंग भी की जिसमें एक सिपाही घायल हो गया है, जबकि पथराव में दारोगा भी घायल है। एडीजी प्रेमप्रकाश ने बताया कि भीड़ को भड़काने और बलवे में शामिल होने के आरोप में आर्य नगर से विधायक अभिताभ वाजपेयी व पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, शुक्रवार को गोली लगने से घायल 13 लोगों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। फीरोजाबाद में शुक्रवार को हुए उपद्रव के दौरान फायरिंग में घायल एक और युवक की मौत हो गई। मेरठ में हिंसा की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरठ में अब तक पांच की मौत हो चुकी है। बिजनौर में दो और मुजफ्फरनगर में एक की मौत हुई है।

सोशल मीडिया पर 14101 पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 63 मुकदमें दर्ज कराए गए हैं। पुलिस ने 102 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा 442 आरोपितों को पाबंद किया है। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार, हिंसा के दौरान अब तक आठ जिलों में 15 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दो अन्य व्यक्तियों के मरने की सूचना भी फैली, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

आइजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 10 दिसंबर से अब तक विभिन्न जिलों में प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ व पुलिस पर फायरिंग की घटनाओं में 124 एफआइआर दर्ज कर 705 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सैकड़ों आरोपितों को नामजद करते हुए हजारों अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों को चिह्नित कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने 4500 से अधिक लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की है। उपद्रव के दौरान अब तक 263 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें 57 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। जिन-जिन स्थानों पर हिंसा व उपद्रव हुआ, वहां से पुलिस ने गैर प्रतिबंधित बोर के 405 खोखे व कई तमंचे भी बरामद किए हैं।

बिहार में बंद और प्रदर्शन से जनजीवन अस्त-व्यस्त : सीएए के विरोध में राजद के बिहार बंद के दौरान राज्य के सभी शहरी इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। एहतियातन स्कूल-कॉलेज, कार्यालय और बाजार सुबह से बंद रखे गए। जहां खोलने की कोशिश हुई, वहां पहुंचकर बंद समर्थकों ने हंगामा किया। विभिन्न जिलों में उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थर बरसाए। राजधानी पटना और आसपास के जिलों में बंद के नाम पर आगजनी की गई और ट्रेनें रोकी गईं। फुलवारीशरीफ में दो पक्ष भिड़ गए। देर तक पथराव-फायरिंग हुई और छुरे चले। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। हंगामा कर रहे लोगों ने मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया।

दैनिक जागरण के फोटो पत्रकार का सिर फोड़ दिया। आधा दर्जन मीडिया कर्मियों के कैमरे तथा टीवी चैनलों की आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन (ओबी वैन) के शीशे तोड़ दिए। दो पुलिस जवानों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, फुलवारीशरीफ में विभिन्न संगठनों के लोग अलग-अलग टुकड़ियों में शहीद चौक से नारेबाजी करते जुलूस की शक्ल में निकले। भीड़ में उपद्रवी और असामाजिक तत्व भी थे। सभी टमटम पड़ाव पर पहुंचने के बाद संगतपर मोहल्ले से आगे बढ़ने पर अड़ गए। उस वक्त पुलिस नहीं थी। जब दूसरे पक्ष के लोगों ने मोहल्ले में घुसने से मना किया तो शरारती तत्व एक धार्मिक स्थल में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इससे बवाल बढ़ गया। लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और पिटाई करने लगे। इसके बाद दोनों ओर से पथराव होने लगा। इस बीच एक युवक को लोगों ने चाकू घोंप कर घायल कर दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। 50 राउंड से अधिक फायरिंग हुई। एक दर्जन लोगों को गोली लगी। जैसे-तैसे लोग घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले गए।

घटना के एक घंटे बाद डीएम कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए 250 राउंड से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में भी सड़क जाम, प्रदर्शन और नारेबाजी के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव हुआ। ट्रेनें भी रोकी गई।

(विशेष सामग्री पेज-5, 7 और 8)

नागरिकता कानून के विरोध में शनिवार को कानपुर में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो उठी। इस दौरान उपद्रवियों ने यतीमखाना पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। जागरण

14101 सोशल मीडिया पोस्टों पर हुई कार्रवाई

63 मुकदमे दर्ज कर 102 की गिरफ्तारी

कोलकाता में भाजपा मुख्यालय घेरने की कोशिश

बंगाल में भी विरोध के स्वर उठे। छात्रों ने कोलकाता स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय के घेराव की कोशिश की। इसमें हजारों वामो, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समर्थित छात्र शामिल हुए। दूसरी ओर सीएए के समर्थन में भाजपा समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया।

मध्य प्रदेश के जबलपुर के चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी

सीएए के विरोध में मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुक्रवार को किए गए उग्र प्रदर्शन के बाद शनिवार को हालात सामान्य रहे। हालांकि शहर के चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। शनिवार को कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी गई। उपद्रव को लेकर छह मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 35 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 51 नामजद सहित 500 से अधिक अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

सरोकार

37 साल से निराश्रित मरीजों की सेवा में जुटे हैं कर्मचारी

हरिद्वार : हरिद्वार के हरमिलाप जिला अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी 1983 से ऐसे बीमारों की सेवा में जुटे हैं, जिनका अपना कोई नहीं है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को अकेलेपन का अहसास न हो, इसके लिए कर्मी तीज-त्योहार की खुशी उनके साथ साझा करते हैं। (पेज-11)

रविवार विशेष

क्योंकि दौड़ने के लिए जूते नहीं जिद और जज्बा चाहिए...

देवघर : झारखंड में देवघर के एक स्कूली फुटबॉल टीम के खिलाड़ी जज्बे और जीवटता की अलग कहानी बयां कर रहे हैं। अभाव के बावजूद गरीब घरों के इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

नहीं मान रहे महातिर, फिर की दखलअंदाजी

नई दिल्ली : इस्लामिक देशों के अगुआ बनने की धुन में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद भारत के साथ अपने देश के रिश्तों को तार-तार करने पर आमदा हैं। भारत की तरफ से पिछले दो दिनों में दो बार आपत्ति जताने के बावजूद मुहम्मद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को नई दिल्ली में मलेशिया के राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें भारत के गुस्से से अवगत कराया।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

पाक चौकियां व जैश का लांचिंग पैड तबाह, दो सैनिक भी ढेर

जम्मू : जम्मू से कश्मीर तक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलाबारी कर रहे पाकिस्तान के दो सैनिकों को भारत के जांबाजों ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के दुदनियाल और एथमुकाम में भी तीन पाकिस्तानी चौकियों और आतंकियों के एक लांचिग पैड को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैन्य प्रशासन ने नियंत्रण रेखा पर तैनात सभी अधिकारियों और जवानों को पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में तैयार रहने का निर्देश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

रूस और तुर्की पर प्रतिबंधों के विधेयक को ट्रंप ने दी मंजूरी

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध के प्रावधान वाले 738 अरब डॉलर (करीब 52 लाख करोड़ रुपये) के रक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून 2020 को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही अमेरिकी सैन्य खर्च में 20 अरब डॉलर (डेढ़ लाख करोड़ रुपये) की वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल पर शुक्रवार रात ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर हस्ताक्षर किए गए।

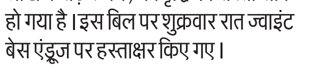

तीसरा वनडे: भारत vs वेस्टइंडीज

दोपहर 1:30 बजे से

स्थान : कटक

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

जेपी ग्रुप का फार्मूला वन व क्रिकेट स्टेडियम का भूखंड आवंटन रद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▸ यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 864 करोड़ बकाया नहीं देने पर की कार्रवाई

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 864 हजार करोड़ रुपये का बकाया नहीं देने पर जेपी ग्रुप (जयप्रकाश एसोसिएट्स) को स्पेशल डेवलपमेंट जोन (एसडीजेड) के लिए आवंटित 1015 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रद कर दिया। जमीन पर स्पोर्ट्स सिटी, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (रेसिंग ट्रैक) और क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। 11 अन्य बिल्डरों को भी जेपी ने सब लीज पर जमीन का कुछ भाग बेचा था। इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट में दस हजार फ्लैट व भूखंड में खरीदारों का पैसा फंसा हुआ है। वहीं, स्पोर्ट्स सिटी में करीब तीन हजार फ्लैट खरीदार हैं। प्राधिकरण रेसिंग ट्रैक और क्रिकेट स्टेडियम को नीलाम करेगा और इससे प्राप्त धनराशि से निवेशकों की बुकिंग की राशि लौटाई जाएगी।

शनिवार को बोर्ड बैठक के बाद यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेपी पर प्राधिकरण का 864 करोड़ रुपये बकाया है। इसकी वसूली के लिए प्राधिकरण व जेपी ने संयुक्त रूप से बैंक में एस्क्रो अकांउट खोला था। अकाउंट में जेपी ने 15 लाख रुपये जमा कराए। बकाया वसूली के लिए कई बार नोटिस दिया गया, पर रकम जमा नहीं कराई गई। ऐसे में बोर्ड ने भूखंड आवंटन रद करने का फैसला किया।

जमीन पर जेपी के ये हैं प्रोजेक्ट : कंट्री होम्स, क्राउंस ग्रीनक्रेस्ट होम्स, बौगन विलेज, विला एक्सपेंजा, स्पोर्ट्सविले, कासिया, कोव, बुद्ध सर्किट स्टूडियो।

दूसरे बिल्डरों को बेची जमीन पर ये हैं प्रोजेक्ट : जेपी एसआइ लिमिटेड, इम्पीरिया होम्स एफ थ्री प्राइवेट लि., रॉयल होमटाउन प्लानर्स, पिरामिड टाउनशिप, सॉलिटेयर रियल इंफ्रा प्राइवेट लि., प्रेसिडेंसी इंफ्राहाइट, मेसर्स एमएमए डेवलपर्स, मेसर्स वीजीए डेवलपर्स, मेसर्स पिरामिड ए थ्री, सोल इंफ्राटेक प्राइवेट लि., इम्पीरिया होम्स ए पांच। बता दें कि 2008 में बसपा शासन काल में जेपी को यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बहुत सस्ती दर पर1015 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। (पेज-2 भी देखें)

यमुना प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरूणवीर सिंह। जागरण

जेपी एसोसिएटस की तरफ से जमीन की कीमत के रूप में यमुना प्राधिकरण को ढाई हजार करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि दी जा चुकी है। करीब सात सौ करोड़ रुपये बकाया है। प्राधिकरण का नियोजन विभाग हमारे प्रोजेक्टों के मानचित्र स्वीकृत नहीं कर रहा है।

– अशोक खेड़ा, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट, जेपी एसोसिएट्स

सीमा पर शांति बनाए रखने पर भारत-चीन राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ दोनों देश सीमा विवाद का भी जल्द समाधान निकालने पर रजामंद

▸ एनएसए डोभाल व चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुआई में हुई वार्ता

भारत व चीन में इस बात के लिए रजामंदी बनी है कि दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो शांति स्थापित हुई है उसे आगे भी बनाए रखा जाएगा। शनिवार को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की अगुआई में हुई बैठक में यह भी सहमति बनी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सीमांकन और उसके स्थायी हल की कोशिश और तेज की जाएगी। सीमा विवाद सुलझाने के लिए की गई व्यवस्था के तहत यह 22वीं बैठक थी।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अगुआई में शनिवार को यह बैठक हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में मुख्य तौर पर चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई वार्ता के मुताबिक आगे द्विपक्षीय रिश्ते प्रगाढ़ बनाने व भरोसा मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। अक्टूबर, 2019 में हुई बैठक के बाद दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह से प्रगति हो रही है, इसकी भी समीक्षा की गई है। दोनों देशों ने इस बात की जरूरत बताई कि भारत-चीन के रणनीतिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए सीमा विवाद का स्थायी हल निकालना चाहिए।

दोनों पक्ष इस बात के लिए रजामंद हैं कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक सीमा पर शांति बनी रहनी चाहिए ताकि द्विपक्षीय रिश्तों के दूसरे आयामों में तरक्की होती रहे। इसके लिए हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भरोसा बहाली के लिए जो उपाय किए गए हैं, उन्हें भी जारी रखना चाहिए। सनद रहे कि मोदी और चिनफिंग के बीच अप्रैल, 2018 में पहली अनौपचारिक बैठक के बाद दोनों देशों के सैन्य अफसरों को रणनीतिक संदेश दिया गया था कि वे आपसी भरोसे को बनाने का काम करे। इसका सकारात्मक असर दिखा है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई असहज स्थिति नहीं बनी है जैसा कि डोकलाम में हुआ था। शनिवार को हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठा और दोनों तरफ के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि एक दूसरे की संवेदनाओं और चिंताओं का ख्याल रखना जरूरी है तभी आगे भरोसा मजबूत होगा। विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक चीन में होगी।

नई दिल्ली में बैठक से पूर्व चीनी विदेश मंत्री वांग यी (बाएं) व एनएसए अजीत डोभाल। एएनआइ

रांची की निर्भया को मिला इंसाफ गुनहगार को फांसी की सजा

रांची : झारखंड की राजधानी रांची में बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने शनिवार को दोषी राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन (25 वर्ष) को फांसी की सजा सुनाई। 1101 दिन बाद रांची की इस निर्भया को इंसाफ मिला है। दोषी राहुल राज मूलत: बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है और आपराधिक प्रवृत्ति का है। (पेज-6)

राजस्व बढ़ाने के लिए आयकर विभाग लेगा जीएसटी की मदद

नई दिल्ली : राजस्व रफ्तार बढ़ाने के लिए आयकर विभाग जीएसटी के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास करेगा। इसके लिए आयकर विभाग करदाताओं की इनपुट टैक्स क्रेडिट और आयकर रिटर्न की सूचनाओं का मिलान करेगा। दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच सूचनाएं साझा करने पर सहमति बनी है। रेवेन्यू विभाग में शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस बात पर सहमति बनी। (पेज-12)

सरकार की प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि व ग्रामीण विकास

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

मंत्रिपरिषद की बैठक

▸ ग्रामीण विकास, कृषि के साथ सड़क, रेल और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विजन डॉक्यूमेंट हुए पेश

▸ मंत्रियों के साथ आला अधिकारियों ने भी पीएम के सामने रखे अपने सुझाव

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जारी आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें ग्रामीण विकास, कृषि और बुनियादी क्षेत्र (इंफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़े मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के साथ उनकी योजनाओं की भावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में इन क्षेत्रों को विश्वस्तरीय बनाने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार के लिए कृषि व ग्रामीण विकास के साथ बुनियादी ढांचा क्षेत्र उच्च प्राथमिकता वाला है।

सूत्रों के मुताबिक, कृषि, ग्रामीण विकास और उससे जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के पहले समूह पर चर्चा के बाद दूसरा समूह इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों का था। दोनों समूहों का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। इस दौरान संबद्ध मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के बाद योजनाओं के अमल को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

केंद्र की सत्ता में दोबारा लौटने के बाद मोदी मंत्रिपरिषद की यह दूसरी बैठक थी। 13 जून, 2019 को हुई पहली बैठक में ही मोदी ने अगली बैठक में सभी मंत्रालयों को प्रमुख योजनाओं पर अमल के साथ 2022 और 2024 के विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने को कहा था। वैसे तो कैबिनेट बैठक हर हफ्ते होती है, जबकि मंत्रिपरिषद हर तीसरे माह में बैठती रही है, लेकिन मंत्रिपरिषद की यह बैठक छह माह बाद हुई है। देश में 14 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं, जिनकी दशा में सुधार लाने के साथ उनकी आमदनी दोगुना करने के उपायों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है।

सूत्रों के मुताबिक, आज की बैठक में कृषि क्षेत्र की योजनाओं को एक-एक कर प्रस्तुत करने के साथ बैठक में शामिल लोगों की राय मांगी गई। इसमें सभी लोगों ने बढ़कर अपने सुझाव भी दिए। कृषि में हर खेत तक पानी पहुंचाने वाली सूक्ष्म सिंचाई योजना,मिट्टी की जांच, उच्च प्रजाति के बीज, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, गुणवत्ता वाले कीटनाशक और उपज के लिए उचित बाजार मुहैया कराने की योजनाओं पर हुए क्रियान्वयन का ब्योरा देने के साथ भविष्य की खेती पर प्रस्तुति दी गई। मांग आधारित खेती और कृषि उपज के निर्यात पर विशेष जोर दिया गया। गांव के लोगों की सामाजिक व आर्थिक दशा में सुधार के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।

गांवों को चौतरफा पक्की सड़कों से जोड़ने के अलावा मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात भी कही गई। पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता को आगे बढ़ाने पर सरकार की ओर से प्रतिबद्धता जाहिर की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबद्ध मंत्रालयों के समूह के प्रजेंटेशन में ग्रामीण सड़कों के साथ हाईवे के निर्माण को प्रमुखता देने की बात कही गई। गुणवत्ता युक्त सड़कें बनाने को लेकर कई सुझाव आए। देश में रेल यातायात सुगम बनाने से लेकर उसकी सुरक्षा व संरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। देश में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को लेकर नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाने की बात कही गई। ज्ञात हो, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। सूत्रों का कहना है कि यह राशि किन परियोजनाओं पर खर्च की जानी है इनकी पहचान भी होनी बाकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो

चलेगा अभियान

तीन करोड़ परिवारों से किया जाएगा संपर्क, पार्टी 10 दिनों तक चलाएगी विशेष अभियान, हर जिले में रैली और करीब 250 पत्रकार वार्ताएं करेगी

सीएए पर विपक्ष का झूठ बेनकाब करेगी भाजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर विपक्ष और मुख्यतः कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। पार्टी विपक्ष की भ्रम और झूठ की राजनीति का जवाब देने के लिए 10 दिनों का विशेष अभियान चलाएगी और तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेगी। इस कानून के पक्ष में हर जिले में रैली और सभा की जाएंगी। 250 से ज्यादा स्थानों पर पार्टी पत्रकार वार्ता भी करेगी।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शनिवार को इस संबंध में एक बैठक हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्यों से संगठन के कुछ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा, 'नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्ष और मुख्यतः कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और वह पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। विपक्ष द्वारा जो भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है, उसका हम जवाब देंगे।' उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2003 में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की अपील की थी? क्या कांग्रेस देश में आगजनी और उपद्रव का समर्थन करती है? क्या एक प्रमुख विपक्षी दल इस विषय पर भारत के बाहर दूतावास पर प्रदर्शन करता है, क्या वह इस नीति को उचित मानते हैं?'

यादव ने कहा कि भाजपा का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए अनेक लोगों को नई आशा, विश्वास, सुरक्षा, आस्था, गरिमापूर्ण जीवन देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्टी अपने विशेष अभियान में उन लोगों को भी शामिल करेगी जो संशोधित कानून से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस मसले पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों से समर्थन पत्र भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि जब वह सत्ता में थी तो गुजरात और राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में जवाब मांगेगी।

कानून के समर्थन में उतरे 11 सौ बुद्धिजीवी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे है, वहीं देश के करीब 11 सौ बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने एक साथ आकर सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। इन सभी ने सामूहिक बयान जारी कर कहा कि यह कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आए शरणार्थियों की सालों पुरानी मांग को पूरा करने वाला है। इससे उन्हें नागरिकता आसानी से मिल सकेगी। बुद्धिजीवियों ने कानून के खिलाफ हिंसा करने वालों पर नाखुशी भी जताई है।

बुद्धिजीवियों ने कहा है कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते की असफलता के बाद कांग्रेस, माकपा जैसे राजनीतिक दलों ने भी इन्हें नागरिकता देने की वकालत की थी। उन्होंने इस कानून को लाने के लिए मौजूदा मोदी सरकार और भारतीय संसद दोनों को ही धन्यवाद दिया है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि यह कानून पूरी तरह से संविधान सम्मत है। बुद्धिजीवियों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों सहित समाज के दूसरे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे किसी के बहकावे में न आएं। इन बुद्धिजीवियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रकाश सिंह, जेएनयू के प्रोफेसर ऐनुल हसन, आइआइएम शिलांग के शिशिर बाजोरिया, नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनयना सिंह, सोनीपत महिला विवि की कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव, जेएनयू के प्रोफेसर मजहर आसिफ व डॉ. प्रमोद कुमार, लेखक अनिर्बान गांगुली, बीएचयू के प्रोफेसर कौशल किशोर, हार्वर्ड विवि के भानु प्रसाद आदि शामिल हैं।

हैदराबाद मुठभेड़ में आरोपितों के शवों का फिर होगा पोस्टमार्टम

▸ एम्स निदेशक से किया जाएगा मेडिकल टीम बनाने का अनुरोध

▸ हाई कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षित रखे गए हैं आरोपितों के शव

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना हाई कोर्ट ने महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या करने के चारों आरोपितों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। पुलिस ने छह दिसंबर को चारों आरोपितों को मुठभेड़ में मार गिराया था। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसे फर्जी मुठभेड़ बताया था। इस पर कोर्ट ने चारों आरोपितों के शवों को गांधी अस्पताल में सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी ने तेलंगाना के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे एम्स (दिल्ली) के निदेशक से मेडिकल टीम बनाने का अनुरोध करें, जिसमें तीन फोरेंसिक विशेषज्ञ होंगे। यही टीम दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर से पहले पोस्टमार्टम करा लेने को कहा है। इसकी रिपोर्ट कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने को कहा गया है। डॉक्टरों को उनके द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने की सलाह भी दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद चारों आरोपितों के शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा सकता है। हाई कोर्ट ने मुठभेड़ की जांच के लिए गठित एसआइटी प्रमुख को मामले से संबंधित सभी वस्तुओं मसलन केस डायरी, पुलिस अधिकारियों की गतिविधि का रजिस्टर, एनकाउंटर में प्रयुक्त हथियार आदि सीज कर लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग द्वारा मांगे जाने पर यह उनके सामने पेश किया जाएगा।

डॉक्टरों के आने-जाने और ठहरने का इंतजाम करेगी राज्य सरकार पेज>>3

10 निगम स्कूलों में क्रेच-कम-डे-केयर सेंटर की शुरुआत की गई उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से। इसकी शुरुआत उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली के महापौर अवतार सिंह मौजूद थे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 22 दिसंबर 2019

जनवरी से एयरपोर्ट की निर्माण प्रक्रिया में आएगी और तेजी

बैठक ▸ जेवर में बनने वाले नोएडा एयरपोर्ट को लेकर प्राधिकरण और प्रशासन की ओर अब तक की कार्रवाई से यमुना प्राधिकरण बोर्ड संतुष्ट

स्विस कंपनी ज्यूरिख को दिया गया है एयरपोर्ट के निर्माण का टेंडर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

यमुना प्राधिकरण की शनिवार को बोर्ड बैठक हुई। जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के संबंध में प्राधिकरण और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराया। प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से जरूरी जमीन मिल चुकी है। शेष जमीन लेने के लिए जिला प्रशासन प्रभावी कदम उठा रहा है। स्विस कंपनी ज्यूरिख को एयरपोर्ट के निर्माण का टेंडर दिया गया है। कंपनी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। सिर्फ पर्यावरण संबंधी स्थाई अनापत्ति मिलना बाकी है।

पांच जनवरी के बाद यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में और तेजी आ जाएगी। प्रदेश सरकार को भी इससे अवगत करा दिया गया है। प्राधिकरण स्तर से एयरपोर्ट के शिलान्यास की सभी तैयारी पूरी है। केंद्र और प्रदेश सरकार से शिलान्यास के लिए तिथि के लिए हरी झंडी मिलते ही युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की समस्याओं के निस्तारित की जानकारी भी बोर्ड सदस्यों को दी गई। बोर्ड सदस्यों ने प्राधिकरण द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर संतुष्टि जाहिर की।

प्राधिकरण ने बैंकों का कर्ज किया कम : यमुना प्राधिकरण पर तीन वर्ष पहले 4580 करोड़ रुपये का कर्ज था। प्राधिकरण ने सभी श्रेणियों के भूखंड आवंटियों से वसूली कर कर्ज को कम किया। प्राधिकरण पर अब 2402 करोड़ रुपये का कर्ज रह गया है। बोर्ड सदस्यों ने बकाया वसूली के लिए सीईओ समेत संबंधित अधिकारियों की प्रसंशा की।

किसानों के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए खुलेगी आइटीआइ : जिन किसानों की प्राधिकरण ने जमीन ली है, उनके बच्चों को रोजगार के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए एक हेक्टेयर भूमि पर निलौनी शाहपुर गांव में कौशल विकास केंद्र का निर्माण होगा। प्राधिकरण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग को निःशुल्क जमीन आवंटित करने का फैसला किया। निर्माण खर्च और संचालन विभाग ही करेगा।

अब गोशाला का संचालन करेगा प्राधिकरण : जेवर बांगर और फलैंदा बांगर गांव में बेसहारा गोवंश के लिए गोशाला संचालित हो रही है। इनका संचालन अब प्राधिकरण करेगा। दोनों के निर्माण पर करीब चार करोड़ 64 लाख 75 हजार रुपये खर्च होंगे।

एचडीएफसी बैंक को देना होगा आवंटी पर लगा जुर्माना : प्राधिकरण के एक आवंटी ने एचडीएफसी बैंक में भूखंड की किश्त का ड्राफ्ट जमा कराया था। बैंक ने ड्राफ्ट खो दिया। इससे आवंटी को फिर से ड्राफ्ट बनवाकर जमा करना पड़ा। इससे देरी होने पर आवंटी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लग गया। चूंकि आवंटी की गलती नहीं थी, इसलिए यह जुर्माना एचडीएफसी बैंक को अदा करना होगा।

आवंटियों की रजिस्ट्री के स्टांप शुल्क का आधा पैसा देगा प्राधिकरण : प्राधिकरण ने सेक्टर-20 के आइ और जे ब्लाक के करीब ढाई हजार भूखंड सेक्टर-18 में स्थानांतरित किए थे। स्थानांतरण के आदेश से पहले आवंटी भूखंड की रजिस्ट्री करा चुके थे। सेक्टर बदल जाने की वजह से उनके द्वारा पूर्व में कराई गई रजिस्ट्री के स्टांप पेपर बेकार हो गए। उन्हें अब फिर से रजिस्ट्री करानी पड़ रही है। इस पर अलग से स्टांप पेपर का शुल्क देना होगा। प्राधिकरण बोर्ड ने स्टांप शुल्क का आधा पैसा प्राधिकरण को देने के निर्देश दिए, जबकि स्टांप शुल्क का आधा पैसा आवंटी खुद वहन करेंगे।

फ्लैट योजना के आवंटी ले सकते हैं पैसा वापस : कुछ समय पहले यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 22 डी में बीएचएस-4 व 5 योजना निकाली थी। इनके सफल आवंटियों को अभी तक फ्लैटों पर कब्जा नहीं दिया जा सका है। योजना में 697 में आवंटी है। आवंटियों को पैसा वापस लेने अथवा दूसरी जगह फ्लैट लेने का विकल्प दिया गया है। वहीं सेक्टर 22 डी के आरपीएस 2009 योजना के आवंटी 30 जून 2020 तक बिना विलंब शुल्क के फ्लैटों की रजिस्ट्री करा सकते हैं। बोर्ड ने उन्हें राहत देने का फैसला किया है।

प्लेसमेंट पर नहीं रखें जाएंगे कर्मी : प्राधिकरण बोर्ड ने माना कि प्लेसमेंट पर कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों में कार्य करने की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इसलिए अब प्राधिकरण प्लेसमेंट पर कर्मचारी व अधिकारी नहीं रखे जाएंगे। शासन द्वारा सीधी भर्ती से ही कर्मचारी रखे जाएंगे।

बोर्ड ने कई विकास योजनाओं को दी हरी झंडी

जासं, ग्रेटर नोएडा : यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने जेवर एयरपोर्ट के मद्देनजर एक्सप्रेस वे के समीप विकास योजनाएं निकालने को हरी झंडी दे दी है। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही प्राधिकरण अब इन योजनाओं को निकालना शुरू कर देगा। इनमें अपैरल एक्सपोर्ट कलस्टर, हस्तशिल्प पार्क व लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग पार्क शामिल है।

लघु उद्योग पार्क सेक्टर-29 में 300 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। पार्क में 500 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहर में करीब 150 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा और 60 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए शीघ्र योजना निकाली जाएगी। इकाई स्थापित करने के इच्छुक लोगों को योजना में आवेदन करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। भूखंडों की संख्या से अधिक आवेदक आने पर ड्रा निकालकर आवंटन किया जाएगा। इसी तरह हस्तशिल्प पार्क में छोटी-बड़ी 250 से 300 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनसे करीब तीन हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा और 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। योजना निकालकर इन्हें भी आवेदन करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। हस्तशिल्प पार्क में भी भूखंडों का आवंटन लाटरी निकालकर किया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर अभी नहीं बढ़ेंगी टोल दरें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▸ प्राधिकरण लगवाएगा अब ग्रेटर नोएडा से आगरा तक स्ट्रीट लाइट

▸ टोल दरों से प्राप्त धन में से प्रतिमाह ली जाएगी 25 फीसद राशि

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बने 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे पर फिलहाल टोल दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने फैसला किया कि एक्सप्रेस-वे पर पहले वाहन यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके बाद टोल दरें बढ़ाने पर निर्णय होगा। बोर्ड ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने एक्सप्रेस-वे पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक स्ट्रीट लाइट लगाने के आदेश दिए थे। जेपी ने इस पर अमल नहीं किया। यह कार्य अब यमुना प्राधिकरण करेगा। जेपी के साथ बैंक में एस्क्रो अकाउंट खोला जाएगा। टोल दरों से जेपी को मिलने वाली धनराशि में से 25 फीसद धनराशि एस्क्रो अकाउंट में जमा होगी। इससे प्राधिकरण एक्सप्रेस-वे पर स्ट्रीट लाइट लगवाने के साथ अन्य रखरखाव पर खर्च करेगा। जेपी को टोल दरों से प्रतिमाह करीब 28 से 30 करोड़ रुपये मिलते हैं।

बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर हादसों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जेपी को दिए थे। आइआइटी दिल्ली ने भी एक्सप्रेस-वे पर हादसे रोकने के लिए अहम सुझाव दिए थे। दोनों पर ही जेपी ने अमल नहीं किया। बोर्ड ने निर्णय लिया कि हर हाल में एक्सप्रेस-वे पर हादसे रोके जाएं। लोगों का जीवन सबसे जरूरी है। एक्सप्रेस-वे पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए, जिससे सड़क हादसे में एक भी व्यक्ति की जान न जाए। बोर्ड ने सख्त लहजे में कहा कि अब समय आ गया है कि यदि एक्सप्रेस-वे पर जेपी सुरक्षा के इंतजाम न करें तो प्राधिकरण स्वयं जिम्मेदारी ले। निर्णय लिया गया कि टोल दरों से प्राप्त धनराशि में से 25 फीसद हिस्सा प्रतिमाह एक्सप्रेस-वे रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। यह धनराशि एस्क्रो अकाउंट में जमा होगी। इसे यमुना प्राधिकरण अपने स्तर से खर्च करेगा। सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि जेपी ने एस्क्रो अकाउंट खोलने और टोल दरों से मिलने वाली धनराशि में से 25 फीसद हिस्सा प्राधिकरण को नहीं दिया तो जेपी से संचालन का अधिकार छीन लिया जाएगा। 2003 में जेपी के साथ हुए समझौते को भी रद कर दिया जाएगा।

रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन

वीके शुक्ला, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कर दिया है। बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए बनाए गए रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के फैसले से जो लोग सहमत नहीं होंगे, वे यहां अपनी अपील डाल सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। यह न्यायाधिकरण दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों केंद्र शासित राज्यों के लिए काम करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के नाम पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुहर लगा दी है। उपराज्यपाल की अनुमति के बाद दिल्ली सरकार के भूमि एवं विकास विभाग ने न्यायाधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति का कार्यकाल पांच साल का होगा।

बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में 14 नवंबर 2018 को रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का गठन किया गया था। तब से बिल्डर सरकार के नियम-कानून मानने को बाध्य हैं। रेरा में प्रावधान किया गया है कि यदि बिल्डर ने निवेशकों के साथ ठगी की तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है। जिस प्रोजक्ट के लिए बिल्डर निवेशकों से पैसा लेगा, उसे उसी प्रोजक्ट पर ही खर्च करेगा। इसके लिए उसे अलग से खाता खुलवाना होगा। बिल्डर का पैसा खाते से तभी जारी होगा, जब अथॉरिटी स्वीकृति देगी। बिल्डर को यह भी जानकारी अथॉरिटी को देनी होगी कि किस-किस प्रॉपर्टी डीलर को उसने फ्लैट बेचने के लिए अधिकृत किया है। बता दें कि डीडीए द्वारा लाई जा रही लैंड पूलिंग पॉलिसी के पूरी तरह लागू हो जाने पर दिल्ली में बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि बिल्डरों को बड़े स्तर पर फ्लैट बनाने का मौका मिल गया है।

न्यूज गैलरी

अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर गुमराह कर रही है सरकार

नई दिल्ली : कांग्रेस ने रामलीला मैदान में रविवार को होने वाली पीएम की रैली को जनता को गुमराह करने वाला बताया है। पार्टी कहना है कि अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को मालिकाना हक देने के नाम पर उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि इन्हें नियमित करने की योजना मनमोहन सिंह सरकार में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री रहे अजय माकन ने बनाई थी। इसके लिए आसान शर्तें तय की गई थीं, जिन्हें मोदी सरकार ने बदलकर लोगों के साथ धोखा किया है। वह प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। माकन ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर सात सवाल उठाते हुए केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जवाब मांगा। (जासं)

सीसीटीवी कैमरे लगे घरों को मिलेगी 50 यूनिट की छूट

नई दिल्ली : दिल्ली कैंट से विधायक और एनडीएमसी के सदस्य सुरेंद्र कमांडो ने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की काउंसिल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में काफी लोगों को राहत देने का फैसला लिया गया। इसमें सबसे प्रमुख फैसला उन लोगों के लिए लिया गया है जिनके घर से सीसीटीवी कैमरों से बिजली उत्पन्न कराई जा रही है उनको 50 यूनिट प्रति माह की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही हर झुग्गी को बिजली का कनेक्शन और धोबी घाट पर पानी का कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। (जासं)

अब निगम जारी कर सकेंगे लघु उद्योग के लाइसेंस

नई दिल्ली : दिल्ली में रिहायशी इलाकों में लघु उद्योग चलाने वाले लाखों लोगों को राहत देते हुए केंद्र के आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में हुए मास्टर प्लान-2021 के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगम और एनडीएमसी के रिहायशी इलाकों में लघु उद्योग करने वाले लोगों को निगम दिल्ली सरकार की बिना मंजूरी के लाइसेंस जारी कर सकेंगे, जबकि पहले दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना पड़ता था, लेकिन, मास्टर प्लान-2021 में संशोधन के बाद अब यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। (जासं)

विरोधी भी मानते हैं, सरकार अच्छी चली : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी के लिए जुटी आम आदमी पार्टी ने शनिवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर से आए सदस्यों को आश्वस्त किया कि हम मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अपने आवास पर आयोजित बैठक में केजरीवाल ने कहा कि पांच साल बाद आज विरोधी भी मानते हैं कि हमने अच्छी सरकार चलाई है। अन्य पार्टियों ने 70 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब पार्टियां आंदोलन से बनीं, तब-तब कुछ सालों के बाद वह पार्टियां अपने निकम्मेपन की वजह से कुछ नहीं कर पाईं। वह आपसी झगड़े की वजह से कुछ सालों में खत्म हो गईं। 1977 और असम का उदाहरण हमारे सामने है। जब हमारी पार्टी बनी थी तब लोगों को लगता था कि यह भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया। वह आंदोलन काफी बड़ा हुआ। इसके बाद हम लोगों ने पार्टी बनाई। विरोधी दलों की उम्मीदों के विपरीत हमें भारी सफलता मिली। जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया और विश्वास किया। इसकी बदौलत बहुत बड़ा बहुमत मिला। इसके बाद का सफर ज्यादा मुश्किल था। विपक्षी कह रहे थे कि अक्सर सत्ता में आने के बाद अहंकार आ जाता है। नए लोगों को सरकार चलानी नहीं आती। लेकिन आज पांच साल के बाद हमारे विरोधी भी मानते हैं कि हमने सरकार बहुत अच्छी चलाई।

उन्होंने कहा कि सत्तर साल में कोई भी विरोधी हमारे जैसा काम नहीं कर पाया। कोई नहीं कह सकता है कि उसने स्कूल अच्छा कर दिया है, इसलिए हमें वोट दो। कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो यह कहे कि हमने अस्पताल ठीक कर दिए, हमें वोट दो। हमने सड़कें बनवा दीं, पानी दे दिया है हमें वोट दे दो। हमारी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, जो धर्म-जाति की बजाय अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। अब हमें काम गिनाने नहीं पड़ रहे हैं। हमारी जनता हमारे बीच खुद आकर काम गिना रही है।

अब दिल्ली के चुनाव को एक से डेढ़ महीना रह गया है। दिल्ली हमारी पार्टी का आधार है। यहीं से हम लोगों ने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। यहां पर हमें बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ना है। हमारा लक्ष्य भी काफी बड़ा है। पिछली बार हमने 70 में से 67 जीती थीं तो इस बार हमें 67 से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा सीटें हमारी आनी चाहिए।

पूरी दुनिया में हो रही दिल्ली के काम की चर्चा : राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को बदला है। पहले हम अमेरिका से सीखते थे, आज अमेरिका और कई अन्य देश हमारे मोहल्ला क्लीनिक से सीख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ काम पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। आज पूरी दुनिया में दिल्ली सरकार के काम की चर्चा हो रही है।

आप को इस बार भी मिल रहा वकीलों का साथ : सीएम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वकीलों की मदद से ही वह 70 में 67 सीटें जीतने में सफल हुए थे। इस बार भी वकीलों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पांच साल पहले अधिवक्ताओं से किए गए वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री शनिवार को वकीलों की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2015 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तब से दिल्ली के वकील उनके साथ हैं। वकील एसोसिएशन उनके साथ लगातार संपर्क में रही हैं और तमाम मुद्दों व समस्याओं पर उनके साथ चर्चा भी होती रही है। यही नहीं सरकार बनने से पूर्व से उन्हें अधिवक्ताओं का सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच साल बाद उन्हें यह कहते हुए खुशी है कि आप ने जितने वादे किए थे, उनसे दो-चार अधिक ही पूरे किए है, कमी नहीं छोड़ी। वकीलों की कई एसोसिएशन ने वेलफेयर के लिए अलग-अलग बजट की मांग की थी। इसके बाद तय हुआ कि 50 करोड़ रुपये अलॉट कर दिया जाए, तो सारी मांगें पूरी हो सकती हैं, इसकी भी सरकार ने स्वीकृति दी है।

रामलीला मैदान में पीएम की रैली आज, तैयारी पूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा की रैली के लिए तैयार रामलीला मैदान का मंच। जागरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को उनके मकान व भूखंड का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। इसके लिए रैली में 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर की हुई प्रति भेंटकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया जाएगा।

रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा नेता पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं। अलग-अलग स्थानों विशेषकर अनधिकृत कॉलोनियों में नुक्कड़ सभाएं, पदयात्रा व अन्य कार्यक्रम आयोजित करके लोगों से रैली में पहुंचने की अपील की जा रही थी। शनिवार को भी पूरे दिन नेता तैयारी में व्यस्त रहे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य नेताओं ने तैयारियों की समीक्षा की। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य भाजपा नेताओं कटआउट लगाए गए हैं।

आसपास के इलाके को भी मोदी की तस्वीर वाले कटआउट और भाजपा के झंडों से सजाया गया है। रैली के लिए 80 फीट चौड़ा भव्य मंच तैयार किया गया है, जिस पर तीस नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। मंच पर दो एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही पंडाल में आठ और रामलीला मैदान के बाहर चार एलईडी स्क्रीन लगाने की तैयारी है ताकि लोग आसानी से प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं का भाषण सुन सकें।

प्रधानमंत्री के साथ मंच पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री व दिल्ली के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर, सह प्रभारी हरदीप सिंह पुरी व नित्यानंद राय, दिल्ली भाजपा के प्रभारी श्याम जाजू व सहप्रभारी तरुण चुघ, दिल्ली के सभी सांसद, राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंत्री आरपी सिंह व महेश गिरी, मिजोरम के प्रभारी पवन शर्मा, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मंच संचालन की भूमिका निभाएंगे। भाजपा के सभी मोर्चों के साथ ही मंडल अध्यक्षों को अपने क्षेत्र से लोगों को रैली में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए लगभग 35 सौ बसों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में जगह-जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रविवार को रामलीला मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। मान सिंह रोड स्थित नए पुलिस मुख्यालय में कई दिनों से सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी। रामलीला मैदान के अंदर व बाहर करीब 5000 से अधिक दिल्ली पुलिस व पैरा मिलिट्री की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के लिए चारों तरफ जगह-जगह मचान व मोर्चा बनाए गए हैं। रामलीला मैदान के चारों तरफ की ऊंची इमारतों पर भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।

सरकारी स्कूलों बच्चों को मिलेगा टिफिन बंद खाना

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली : राजधानी के सरकारी स्कूलों के 75 हजार विद्यार्थियों को अक्षय पात्र संस्था अगले साल से मिड-डे मील के रूप में टिफिन बंद खाना खिलाएगी। संस्था पिछले चार सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को खाना खिलाने की दिशा में प्रयास कर रही थी। लेकिन किसी न किसी वजह से अनुबंध उनको मिलने में समय लग गया।

अक्षय पात्र के रीजनल प्रसिडेंट भरतार्शभा दास ने बताया कि इसके लिए अक्षय पात्रा ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 75 हजार बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए तीन किचन भी बनकर तैयार हैं। ये किचन ओखला स्थित मोहन एस्टेट, जहांगीरपुरी और समयपुर बादली में बनाए गए हैं। इनमें ओखला स्थित किचन से 22 हजार बच्चों के लिए खाना बनेगा। बाकि बच्चों के लिए खाना अन्य दोनों किचन में तैयार होगा। 24 दिसंबर को ओखला स्थित किचन का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे।

आश्रम फ्लाईओवर विस्तार योजना का शिलान्यास 24 को

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार वर्षों से लंबित आश्रम फ्लाईओवर विस्तार व अंडरपास योजना पर काम शुरू करने जा रही है। 24 दिसंबर को इन दोनों योजनाओं का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिलान्यास करेंगे।

आश्रम फ्लाईओवर विस्तार योजना को लेकर पिछले 30 साल से मांग की जा रही थी। नोएडा व सराय काले खां की ओर से दक्षिणी दिल्ली की ओर आने-जाने के लिए रिंग रोड पर रोजाना सुबह व शाम को किलोकरी गांव के पास लोग घंटों जाम में फंसते हैं। इस योजना के पूरा होने पर नोएडा व गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली के अन्य हिस्सों से दक्षिणी दिल्ली आना-जाना आसान हो जाएगा। इसके तहत रिंग रोड पर आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाई-वे तक विस्तार दिया जाएगा। यह छह लेन का होगा। तीन लेन आश्रम से डीएनडी जाने के लिए व तीन लेन डीएनडी से आश्रम आने के लिए होंगी। साथ ही आश्रम फ्लाईओवर से सराय कालेखां जाने के लिए तीन लेन के डाउन रैंप का निर्माण होगा। इसके अलावा आइटीओ व सराय कालेखां से साउथ दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए तीन लेन का अप रैंप डीएनडी लूप से इस फ्लाईओवर के लिए बनेगा। इस योजना पर कुल 128.95 करोड़ रुपये की लागत आएगी। निर्माण शुरू होने पर यह कार्य एक साल में पूरा कर लिया जाएगा।

आश्रम अंडरपास योजना पर 78 करोड़ रुपये होंगे खर्च : अंडरपास के निर्माण पर करीब 78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस चौक से रोजाना 4.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। अंडरपास बनने के बाद निजामुद्दीन से बदरपुर आना-जाना आसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग निजामुद्दीन की ओर से आ रहे हैं और मूलचंद या एम्स की ओर जाना है, उन्हें ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा। इस अंडरपास के लिए पिछले दस साल से प्रयास चल रहे थे।

दिल्ली को हिमाचल प्रदेश देगा अतिरिक्त पानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अपने हिस्से का अतिरिक्त पानी देगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश व दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। दिल्ली की प्रधान सचिव मनीषा सक्सेना (शहरी विकास) व हिमाचल प्रदेश के सचिव डॉ. आरएन बत्ता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निखिल कुमार व तकनीकी सदस्य (जल) शलभ कुमार मौजूद थे।

समझौते के अनुसार, हिमाचल प्रदेश नवंबर से फरवरी के बीच दिल्ली को प्रतिदिन 368 क्यूसेक व मार्च से जून के बीच 268 क्यूसेक पानी देगा। जल बोर्ड के अधिकारियों को उम्मीद है कि मार्च से अतिरिक्त पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश से मिलने वाले पानी को लाने और उसके स्टोरेज के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह कार्य पूरा होने पर पानी की आपूर्ति बढ़ेगी और पूरे साल 421 क्यूसेक पानी प्रतिदिन मिलेगा।

मौसम की मार

आने वाले दिनों में घने कोहरे का है अनुमान, धूपी निकलेगी देरी से और होगा ठिठुरन का अहसास

दिल्ली-एनसीआर में आज से और परेशान करेगा कोहरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को घने कोहरे से परेशान रहे लोगों की समस्या रविवार को और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 25 दिसंबर के बीच घना कोहरा आने का अनुमान है। इससे धूप भी देरी से निकलेगी, जिससे लोगों को ठिठुरन का अहसास होगा। वहीं 25 दिसंबर के बाद पारा एक बार फिर तेजी से नीचे गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है।

पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच शनिवार को लोगों को आंशिक राहत मिली। धूप खिलने की वजह से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में भी मामूली सुधार हुआ है। हालांकि कोहरे की वजह से बीते दो दिन की तरह शनिवार को भी दिल्ली में पालम केंद्र पर दृश्यता 50 मीटर रही। वहीं सफदरजंग में सुबह आठ बजे तक 200 मीटर तक दृश्यता दर्ज की गई।

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी की मात्रा 69-100 फीसद के बीच रही। अधिकतम तापमान शुक्रवार के मुकाबले एक डिग्री तो न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक दर्ज किया गया।

दिल्ली-एसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स

स्थान	इंडेक्स
दिल्ली	418
गाजियाबाद	454
फरीदाबाद	441
ग्रेटर नोएडा	467
नोएडा	474
गुरुग्राम	302

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शनिवार की सुबह छाए कोहरे के बीच से जाते वाहन चालक। जागरण

विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। सुबह के समय दृश्यता कोहरे की वजह से कम रहने की उम्मीद जताई गई है। उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवा का असर जारी रहेगा।

सुधर सकती है वायु की गुणवत्ता : दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हवा की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश की वजह से वायु प्रदूषण में मामूली सुधार देखा गया है। लेकिन अभी भी स्थित खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। हालांकि रविवार को वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार की उम्मीद है। शनिवार को दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 254 रहा। यह शुक्रवार से दो अंक अधिक था। शुक्रवार को पीएम 2.5 का स्तर 252 पर रहा था। रविवार को यह 241 पर जा सकता है।

शारीरिक संबंध के लिए किशोरी की सहमति के मायने नहीं : कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

▸ दुष्कर्म के समय 13 साल से कम थी पीड़िता की उम्र

किशोरी की सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि घटना के दौरान किशोरी की उम्र 13 साल से कम थी। कानून के हिसाब से इस उम्र में किशोरी की सहमति मायने नहीं रखती है। पीड़िता ने बयान में कहा कि दोषी राहुल मंडल उर्फ राहुल ने जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वह 13 साल से कम उम्र की थी। ऐसे में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा में कोई भी खामी नहीं है। हाई कोर्ट ने दोषी की याचिका को खारिज कर निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा।

निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा-386 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत दोषी राहुल को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना नहीं भरने पर आठ महीने तक कारावास की सजा का भी आदेश दिया था। दोषी ने हाई कोर्ट में इसे चुनौती देते हुए कहा था कि किशोरी की सहमति से शारीरिक संबंध बनाया था और उससे शादी की थी। यह सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मामला है न की दुष्कर्म करने का। याचिका के अनुसार 12 नवंबर 2013 को किशोरी द्वारका में दोषी राहुल से मिली थी। वहां से राहुल उसे पास की झुग्गी में ले गया, जहां उसके साथ एक सप्ताह रही। यहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। निचली अदालत ने राहुल को अपहरण के केस से मुक्त कर दिया, लेकिन दुष्कर्म के लिए दोषी करार दिया था।

1883 में ब्रिटिश सैनिकों के लिए दिल्ली के वर्तमान रामलीला मैदान में एक शिविर बनाया गया था। बाद में स्थानीय संस्थाएं इसमें रामलीला कराने लगी तभी से ये रामलीला मैदान हो गया। इन दिनों यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियां की जा रही हैं।

नहीं मान रहे महातिर, फिर की दखलअंदाजी

हिमाकत ▶ भारत की आपत्ति के बावजूद मलेशिया के पीएम का अंदाज उकसाने वाला

फिर की सीएए और कश्मीर पर टिप्पणी, जाकिर नाईक के साथ भी दिखे

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद की फाइल फोटो। एएफपी

इस्लामिक देशों के अगुआ बनने की धुन में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद भारत के साथ अपने देश के रिश्तों को तार-तार करने पर आमादा हैं। भारत की तरफ से पिछले दो दिनों में दो बार आपत्ति जताने के बावजूद मुहम्मद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को नई दिल्ली में मलेशिया के राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें भारत के गुस्से से अवगत कराया। हालात जिस तरह से बनते जा रहे हैं उसे देखते हुए भारत मलेशिया के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने से परहेज नहीं करेगा।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि मलेशिया के राजदूत को साफ शब्दों में बताया गया है कि महातिर की टिप्पणी किस तरह से अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के सामान्य मानकों के खिलाफ है। भारत मलेशिया को एक मित्र राष्ट्र मानता है और उम्मीद करता है कि वहां की सरकार हमारे आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत ने यह भी उम्मीद जताई है कि मलेशिया सरकार भारत के साथ आगे के रणनीतिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी। शुक्रवार को भी विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि जिस मुद्दे के बारे में पता नहीं हो उसके बारे में प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद को बोलना नहीं चाहिए।

मलेशिया के प्रधानमंत्री का अंदाज पूरी तरह से उकसाने वाला है। शनिवार को उन्होंने सीएए पर टिप्पणी तो की ही, साथ ही भारत से फरार धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले प्रचारक जाकिर नाईक के साथ भी दिखे। कुआलालंपुर में इस्लामिक देशों के प्रमुखों की बैठक में आयोजित एक समारोह में जाकिर नाईक भी आमंत्रित था। उसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और महातिर मुहम्मद से हाथ मिलाते और बात करते हुए देखा गया। सनद रहे कि भारत ने मलेशिया से नाईक को सौंपने की मांग की है।

सूत्रों का कहना है कि महातिर दरअसल अपने देश को इस्लामिक देशों के नए नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि वह लगातार भारत की नीतियों पर टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सितंबर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर टिप्पणी की। अब उन्होंने सीएए को भी अपने तरकश में शामिल कर लिया है। गुरुवार को राजधानी कुआलालंपुर में इस्लामिक देशों के एक समारोह को संबोधित करते हुए सीएए की आड़ में भारत की पंथनिरपेक्ष छवि पर निशाना साधा था। सितंबर में पाकिस्तान ने मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की थी। सूत्रों का कहना है कि उक्त तीनों देशों के साथ भारत का कोई ऐसा रणनीतिक या कारोबारी रिश्ता नहीं है जो उसके लंबे वैश्विक हितों पर विपरीत असर डाले। भारत ने जब से तुर्की के सबसे प्रबल विरोधी देशों साइप्रस व अर्मेनिया को तवज्जो देना शुरू किया है तब से उसके विरोधी स्वर शांत हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक अभी यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में भी मलेशिया का क्या रुख होता है। अगर उसके रुख में बदलाव नहीं आता है तो भारत दूसरे कठोर कदम उठा सकता है। महातिर मुहम्मद के लगातार इस तरह के बयान से दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। सितंबर में जब प्रधानमंत्री महातिर ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था तब भारत के कारोबारियों ने मलेशिया से पाम ऑयल आयात प्रतिबंधित करने की धमकी दी थी। मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीददार भारत है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मुहम्मद ने अपने राजनीतिक हितों के लिए भारत के साथ रिश्तों पर प्रहार कर ही दिया है। सनद रहे कि मई, 2018 में अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घंटे निकालकर मलेशिया की यात्रा की और कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री पद संभालने वाले महातिर मुहम्मद को बधाई दी थी।

परंपरागत की जगह युद्ध के नए तरीके पैदा कर रहा नई चुनौती

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय सेना के लिए युद्ध का बदलता स्वरूप बड़ी चिंता बनकर उभरा है। परंपरागत युद्ध की जगह तकनीकी युद्ध का बढ़ता दायरा नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि तकनीक में तेजी हो रहे बदलाव से युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। अब जल, थल, नभ से परे भी युद्ध का मैदान सजाया जा रहा है। डिजिटल वार खुद में हर देश के लिए बड़ी चुनौती है। आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस इस चुनौती को और बढ़ा रहा है। सेना प्रमुख ने यह बात शनिवार को आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार में कही।

जनरल रावत ने कहा, गैर परंपरागत युद्ध भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए देश भी तैयारी में जुट गया है। कार्यक्रम में मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सेनाओं के आमने-सामने हुए बगैर लड़े जाने वाले युद्ध के बारे में बताया। कहा कि दुनिया की महाशक्तियां इसके लिए व्यापक तैयारियों में जुटी हुई हैं। ये महाशक्तियां अब गैर परंपरागत तरीके से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इसमें परंपरागत रूप से हमला कर दूसरे की धरती पर जाने की जरूरत नहीं होगी। जनरल रावत के अवकाश ग्रहण करने के बाद नरवाने 31 दिसंबर को देश के थलसेना प्रमुख बन जाएंगे। सेमिनार में सेना की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी, नीति नियंता, शिक्षा एवं शोध से जुड़ी हस्तियां और उद्योगों से जुड़े लोग उपस्थित थे।

देश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़े शोध को लगेंगे पंख

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

- मिशन मोड में काम शुरू, सरकार पांच वर्षों में 12 हजार लोगों से कराएगी शोध
- 36 सौ करोड़ से ज्यादा खर्च का रखा गया लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष में मिले 124 करोड़

प्रतीकात्मक

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में भारत एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। सरकार ने इससे जुड़े शोध को बढ़ावा देने का काम मिशन मोड में शुरू किया है। इसके तहत आगामी पांच वर्षों में 12 हजार लोगों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें पीएचडी सहित इससे जुड़े अन्य शोध कार्य करने वाले शामिल होंगे। साथ ही इन पांच वर्षों में इस पर करीब 36 सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) को लेकर यह सारी कवायद प्रधानमंत्री की रुचि के बाद तेज हुई है। कई मौकों पर वह इसे बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। फिलहाल मौजूदा समय में देश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में शोध करने वालों लोगों की संख्या करीब 386 ही है, जबकि पूरी दुनिया में यह संख्या 22 हजार से ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं को देखते हुए अपनी मुहिम तेज की है। वह इस क्षेत्र में दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है।

सरकार इससे जुड़े शोध को लेकर अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई है। मिशन के पहले ही साल यानी चालू वित्त वर्ष 2019-20 में इसके लिए 124 करोड़ का बजट दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले दिनों इससे जुड़ी एक रिपोर्ट संसद को भी दी है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़े शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन को एनएम-आइसीपीएस (नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लीनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम) नाम दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इस क्षेत्र में हाथ बंटा रहा है।

विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के तहत शोध करने वालों को इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय भी सहायता दे रहा है। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लेकर शुरू किए गए मिशन के तहत बेहतर शोध करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल किया है। इसे लेकर देश में 25 इनोवेशन हब भी स्थापित किए हैं। जहां शोधार्थी गुणवत्तापूर्ण काम कर सकते हैं। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से रोबोट या उसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनें तैयार की जाती हैं।

रक्षा क्षेत्र में वायुसेना अहम भूमिका निभाना जारी रखेगी

हैदराबाद में डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड के मौके पर फ्लाइट कोर्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फ्लाइंग ब्रांच के फ्लाइंग अफसर अरुणाभ चक्रवर्ती को 'सॉर्ड ऑफ आनर' से सम्मानित करते वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया (दाएं)। एएनआइ

- स्थापना के बाद से इस बल ने निभाई हैं कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं : भदौरिया

हैदराबाद, प्रेट्र : वायुसेना ने इस बात पर जोर दिया है कि वह सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगी। स्थापना के बाद से इस बल ने कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह बात शनिवार को वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कही।

वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा कि मौजूदा दशक में युद्ध की पद्धतियों और स्वरूप में अहम बदलाव नजर आने की संभावना है। वायुसेना प्रमुख ने नजदीक के डुंडीगल स्थित एयरफोर्स एकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड के दौरान कहा, 'भारतीय वायुसेना रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगी और आप उन प्रमुख लोगों के समूह में शामिल होंगे जिनसे यह कर दिखाने को कहा जाएगा।'

उन्होंने भरोसा जताया कि सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले फ्लाइट कैडेट प्रत्येक कार्य को निपुणता से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, 'जब हम युद्ध के समूचे परिदृश्य में दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में हमें मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों तथा उभरने वाली किसी अन्य जरूरी भूमिका में भी राष्ट्र की सक्रियता से अवश्य मदद करनी चाहिए।' एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वायुसेना की फ्लाइंग एवं ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के 127 फ्लाइट कैडेट के प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर इस परेड का आयोजन किया गया था। इसमें कहा गया है वायुसेना में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 21 महिला अधिकारी भी इसमें शामिल हुई हैं।

गाजियाबाद की आरती तोमर बनीं कमीशंड अधिकारी

शनिवार को नए कमीशंड अधिकारियों में गाजियाबाद की आरती तोमर फ्लाइट ब्रांच से एकमात्र महिला हैं। उन्होंने कहा कि अपने परिवार से पहली रक्षा अधिकारी हैं। उन्होंने कहा, 'मैं रक्षा में फ्लाइंग ब्रांच में शामिल होने जा रही हूं। यह कठिन तो होगा, लेकिन रोमांचकारी भी होगा।' यह पूछा गया कि लड़ाकू शाखा जिसे महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण के रूप में देखा जाता है, उसमें शामिल होने की प्रेरणा कहां से मिली? उन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हर जिम्मेदारी कठिन होती है। जो लोग परिवहन जैसी शाखाओं में काम करते हैं वे भी कठिन परिश्रम करते हैं। लड़ाकू को कठिन माना जाता है, लेकिन जब आप सीखना शुरू करते हैं तो यह कठिन नहीं रह जाता है।

परेड के निरीक्षण के बाद भदौरिया ने अपना पेशेवर प्रशिक्षण पूरा करने वालों को स्नातक फ्लाइट कैडेट का राष्ट्रपति के कमीशन से नवाजा। सफल फ्लाइट कैडेट को एयरफोर्स अकादमी के कमांडेंट ने शपथ दिलाई। फ्लाइट कोर्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फ्लाइंग ब्रांच के फ्लाइंग अफसर अरुणाभ चक्रवर्ती को 'सॉर्ड ऑफ आनर' से सम्मानित किया गया और उन्हें राष्ट्रपति का फलक प्रदान किया गया।

किसानों का दो लाख तक कर्ज माफ करेगी उद्धव सरकार

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने किया एलान
- सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी कर्ज माफी की रकम

उद्धव ठाकरे फाइल फोटो

महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने किसानों को दो लाख तक की संपूर्ण कर्ज माफी देने की घोषणा की है। यह कर्ज माफी मार्च माह से दी जाएगी। राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही किसान कर्ज माफी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए दो लाख रुपये तक संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की। उनके अनुसार 30 सितंबर, 2019 तक के सभी कर्ज महात्मा फुले कर्ज माफी योजना के तहत माफ किए जाएंगे। करीब दो माह का समय इस कर्ज माफी की तैयारियों में लगेगा। इसलिए कर्ज माफी का लाभ किसानों को मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना में सीधे किसानों के खाते में कर्ज माफी की रकम भेजी जाएगी। इसके लिए किसानों को किसी बैंक या सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि, सरकार की इस घोषणा से विरोधी दल भाजपा संतुष्ट नहीं है। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने यह कहते हुए अपने विधायकों के साथ सदन का बहिष्कार किया कि चुनाव में शिवसेना ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। लेकिन, अब सरकार सिर्फ दो लाख तक कर्ज माफी की बात कर रही है। बता दें कि देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्ववाली पिछली सरकार ने भी किसानों के लिए 34,022 करोड़ की कर्जमाफी योजना शुरू की थी। इसके लिए करीब 80 लाख किसानों ने आवेदन किया था। लेकिन, उचित लाभार्थियों की पहचान में ही सरकार को काफी समय लग गया था। इस कारण कर्ज माफी की घोषणा के 18 महीनों बाद भी सरकार इस मद में निर्धारित राशि का आधा भी खर्च नहीं कर पाई थी।

मंडल स्तर पर स्थापित होंगे सीएम दफ्तर: **नागपुर, प्रेट्र** : उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरे राज्य में मंडल स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे लोगों को सरकारी काम के लिए मुंबई न आना पड़ेगा। ठाकरे ने इसे सरकार के विकेंद्रीकरण के प्रयास का हिस्सा बताया। उन्होंने शिव भोजन योजना का भी एलान किया। इसके तहत गरीबों को 10 रुपये में खाना मिलेगा।

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार फड़नवीस सरकार के कोष इस्तेमाल की हो जांच

मुंबई, एएनआइ : राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पूर्व की भाजपा की अगुआई वाली सरकार द्वारा कोष के दुरुपयोग की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने 2018 तक 66000 करोड़ के कोष के इस्तेमाल का प्रमाणपत्र नहीं सौंपा है।

महाराष्ट्र सरकार नागरिकता कानून और एनआरसी लागू न करे : पवार

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- लागू करने से बिगड़ सकता है देश का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी है कि वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) लागू नहीं करे। उन्होंने कहा, इसे लागू करने से देश का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा बिगड़ने की आशंका है।

पवार के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सीएए और एनआरसी का मुद्दा अन्य अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उछाला है। उन्होंने कहा, राकांपा ने लोकसभा एवं राज्यसभा में विधेयक का विरोध किया था। अब महाराष्ट्र सरकार को भी इसका विरोध करने वाले अन्य आठ राज्यों का रुख अपनाना चाहिए। पंजाब, राजस्थान, बंगाल समेत राजग शासित बिहार सरकार ने इस कानून को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। उद्धव ठाकरे ने गत रविवार को ही कहा था कि वह इसे लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।

राज ठाकरे के सुर भी पवार जैसे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी पवार के सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने कहा कि देश कोई धर्मशाला नहीं है, जहां कहीं से भी किसी को लाकर बसा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री पर व्यंग्य कसते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो 'खेल' किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान आर्थिक मंदी से दूसरी ओर मोड़ दिया है। राज के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन देशों से आनेवालों में हिंदू-मुसलमान के आधार पर भेद करने की जरूरत नहीं है। यह देखने की जरूरत है कि नेपाल के रास्ते कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भारत में आ रहे हैं।

खुफिया एजेंसियों की मदद से सफल होते हैं सैन्य अभियान

- जासूसी की असली दुनिया फिल्मी चरित्र जेम्स बांड जैसी नहीं : नरवाने
- पूर्व पत्रकार नितिन गोखले की पुस्तक के विमोचन अवसर पर कही यह बात

पुणे, प्रेट्र : कोई भी सैन्य अभियान खुफिया एजेंसियों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता है। जासूसी की दुनिया सिनेमा के चरित्र जेम्स बांड, बंदूक और लड़कियों जैसी नहीं है। यह बहुत कुछ जॉन ले कार के स्माइल उपन्यास जैसी होती है। यह बात वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एवं नामित थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवाने ने कही।

पूर्व पत्रकार नितिन गोखले की पुस्तक 'आरएन काव : भद्र जासूस' के विमोचन कार्यक्रम को लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने ने संबोधित किया। काव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पहले प्रमुख रहे थे।

लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने ने कहा, 'सैन्य अभियान और खुफिया सूचनाओं का आपस में करीबी संबंध है। जब कभी हमें संचालन ब्रीफिंग की जरूरत होती है तब यह हमेशा ही यह 'खबर दुश्मन के बारे में' के साथ शुरू होती है। 'खबर' वह होती है जो हम अपनी खुफिया एजेंसियों से प्राप्त करते हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा कोई भी सैन्य अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि इसे रॉ सहित विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सहायता नहीं मिली हो।'

लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने ने कहा कि जब जासूसी के बारे में सोचा जाता है तो आम तौर पर दिमाग में सिनेमा का चरित्र जेम्स बांड उभरता है, लेकिन यह वैसा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, 'जब हम खुफिया कार्य के बारे में सोचते या बातचीत करते हैं तो हम सामान्य रूप से जेम्स बांड, बंदूक, लड़कियां, गिटार और ग्लैमर के बारे में सोचते हैं, लेकिन गुप्तचरी की दुनिया वैसी नहीं है। गुप्तचरी की दुनिया बहुत कुछ जॉन ले कार के स्माइल उपन्यास जैसी है।'

ज्ञात हो, ब्रिटिश लेखक डेविड जॉन मूर कॉर्नवेल को उनके उपनाम जॉन ले कार के नाम से जाना जाता है। इसी नाम से उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखकर ख्याति अर्जित की थी। 1950 से 1960 के बीच उन्होंने सिक्यूरिटी सर्विस (एमआइ5) और सीक्रेट इंटेलीजेंस सर्विस (एमआइ6) के लिए काम किया था। उनके उपन्यास में उनके काम की झलक साफ रूप से दिखाई देती है।

डॉक्टरों के आने-जाने और ठहरने का इंतजाम करेगी राज्य सरकार

▶ प्रथम पृष्ठ का शेष

खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार एम्स के चिकित्सा दल की विमान यात्रा, उनके ठहरने और उनके लिए अन्य सारी सुविधाओं का इंतजाम करेगी, ताकि दल अपना काम बखूबी कर पाए। शुक्रवार को तेलंगाना के महाधिवक्ता ने कहा था कि इन चारों आरोपितों के शवों का उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया गया है। इसलिए फिर से पोस्टमार्टम के लिए आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। न्यायमित्र डी प्रकाश रेड्डी ने दलील दी थी कि दूसरे पोस्टमार्टम की जरूरत पर गौर करने के लिए ही उच्च न्यायालय के निर्देश पर शवों को सुरक्षित रखा गया है और उच्चतम न्यायालय भी इस पर मुहर लगा चुका है। उच्चतम न्यायालय ने चारों आरोपितों के मुठभेड़ में मारे जाने की परिस्थितियों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वीएस सरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग गठित किया था। बांबे हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा सोनदुर बालडोटा और सीबीआइ के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन उसके अन्य सदस्य हैं। आयोग को छह महीने के अंदर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट सौंपनी है।

उत्तराखंड की जेलों में कैदियों की संख्या घटाने को उठेंगे कदम

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- जेलों में लगातार बढ़ रही संख्या का गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान

देशभर की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की लगातार बढ़ती संख्या चिंता का सबब बनती जा रही है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों का पत्र लिखकर जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर गठित जिला विधिक सेवा समिति की बैठकें करने के साथ ही नियमानुसार कैदियों को रिहा करने अथवा बेल देने को कहा गया है।

उत्तराखंड की कुल 11 जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 3420 है। बावजूद इसके हालात यह हैं कि इन जेलों में तकरीबन 5400 कैदी बंद है। यह संख्या जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता से डेढ़ गुना ज्यादा है। इनमें भी सबसे अधिक कैदी हल्द्वानी और देहरादून जेल में बंद हैं। जेलों में बंद कैदियों में से विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक है। यानी ऐसे कैदी जिन पर अभी मुकदमें चल रहे हैं और फिलहाल फैसला नहीं आया है। शेष संख्या दोषसिद्ध कैदियों की है।

जेलों में कैदियों की भीड़ केंद्र सरकार की पेशानी पर भी बल डाले हुए है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस मसले को गंभीरता से लेने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश में गठित अंडर ट्रायल समितियों से अपने यहां विचाराधीन कैदियों के लंबित प्रकरणों के तेजी से निस्तारण का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे कैदियों के बारे में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, जो बेल बांड भरने में सक्षम नहीं है और इसी कारण जेलों में बंद हैं। केंद्र ने जिला विधिक सेवा समिति के सचिव से इस तरह के मामलों पर नजर रखने को कहां है, जिनमें दोषियों को जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक जिलों में गरीबों को विधिक सेवा उपलब्ध कराने को वकीलों का पैनल तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में पत्र प्राप्त हो गया है और अब इस दिशा में कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नाराजगी

पसंद की सीट नहीं मिलने पर प्रज्ञा विमान में ही धरने पर बैठीं

दिल्ली से भोपाल आते समय पहली पंक्ति में सीट नहीं मिलने से थीं नाराज, समय पर नहीं उतरने के कारण 20 मिनट की देरी से वापस दिल्ली रवाना हुआ विमान

नई दुनिया, भोपाल

स्पाइस जेट की दिल्ली उड़ान से भोपाल आ रहीं सांसद साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर को पसंद की सीट नहीं मिली तो वे विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गईं। एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुरोध पर वे करीब 20 मिनट बाद विमान से उतरीं। बाद में उन्होंने स्पाइस जेट प्रबंधन के खिलाफ सेवाओं में कमी की शिकायत दर्ज कराई।

जानकारी के अनुसार, साध्वी प्रज्ञा शनिवार शाम को दिल्ली से स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी 2489 से भोपाल आ रही थीं। विमान के अंदर उन्हें सीट नंबर 2-ए दी गई। सांसद चाहती थीं कि प्रोटोकाल के लिहाज से उन्हें सीट नंबर ए-1 दी जाए, लेकिन यह सीट पहले ही दूसरे यात्री को दी जा चुकी थी। शाम सात बजे विमान भोपाल में राजाभोज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भोपाल के सभी यात्री उतर गए, लेकिन साध्वी नहीं उतरीं। वे विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गईं। स्पाइस जेट के स्टाफ ने भी उनसे नीचे आने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं मानीं। बाद में एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम विमान के अंदर पहुंचे और सांसद से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद वे विमान से उतरीं। उनके विमान से समय पर नहीं उतरने के कारण यह विमान भोपाल से 20 मिनट की देरी से वापस दिल्ली रवाना हुआ।

पत्रकारों से कहा- मैंने धरना नहीं दिया

साध्वी प्रज्ञा एयरपोर्ट से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भगवानदास सबनानी के साथ संत हिरदारामजी की कुटिया पर पहुंचीं। यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्पाइस जेट की सेवाएं ठीक नहीं हैं। कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। मैंने जो सीट बुक कराई थी, वह नहीं दी गई। मैंने धरना नहीं दिया है, लेकिन सेवाओं में कमी की शिकायत दर्ज कराई है। साध्वी ने कहा कि स्पाइस जेट ने इसके पहले भी एक महिला राज्यपाल के आगमन के समय सही सेवा नहीं दी थी।

भोपाल में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भगवानदास सबनानी के साथ संत कुटिया जातीं साध्वी प्रज्ञा। नईदुनिया

कह के रहेंगे माधव जोशी

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 22 दिसंबर 2019

आज भर इंतजार, कल पता चलेगा जीत और हार

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

राज्य ब्यूरो, रांची

इनके भाग्य का होगा फैसला	
पुरुष	1,087
महिला	127
थर्ड जेंडर	01
निर्दलीय	366

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए पांच चरणों में हुए मतदान के बाद अब सोमवार को आने वाले नतीजे पर सभी की नजरें टिक गई हैं। मतगणना के साथ ही जनता की अदालत में 1,215 उम्मीदवारों के लिए हुए फैसले सामने आ जाएंगे। तय हो जाएगा कि किसके सिर पर ताज सजेगा और कौन कुर्सी से बेदखल होगा।

प्रदेश में 29,464 बूथों पर 41,870 ईवीएम में पड़े मतों की गणना के लिए कड़ी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सोमवार सुबह सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम से मतों की गणना होगी। हर राउंड में मतों की गिनती के बाद उसकी घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग व संबंधित जिला प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कर्मियों को पहले ही प्रशिक्षण दे दिया गया है। जिला मुख्यालयों में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में पड़े मतों की गणना लगभग 81 हॉल में पर्यवेक्षकों की देखरेख में होगी। कुछ सीटों पर दो हॉल भी हो सकते हैं।

मतगणना के लिए सभी चौबीस जिला मुख्यालयों में एक-एक काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों में कुल एक हजार से अधिक टेबलों पर मतों की गणना होगी, जबकि एआरओ के अलग से टेबल होंगे।

यहां बंद है प्रत्याशियों का भाग्य : दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को ईवीएम रखने के लिए बनाए गए वज्रगृह को सभी रजानीतिक दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में सील किया गया। इस दौरान दुमका के भाजपा प्रत्याशी लुईस मरांडी और झामुमो के प्रत्याशी हेमंत सोरेन मौके पर पहुंचे। यहां दोनों की मौजूदगी में वज्रगृह को सील किया गया। मौके पर एसडीओ राकेश कुमार, सामान्य प्रेक्षक अनिल भंडारी मौजूद थे। जागरण

रघुवर, हेमंत के सामने इतिहास बदलने की चुनौती

राज्य ब्यूरो, रांची

2009 में फेल हुए थे रघुवर, नतीजे बताएंगे इस बार पास होंगे या फेल

झारखंड विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद अब जीत-हार को लेकर कयासों का दौर चरम पर है। पलड़ा भाजपा का भारी रहेगा या यूपीए सत्ताधारी दल को झटका देने में कामयाब होगा, इसे लेकर हर कोई सशंकित है। विभिन्न टीवी चैनलों के एक्जिट पोल से भी स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है।

इतना तय है कि यदि भाजपा सत्ता में दोबारा वापसी करती है तो जीत का सेहरा मुख्यमंत्री रघुवर दास के सिर बंधेगा और यदि यूपीए उलटफेर करने में कामयाब रही तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन नायक के तौर पर उभरेंगे। इन दोनों शीर्ष नेताओं के समक्ष खुद का इतिहास बदलने की भी चुनौती है। 2009 में रघुवर दास भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी ने प्रदेश में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। नतीजे पार्टी के अनुकूल नहीं रहे थे और भाजपा का आंकड़ा 30 से घटकर 18 पर आ गया था। 10 साल बाद एक बार फिर रघुवर के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया है। सत्ता और संगठन की कमान उन्हीं के हाथों में है। रघुवर यदि भाजपा को सत्ता में वापस लाते हैं तो बड़ी उपलब्धि तो होगी ही साथ ही वे अपना पुराना कलंक धोने में भी कामयाब रहेंगे।

वहीं, यूपीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन की असर चुनौती दुमका के गढ़ को वापस पाने की है। यदि हेमंत किसी तरह अपनी टीम के साथ बहुमत के करीब पहुंच भी गए और दुमका हार गए तो यह जीत भी उन्हें सालती रहेगी। हेमंत वर्ष 2014 में दुमका से चुनाव हार गए थे, बरहेट ने उनकी लाज रखी थी। लोकसभा चुनाव में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को भी वे दुमका लोकसभा सीट से चुनाव जिताने में कामयाब नहीं रहे थे। इस बार भी वे बरहेट के साथ-साथ दुमका से भी चुनाव लड़े हैं। इस तर्क के साथ कि उन्हें अपनी पार्टी की पिछली हार का हिसाब-किताब चुकाना है। स्पष्ट है कि भाजपा और यूपीए के शीर्ष नेताओं की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी है। परिणाम बताएंगे कि विकास बनाम बदलाव में किसका पलड़ा भारी रहा।

मरांडी का भाजपा को ना, कांग्रेस को इन्कार नहीं

जासं, रांची : झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने सरकार बनाने को लेकर चल रही अटकलों के बीच भाजपा को पूरी तरह से ना कह दिया है। वह कांग्रेस को इन्कार नहीं कर रहे हैं। शनिवार को आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देने पहुंचे मरांडी ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

भाजपा ने गैरवाजिब हथकंडा अपना कर मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, शुरुआती रुझान से यह तय हो गया है कि लोगों में भाजपा के प्रति नाराजगी है। कुछ भी हो मगर झारखंड में फिर से भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है। कांग्रेस से हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मगर किसी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सत्ता की गोटियां बैठाने जुट रहे दोनों गुटों के चाणक्य

महासमर ▶ मतगणना पूर्व झारखंड पहुंच रहे पार्टियों के वरिष्ठ नेता

मुख्यमंत्री आवास से सीधे जुड़कर केंद्र से राज्य की गतिविधियों पर नजर रख रही भाजपा की कोर टीम

राज्य ब्यूरो, रांची

चाणक्यों के सॉफ्ट टारगेट हैं छोटे दल, कांग्रेस पर भी नजर

वर्तमान परिस्थितियों में जब दोनों गुटों में से किसी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है तो छोटे दलों के विधायकों को तोड़ना सबसे आसान रास्ता माना जा रहा है। इसमें झाविमो, आजसू और यहां तक कि कांग्रेस पर भी नजर है। पूर्व में ऐसे कई उदाहरण झारखंड में देखने को मिले हैं। वर्तमान सरकार में भी झाविमो के आठ में से छह विधायक पार्टी तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके लिए कुल विधायकों में से दो तिहाई के साथ होने की जरूरत है।

जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, 23 दिसंबर को परिणाम का पता चलेगा। संभावित चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक दलों के मैनेजरों की सक्रियता बढ़ गई है। एक्जिट पोल के रुझान और इससे इतर आने वाले परिणाम के आधार पर रणनीति का खाका तैयार किया जा रहा है। भाजपा और संप्रग के साथ-साथ अन्य छोटे दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है, इनकी कोशिश सत्ता के साथ बने रहने की है।

भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर दिल्ली में हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। भाजपा की दिल्ली में बैठी कोर टीम रांची के बराबर संपर्क में है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से शनिवार को फोन पर बातचीत कर फीडबैक लिया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं को रांची भेजा जा सकता है। सोमवार को मतगणना के दौरान सभी स्ट्रांग रूम में पर्याप्त मात्रा में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तैनाती का निर्देश भी दिया गया है।

इधर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह समेत एक दर्जन नेताओं के झारखंड पहुंचने की सूचना है। इनमें प्रदेश सह प्रभारी उमंग सिंघार, अजय शर्मा आदि नेता पहली खेप में पहुंच रहे हैं तो अन्य दिग्गज दूसरे चरण में पहुंचेंगे। दूसरी ओर, भाजपा के रणनीतिकार भी नई दिल्ली से पल-पल की गतिविधियों पर निगाह रख रहे हैं। वह लगातार मुख्यमंत्री से भी संपर्क में हैं। वहीं, एक्जिट पोल के बाद सत्ता के सूत्रधार माने जा रहे छोटे दलों की गतिविधियों पर भी सभी की नजर है। इनमें झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन अन्य दल अभी चुप हैं। जाहिर सी बात है परिणाम के बाद जोड़-घटाव करने का अवसर मिलेगा। फिलहाल चुप्पी साधे आजसू, राकांपा, और वामपंथी दलों का स्टैंड जानना दिलचस्प होगा।

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार हाईकमान तमाम विनिंग सीट पर नजर रख रहा है और कोशिश यह है कि वहां कोई ने कोई सीनियर नेता मौजूद हो। विधायकों के इधर-उधर होने की आशंकाओं के मद्देनजर उनपर नजर रखी जा रही है।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी के सीनियर नेताओं को भरोसा है कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ दल किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। वैसे दलों से कांग्रेस को बचाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। एक स्थानीय नेता ने तो यहां तक कहा कि बाहुबली नेताओं से कांग्रेस विधायकों को बचाने के लिए मजबूत टीम तैयार की जा रही है।

देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने में सीए की भूमिका अहम : ओम बिरला

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था को आगे बढ़ाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा योगदान है।

वे शनिवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फरीदाबाद शाखा, सेक्टर-20ए के 40 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने जीएसटी से लेकर कई विभिन्न आर्थिक मुद्दों में अपनी सलाह दी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बलवती हुई है। देश के लिए गौरव की बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था, बल्कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को भी संभाल रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की भी सेवा कर रहे हैं। हमारी सेना में कई ऐसे जवान हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आइसीएआइ की परीक्षाओं पर आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाई है। इसकी परीक्षा बहुत ही पारदर्शी है। सरकार द्वारा ली गई परीक्षाओं, साक्षात्कारों में सवालिया निशान लगाया जा चुका है, लेकिन इसकी परीक्षा के बारे में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। कार्यक्रम का मंच संचालन सचिव हर्ष मित्तल ने किया।

आइसीएआइ के चेयरमैन डीसी गर्ग ने ओम बिरला का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान आइसीएआइ के उपाध्यक्ष सीए अतुल गुप्ता, वाइस चेयरमैन सीए अमित पुनियानी, कार्यकारी सदस्य महेंद्र गुप्ता, जितेंद्र चावला, विजय कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष नितेश पाराशर सहित कई लोग उपस्थित थे।

लालू की सलाह, चुनाव परिणाम आने के बाद नए विधायकों को संभालकर रखें

▶ राजद सुप्रीमो एक्जिट पोल से हैं उत्साहित, मिलने गए नेताओं को दिया निर्देश

▶ लालू प्रसाद से मिली महुआ माजी और राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह

जागरण संवाददाता, रांची

रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने विपक्षी महागठबंधन खासकर राजद के प्रदेश नेतृत्व को हिदायत दी है कि नए विधायकों को संभालकर रखें। उनका अंदेशा यहां सरकार बनाने के लिए संभावित जोड़तोड़ को लेकर है। नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे निश्चिंत रहें। लालू प्रसाद झारखंड विधानसभा चुनाव के एक्जिट पोल को लेकर खासे उत्साहित हैं।

शनिवार को लालू से मिलने पहुंचे रांची से झामुमो की प्रत्याशी महुआ माजी, राजद प्रदेश अभय कुमार सिंह, राजद प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह ने कहा कि लालू काफी खुश हैं और झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त हैं। लालू प्रसाद से मिलने के बाद महुआ माजी ने कहा कि उन्हें धन्यवाद देने और आशीर्वाद लेने आई थी। राजद के लोगों ने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है। जनता ने क्या जनादेश दिया है, यह तो 23 को ही पता चलेगा, लेकिन समाज सेवा का कार्य जारी रहेगा। वैसे यह तय है कि प्रदेश में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी।

राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लालू यादव से गहन चर्चा हुई। राजद सुप्रीमो से गठबंधन के तहत सभी सीटों पर चर्चा हुई। एक्जिट पोल में मिल रहे रुझानों पर भी लालू यादव से बातचीत हुई। उन्होंने गठबंधन को संभावित बहुमत पर हर्ष जताया और बधाई दी। उन्होंने जीत रहे विधायकों को एकजुट रखने का भी निर्देश दिया। मुलाकात के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह ने कहा कि जनता नतीजे पर अपना फैसला लिख चुकी है। अभी फैसले को रिजर्व रखा गया है। 23 दिसंबर को रिजल्ट के साथ महागठबंधन की सरकार बनने की पुष्टि हो जाएगी।

ऐश्वर्या को मिलेगा गुजारा भत्ता

न्यायालय संवाददाता, पटना

ऐश्वर्या राय। फाइल

बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को भरण-पोषण के लिए अंतरिम गुजारा भत्ता मिलेगा। बाद में परिवारिक न्यायालय स्थायी गुजारा भत्ता तय करेगा। सूत्र बताते हैं कि ऐश्वर्या राय के आवेदन पर फैमिली कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश कर दिया है। कोर्ट ने आदेश को सार्वजनिक नहीं किया कि तेज प्रताप को प्रतिमाह पत्नी को कितने रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देने होंगे। ऐश्वर्या ने अक्टूबर 2019 में अदालत में आवेदन देकर ससुराल में घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। अदालत में उन्होंने गुजारा भत्ता दिलाने और रहने के लिए एक आवास की सुविधा की मांग की थी। अंतरिम गुजारा भत्ता तय हो गया है। रहने के लिए आवास मामले पर भी विचार कोर्ट करेगा। अगर तेजप्रताप अपने आवास में पत्नी को नहीं रहने देते हैं तब जिस किराए के मकान में वह रहेंगी, उसका किराया भी अदालत तेजप्रताप को देने का आदेश कर सकती है। आदेश में क्या-क्या है, यह सोमवार को पता चलेगा। अदालत में तेजप्रताप ने अपना वार्षिक आयकर रिटर्न में साल भर में दस लाख की आमदनी दिखाई गई थी।

मप्र में कांग्रेस को फिर निर्दलीय सपा, बसपा के सहारे की जरूरत

भोपाल, नईदुनिया स्टेट ब्यूरो

▶ कांग्रेस विधायक का निधन, विधानसभा में कांग्रेस के 114 विधायक बचे

▶ झाबुआ उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया की जीत से कांग्रेस को ताकत मिली थी

▶ निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के मंत्री होने से वे भी सरकार का हिस्सा हैं

मध्य प्रदेश में दलीय स्थिति	
कांग्रेस	114
भाजपा	108
सपा	01
बसपा	02
निर्दलीय	04
बहुमत के लिए जरूरी सीट	116
कुल सीट: 230 (शर्मा के निधन से एक सीट रिक्त)	

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा का भोपाल में शनिवार तड़के गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। इससे विधानसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या कम होकर 114 पर आ गई है और अब एक बार फिर कांग्रेस को बसपा-सपा व निर्दलीय विधायकों के सहारे की जरूरत होगी।

करीब डेढ़ महीने पहले झाबुआ उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया की जीत से कांग्रेस को ताकत मिली थी और 31 अक्टूबर को भूरिया के विधायक की शपथ लेने पर कांग्रेस के 115 विधानसभा सदस्य हो गए थे। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के मंत्री होने से वे भी सरकार का हिस्सा हैं और इससे कांग्रेस 116 सदस्य संख्या के साथ बहुमत में आ गई थी।

बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मांगा गनमैन : कमलनाथ सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने राज्य सरकार से अपने लिए एवं प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम के लिए सुरक्षा मांगी है। साथ ही आरक्षण आंदोलन के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के लोगों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की है। पिप्पल ने शुक्रवार को कमलनाथ से मुलाकात की थी। पिप्पल ने उनसे कहा था कि पार्टी के कामकाज को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आना-जाना होता है। कई बार सुरक्षा को लेकर संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए निजी सुरक्षा के लिए गनमैन दिया जाए।

छत्तीसगढ़ में 151 निकायों के लिए 66 फीसद मतदान

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीगसढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। प्रदेश के दस नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायत समेत 151 निकायो में 66 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। हल्की ठंड के बीच शुरू हुए मतदान में सुबह रफ्तार सुस्त थी, लेकिन जैसे-जैसे सूरज की गर्मी बढ़ी, वोटर घर से निकले। शहरी क्षेत्र में दस बजे के बाद बूथ पर भीड़ बढ़ी। प्रदेशभर में छिटपुट घटनाओं और विवादों के बीच शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बुजुर्गों और दिव्यांगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मतगणना 24 दिसंबर को होगी। प्रदेश के कई नगरीय निकाय में मतदाताओं का बूथ बदलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। राजनांदगांव के कई वार्ड में मतदाताओं का नाम सूची में नहीं होने की शिकायत मिली। जगदलपुर के दो वार्ड के करीब 100 लोगों का नाम सूची से गायब था। कई जगहों में बूथ के अंदर प्रचार करने की शिकायत मिली, जिसे अधिकारियों ने तत्काल बंद कराया। वहीं, कांकेर में 50 के कथित नकली नोट को लेकर बवाल मच गया। अफवाह फैली की एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के बाद नकली नोट दिखाने पर दो हजार पये मिलेंगे। धमतरी में फौजी के नाम पर वोट डालने पहुंचे उसके चचेरे भाई पुलिस के हवाले किया गया।

कैप्टन सरकार बिना ड्राइवर की गाड़ी टक्कर जरूर होगी : सुखबीर बादल

जागरण संवाददाता, पटियाला

पटियाला के मिनी सचिवालय के सामने शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए प्रधान सुखबीर सिंह बादल (हाथ ऊपर उठाए हुए), साथ में हैं पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा (पीली पगड़ी में), नीचे बैठे हुए (बाएं से) एनके शर्मा, बलदेव सिंह मान, हरमेल सिंह टोहड़ा, सुरजीत सिंह रखड़ा, सुरजीत सिंह कोहली व मंजू कुरैशी। जागरण

शिरोमणि अकाली दल के तीसरी बार प्रधान बनने के बाद सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के गृह नगर में पटियाला में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। उन्होंने कैप्टन को देश में सबसे नाकाम मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि कैप्टन सरकार बिना ड्राइवर की गाड़ी है जिसकी टक्कर जरूर होगी। सुखबीर को फिर प्रधानगी मिलने के बाद अकाली दल ने उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ शनिवार को पहला धरना दिया।

कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए सुखबीर ने कहा कि अकाली वर्करों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट उन्हें एक हफ्ते में जनता दे। अकाली सरकार बनने के बाद वह एसआइटी गठित कर इन अधिकारियों की जांच करवाएंगे। दोषी पाए जाने पर अधिकारी डिसमिस होंगे। जिस थाने में अधिकारी ने पर्चा दर्ज किया था, उसी थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज कर बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीआइ से पता चला है कि कैप्टन तीन सालों में महज छह बार ही दफ्तर गए। बादल सरकार के दौरान जहां रेवेन्यू पांच हजार करोड़ रुपये था, वहीं यह अब 4500 करोड़ रुपये रह गया है।

सुखदेव ढींडसा के जाने से शिअद को कोई नुकसान नहीं : सुखबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वरिष्ठ अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने जिस दिशा के लिए जो मन बनाया है, वह उसे चाव से पूरा करें। इससे अकाली दल को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई आए या जाए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्वयं वह (सुखबीर) ही क्यों न हों।

मुस्लिमों को शामिल करने की पैरवी : सुखबीर ने नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिमों को भी शामिल करने की फिर पैरवी की। कहा कि यह उनकी निजी राय नहीं बल्कि पार्टी की भी यही सोच है।

मप्र में कर्मकार कल्याण उपकर के 475 करोड़ रिकॉर्ड में नहीं

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर में 475 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी सामने आई है। यह जानकारी भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में दी गई है। कैग ने कर्मकार मंडल के पास रिकॉर्ड नहीं होने पर भी आपत्ति उठाई है और सरकार से व्यवस्थाएं सुधारने की सिफारिश की है।

कैग की रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा पटल पर रखी गई। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2018 में मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास 1212.79 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। इसमें से 1063.78 करोड़ रुपये मंडल ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की 29 शाखाओं में रख दिए। शेष 149.01 करोड़ रुपये का पता नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, बैंक खातों में जमा राशि पर 326.94 करोड़ रुपये ब्याज मिला है। यह राशि भी रोकड़ पुस्तिका में दर्ज नहीं की गई है।

इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा इकट्ठी की गई उपकर की राशि का भी पता नहीं चल रहा है। कैग ने इस पर भी आपत्ति ली है कि मंडल के पास अचल संपत्ति पंजी ही नहीं है। इस कारण ऑडिट के समय मंडल की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

छग व झारखंड को फिर कम मिला पुलिस अधुनिकीकरण का फंड

उपेक्षा

देश में सर्वाधिक नक्सल घटनाएं इन्हीं दोनों राज्यों में होती हैं, छत्तीसगढ़ के 12 और झारखंड के 18 जिलों को नक्सल प्रभावित मानती है केंद्र सरकार

संजीत कुमार, रायपुर

देशभर में होने वाली नक्सल वारदातों में से 80 फीसद छत्तीसगढ़ और झारखंड में होती हैं। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के 12 और झारखंड के 18 जिलों को नक्सल प्रभावित मानती है। इसके बावजूद इन दोनों राज्यों को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए बजट दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों की तुलना में कम दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में दोनों राज्यों को नौ से 10 करोड़ रुपये मिला है। बीते तीन-चार वर्षों से यह स्थिति लगातार बनी हुई है।

इस वर्ष सबसे ज्यादा उत्तर को 63 करोड़ : नक्सल प्रभावित राज्यों की सूची में 10 राज्य शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पिछले चार वर्षों में एक भी नक्सली घटना नहीं हुई है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रभावित राज्यों में इस वर्ष सर्वाधिक 63.19 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को मिला है। महाराष्ट्र को 47.11 करोड़, पश्चिम बंगाल को 28.9, बिहार को 27.62, मध्यप्रदेश को 27.11, आंध्रप्रदेश को 24.46, तेलंगाना को 17.48 और ओडिशा को 15.6 करोड़ मिला है। छत्तीसगढ़ को 9.72 और झारखंड को सबसे कम 9.21 करोड़ मिला है।

60 फीसद केंद्र और 40 फीसद राज्य का हिस्सा : राज्य पुलिस के लिए आधुनिक हथियार की खरीद, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार उपकरण, प्रशिक्षण के साथ फारेंसिक विज्ञान समेत अन्य काम किया जाता है। योजना में 60 फीसद राशि केंद्र सरकार देती है। बाकी 40 फीसद राज्य सरकार खर्च करती है।

पांच राज्य खर्च नहीं कर पाए पूरी राशि

आवंटित राशि के उपयोग के संबंध में राज्यों को केंद्र सरकार को रिपोर्ट (उपयोगिता प्रमाण पत्र) देनी पड़ती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश ने 2016-17 में जारी आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया है। छत्तीसगढ़ ने 3.37 और झारखंड ने 4.71 करोड़ का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। बंगाल ने 6.29, बिहार ने 20.63 और महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 40.82 करोड़ का उपजयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। राज्यों को 2017-18 का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस वर्ष 31 दिसंबर और 2018-19 का 31 दिसंबर 2020 तक देना होगा।

पुलिस आधुनिकरण मद में राज्यों का आवंटन

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
छत्तीसगढ़	9.01	11.87	10.52	9.72
झारखंड	8.54	4.71	9.97	9.21
मध्य प्रदेश	25.14	33.11	29.34	27.11
आंध्र प्रदेश	22.68	29.87	26.48	24.46
तेलंगाना	16.22	21.35	18.93	17.48
बिहार	25.62	33.73	29.90	27.62
महाराष्ट्र	43.69	57.54	51.00	47.11
ओडिशा	14.47	19.05	16.89	15.6
उत्तर प्रदेश	58.59	77.16	68.39	63.19
प.बंगाल	26.80	35.3	31.28	28.9

(नोट- राशि करोड़ रुपये में)

पुलिस आधुनिकीकरण मद में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पहले 50 से 55 करोड़ रुपये तक मिले हैं, लेकिन अब यह राशि धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसका असर तो पड़ता है। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार अपने संसाधन से भी बजट देती है। फंड बढ़ाने को लेकर हमारी तरफ से समय-समय पर पत्र व्यवहार भी किया जाता है।

- आरके विज, स्पेशल डीजी, छत्तीसगढ़ पुलिस

उम्र सीमा में उलझे मप्र भाजपा के मंडल अध्यक्षों के चुनाव

भोपाल, नईदुनिया :

छानबीन चल रही है। प्रमाण पत्र मांगे हैं। अब प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के बाद मंडल के रके परिणामों पर फैसला करेंगे।

- विजेश लुणावत, सह प्रदेश निर्वाचन प्रभारी, भाजपा

मध्यप्रदेश भाजपा मंडल अध्यक्ष का चुनाव उम्र सीमा में उलझ गया है। संगठन ने इन चुनावों के दौरान सामने आए ऐसे 72 मामलों की जांच शुरू कर दी है। पार्टी ने मंडल अध्यक्ष चुनाव में अध्यक्ष के लिए उम्र सीमा 35-40 वर्ष रखी थी। इसमें कुछ मामलों में अधिक उम्र को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। राज्य के एक हजार से ज्यादा भाजपा मंडलों में 15-16 नवंबर को चुनाव हुए थे।

एक माह ज्यादा होने पर रोका नाम : भाजपा के निर्वाचन प्रभारी के सामने उम्र सीमा को लेकर शिकायतें पहुंची थीं। उम्र के दायरे ने अच्छे-अच्छे नेताओं की सियासत फीकी कर दी है। मप्र प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह के गृह जिले जबलपुर में एक ग्रामीण मंडल अध्यक्ष की उम्र 40 साल एक महीना होने से निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका नाम घोषित करने से इनकार कर दिया गया। ऐसा ही मामला पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और पूर्व मंत्री जयंत मलैया सहित कई दिग्गज नेताओं के इलाकों में हुआ। जहां उम्र सीमा के पालन के लिए दिग्गज नेताओं को नए नाम पर सहमत होना पड़ा। उम्र के ऐसे ही 72 विवादास्पद मामलों को भी भाजपा संगठन ने रोक लिया है। प्रारंभिक छानबीन में लगभग 30 से 35 मंडलों में उम्र के मामले संदेहास्पद पाए गए हैं। लोगों के खिलाफ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उम्र के दस्तावेज प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजे थे। अब इन लोगों से दस्तावेज मांगे गए हैं।

130 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके अलावा 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।

उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया शुरू

कार्रवाई ▶ हिंसा से प्रभावित उत्तर प्रदेश के जिलों के डीएम और एसपी से मांगी गई नुकसान के मूल्यांकन की रिपोर्ट

नुकसान के मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति के लिए टीमें गठित की गई हैं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सीएए के विरोध में हुई हिंसा के दौरान संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से किए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन हरकत में आ गया है। लोक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान को वसूलने के लिए नोटिस भेजे जाने की कसरत शुरू हो गई है। हिंसा से प्रभावित जिलों के डीएम व एसपी से क्षति की मूल्यांकन रिपोर्ट रविवार शाम तक तलब की गई है। नुकसान के मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति के लिए टीमें गठित की गई हैं।

सीएए के विरोध में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने उपद्रवियों की पहचान कर उनकी संपत्ति नीलाम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, वीडियो व फोटो के जरिए की जा रही है। सार्वजनिक व सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान के मूल्यांकन के आधार पर भरपाई के लिए आरोपितों को नोटिस भेजे जाएंगे।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी करने वाले उपद्रवियों की सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से पहचान के बाद शनिवार को गोरखपुर में उनकी तस्वीरों का कोलाज लगाते पुलिस अधिकारी। प्रेट्र

लखनऊ में मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति के लिए एडीएम पूर्वी, एडीएम पश्चिम, एडीएम ट्रांसगोमती व एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में चार टीमें गठित कर दी गई हैं। बताया गया कि लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई घटनाओं को लेकर सीआरपीसी की धारा 149 के तहत उपद्रवियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि जमावड़ा व उसके फलस्वरूप उत्पन्न कानून व्यवस्था व शांतिभंग का प्रयास दंडनीय है। सार्वजनिक व निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, पथराव कर लोगों के जीवन से खिलवाड़, सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करना, आगजनी, बलवा व अन्य प्रकार से शांति भंग करना आपराधिक कार्य है।

यूपी पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के तहत होगी वसूली : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुई क्षति के दृष्टिगत दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर क्षतिपूर्ति के लिए वसूली की विधिक कार्रवाई का आदेश दिया था। आइजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पब्लिक प्रापर्टी डैमेज एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज करने के बाद यूपी पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के तहत नुकसान की वसूली का प्रावधान है। 2011 में इसे लेकर गृह विभाग ने एक शासनादेश भी जारी किया था। एडीएम फाइनेंस के जरिए यह कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाती है। तहसील से आरोपित के खिलाफ वसूली के लिए आरसी जारी होती है और कुर्क अमीन संबंधित की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई कराते हैं। इसके बाद नीलामी कराकर वसूली की जाती है।

मारे गए लोगों के परिजनों से आज मिलेगा तृणमूल का प्रतिनिधिमंडल

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सीएए के विरोध में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से तृणमूल कांग्रेस का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वरिष्ठ पार्टी नेता व पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य सदस्यों में सांसद प्रतिमा मंडल, मुहम्मद नदीमुल हक और अबीर विश्वास शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल रविवार सुबह लखनऊ पहुंचेगा और वहां प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेगा। तृणमूल की ओर से कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल मानवीय आधार पर उत्तर प्रदेश जा रहा है।

आरिफ मुहम्मद खान बोले, मोदी सरकार ने पूरा किया नेहरू-गांधी का किया वादा

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देशव्यापी विरोध के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएए के तहत महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के उस वादे को पूरा किया है जो उन्होंने उन लोगों से किए थे जो पाकिस्तान में दुखद जीवन जी रहे थे। इस कानून की बुनियाद साल 1985 और 2003 में रखी गई थी। मोदी सरकार ने केवल इसे कानूनी जामा पहनाया है।

सीएए में मुसलमान शरणार्थियों को जगह नहीं मिलने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर बनाया गया था। ऐसे में क्या वे लोग मुस्लिमों को भी प्रताड़ित करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं मानता हूं कि मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था। वे यहां आर्थिक अवसरों की तलाश में आए थे।' बता दें कि केंद्र द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून को कई प्रदेशों ने अपने यहां लागू करने से इन्कार कर दिया है।

राजघाट पर कल धरना देगी कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसियां : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस सोमवार को राजघाट पर सत्याग्रह धरना देगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाले इस धरने में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा समेत शीर्ष नेताओं के भाग लेने की संभावना है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को बताया कि 23 दिसंबर को तीन बजे से आठ बजे तक महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सीएए और एनआरसी के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलकर पार्टी केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ और बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी।

वेणुगोपाल ने बताया कि मौन प्रदर्शन का फैसला शनिवार को सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पहले रविवार को धरना देने वाली थी। लेकिन, अधिकारियों द्वारा इसकी इजाजत नहीं मिलने के कारण सोमवार को धरना देने का फैसला किया गया।

वेणुगोपाल ने बताया कि भाजपा सरकार के हाल के फैसलों के चलते देशभर के युवाओं में नाराजगी है। लोग संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की तानाशाह और अड़ियल भाजपा सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने के नाम पर आम लोगों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। इसने हालात को और खराब किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल प्रयोग के खिलाफ है।

भारत का गलत नक्शा पोस्ट कर ट्रोल हुए शशि थरूर

मुंबई, आइएएनएस : कांग्रेस नेता शशि थरूर भारत का गलत नक्शा ट्वीट कर फंस गए। ट्वीट के बाद थरूर ट्रोल होना शुरू हो गए और भाजपा नेता संबित पात्रा समेत कई लोगों ने उन पर निशाना साधा। दरअसल, थरूर ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन की सूचना साझा की थी और उसके साथ भारत का गलत नक्शा पोस्ट कर दिया। इसके साथ कैप्शन लिखा था, 'कल सुबह मेरा पहला कार्यक्रम इंडिया अगेंस्ट सीएए-एनआरसी कोझीकोड में विरोध प्रदर्शन। सभी का स्वागत।' सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल होने के बाद शशि थरूर ने अपने इस विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया।

थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ : स्थानीय अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कांग्रेस नेता पर अपनी एक किताब में हिंदू महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर तिरुवनंतपुरम की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। थरूर तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं।

'नागरिकता कानून बनाना केंद्र सरकार का अधिकार'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ नागरिकता को लेकर पैदा होने वाले संदेह को खत्म करता है एनआरसी

▶ केंद्रीय सूची के विषय पर बनाए गए कानून राज्यों पर बाध्यकारी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच यह साफ होने लगा है कि नागरिकता को लेकर कानून बनाना केंद्र सरकार का अधिकार है। यह तर्क भी दिया जा रहा है कि किसी देश के लिए यह अपेक्षित है कि उसके पास सभी नागरिकों का एक रजिस्टर हो। आखिर रजिस्ट्रार जनरल भी यही करता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसआर सिंह के मुताबिक, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) एक ऐसा प्रावधान है, जो नागरिकता को लेकर पैदा होने वाले संदेह को खत्म करता है। नागरिकता के बारे में केंद्र सरकार को कानून बनाने और कोई भी आदेश जारी करने या कोई व्यवस्था तय करने का बहुत विस्तृत अधिकार है। सरकार अथवा संसद को यह अधिकार सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 17 से प्राप्त होता है। इसमें तीन बिंदु दिए गए हैं, जिनमें पहला सिटिजनशिप, दूसरा नेचुरलाइजेशन और तीसरा एलियंस है।

जस्टिस सिंह ने बताया कि इसके तहत सरकार चाहे तो इस बारे में कानून बनाए या एक्जीक्यूटिव आदेश जारी कर कोई व्यवस्था तय करे। एनआरसी बनाने की शक्ति केंद्र सरकार इन्हीं प्रावधानों से प्राप्त करती है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 256 कहता है कि केंद्र द्वारा बनाने गए किसी भी कानून के क्रियान्वयन के लिए राज्य बाध्यकारी हैं। केंद्रीय सूची के विषय पर केंद्र अथवा संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्यों पर बाध्यकारी है। राज्य इसे लागू करने से मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्यों को इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।

हालांकि नागरिकता संशोधन कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पूरे देश में एनआरसी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन, इसके समर्थकों का मानना है कि जनगणना और एनआरसी में बहुत फर्क नहीं है। एनआरसी यह भी तय करेगा कि देश में रहने वाला व्यक्ति अवैधानिक तरीके से तो नहीं रह रहा है। यह भी एक रजिस्टर मात्र होगा जो नागरिकों की जानकारी देगा।

मोदी सरकार का अगला एजेंडा जनसंख्या रजिस्टर

नई दिल्ली, आइएएनएस : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर देशभर में मचे घमासान के बीच मोदी सरकार का अगला एजेंडा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) बनाना हो सकता है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि मंगलवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में एनपीआर के नवीनीकरण को मंजूरी दे दी जाए। एनपीआर के तहत एक अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। इसका मकसद देश के निवासियों की पहचान का विस्तृत डाटाबेस बनाना है। इस डाटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में 2010 में एनपीआर बनाने की पहल शुरू हुई थी। इसमें कोई भी व्यक्ति जो छह माह या इससे अधिक समय से देश के किसी हिस्से में रह रहा है, उसका नाम लिखा जाएगा।

मेंगलुरु में कर्फ्यू में ढील, हैदराबाद में प्रदर्शन जारी

बेंगलुरु, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद मेंगलुरु में हालात शनिवार को शांतिपूर्ण रहे और शहर में कर्फ्यू में ढील भी दी गई। बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में भी स्थिति शांतिपूर्ण रही और कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि बेंगलुरु में निषेधाज्ञा अभी जारी है। वहीं, हैदराबाद में शनिवार रात हजारों लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के मुख्यालय पर जुटकर सीएए और एनआरसी का विरोध किया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को मेंगलुरु का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने हिंसा की घटनाओं की जांच कराने और दिन के कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की। इस बीच, कर्फ्यू का उल्लंघन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे केरल से भाकपा के राज्यसभा सदस्य बिनॉय विस्वम और उनके समर्थकों को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया।

तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी : तमिलनाडु में भी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को कई माकपा कार्यकर्ताओं ने एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश विफल कर दी।

मेघालय से इंटरनेट प्रतिबंध हटा : असम और मेघालय में शांति है, हालांकि वहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी हैं। शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ और मेघालय में शिलांग के दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी गई। दोनों ही राज्यों से मोबाइल और इंटरनेट से प्रतिबंध हटा लिया गया है। असम से इसे शुक्रवार को हटाया गया था, जबकि मेघालय से इसे शनिवार को हटा लिया गया।

कर्नाटक के कलबुर्गी में शनिवार को फ्लैग मार्च करते अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस के जवान। एएनआइ

हैदराबाद में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने लहराए तिरंगे

हैदराबाद, आइएएनएस : हैदराबाद में हजारों प्रदर्शनकारियों ने कई मुस्लिम संगठनों के समूह 'यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी' के बैनर तले शनिवार रात एआइएमआइएम मुख्यालय पर जुटकर सीएए और एनआरसी का विरोध किया। सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई और इस दौरान एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेता मंच पर खड़े रहे और नीचे भीड़ में कई लोग तिरंगे लहराते रहे। वहीं, दिन में भी कई संगठनों ने शहर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

सिद्दरमैया बोले-देश में अघोषित आपातकाल

बेंगलुरु, एएनआइ : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में धारा-144 लागू किए जाने के एक दिन बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा, उन्हें नहीं पता कि देश में लोकतंत्र अस्तित्व में है अथवा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि यह अघोषित आपातकाल है।

पत्रकारों से बातचीत में सिद्दरमैया ने कहा, 'कोई अदालत यह नहीं कहती कि अगर धारा-144 लागू हो तो आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करके रखा गया है। इस तरह घटनाएं सिर्फ फासीवादी देश में होती हैं।' इससे पहले दिन में मेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने उनकी शहर यात्रा के संबंध में एक नोटिस जारी कर कहा था कि उनकी यात्रा से कानून-व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो सकता है। इस पर सिद्दरमैया ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि राज्य या केंद्र में लोकतंत्र है या नहीं। अगर उनके लिए हालात अनुकूल हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं। हम वहां लोगों को भड़काने के लिए नहीं जा रहे। हमें उनसे कानून-व्यवस्था के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है।'

एनसीआर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई

जेएनएन, नई दिल्ली

शुक्रवार को हुई हिंसा और आगजनी के बाद शनिवार को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के कारण शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में नागरिक सुरक्षा कानून के विरोध और समर्थन में हुए प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर विश्वविद्यालय की छात्राओं की अगुआई में शनिवार को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहा। इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सीएए के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतरे। राजधानी दिल्ली में अब तक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 51 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरियागंज में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में 15 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने तीस हजारी अदालत में पेश किया। दंगा भड़काने, पुलिसकर्मियों पर पथराव व आपराधिक साजिश रचने के आरोप में चंद्रशेखर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वहीं, शुक्रवार को गाजियाबाद, मुरादनगर, लोनी में भड़की हिंसा के मामलों में 461 के खिलाफ नामजद और 4950 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के गेट पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करते लोग। जागरण

62 फीसद लोग सीएए व 65 फीसद एनआरसी के पक्ष में

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश भर के करीब 62 फीसद लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया है। असम के करीब 68 फीसद लोग इसके खिलाफ हैं। आइएएनएस-सीवोटर के एक सर्वे में शनिवार को यह दावा किया गया है। करीब 65.4 फीसद और असम के 76.9 फीसद लोग चाहते हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए।

देश भर के 3000 से ज्यादा नागरिकों के बीच 17 से 19 दिसंबर के बीच कराए गए सर्वे में असम, पूर्वोत्तर और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी शामिल किया गया। 55.9 फीसद लोगों का मानना है कि सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) केवल घुसपैठियों के खिलाफ है जबकि 31.9 फीसद इसे मुस्लिमों के खिलाफ मानते हैं।

सर्वे के मुताबिक 62.1 फीसद लोगों ने कहा कि वे सीएए का समर्थन करते हैं जबकि 36 फीसद ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में क्रमशः 57.3, 64.2, 67.7 और 58.5 फीसद लोग इस कानून के समर्थन में हैं। पूर्व में जहां इसके खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से विरोध हुआ है वहां 50.6 फीसद ने समर्थन किया जबकि 47.4 फीसद ने विरोध किया। सर्वे में शामिल 47 फीसद लोगों का मानना है कि सीएए पारित कराने में संविधान का उल्लंघन हुआ है और करीब इतने ही लोगों का मानना है कि संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। सर्वे के दौरान 5.5 फीसद लोगों ने कहा कि वह इस संबंध में कोई राय नहीं दे सकते।

पुणे में मानव श्रृंखला बनाकर किया सीएए का समर्थन

पुणे, प्रेट्र : पुणे में सीएए के समर्थन में बनाई गई मानव श्रृंखला में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान करीब 500 मीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें भाग लेने वालों में युवा, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, कामगार पेशेवर के अलावा विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल थे।

जनमत संग्रह सिर्फ राष्ट्रीय सरकार के अनुरोध पर : यूएन

संयुक्त राष्ट्र, आइएएनएस : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि यह वैश्विक निकाय सिर्फ राष्ट्रीय सरकार के अनुरोध पर ही जनमत संग्रह में शामिल होता है। शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून पर यूएन की देखरेख में जनमत संग्रह कराने की मांग की थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजैरिक ने कहा कि किसी चुनावी कार्य और जनमत संग्रह में संयुक्त राष्ट्र के शामिल होने की मानक नीति यही है कि इसके लिए राष्ट्रीय सरकार अनुरोध करे। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ ममता बनर्जी के मांग करने का नहीं बल्कि बयान के स्तर का है जिस पर संयुक्त राष्ट्र काम करता है। बता दें कि ममता ने बाद में अपनी मांग से पलटते हुए यह भी कहा था कि उनका मतलब मानवाधिकार आयोग जैसे किसी निकाय की देखरेख में ओपिनियन पोल कराने से था।

प्रभाव बरकरार

बिहार बंद के दौरान अलग-थलग दिखे महागठबंधन के घटक दल, बिहार बंद के दौरान राजद ने दो मोर्चे खोले, साथी दलों को पीछे रखा, धरना पर बैठे कुशवाहा से नहीं हो सकी तेजस्वी की बात-मुलाकात

'दुश्मन' सरीखे 'दोस्तों' को भी राजद ने दिखाई ताकत

अरविंद शर्मा, पटना

बिहार बंद के दौरान राजद ने दो मोर्चा खोल रखा था। पहला उसे भाजपा-जदयू गठबंधन को अपनी ताकत का अहसास कराना था और दूसरा महागठबंधन के सहयोगी दलों को भी बताना था कि लालू प्रसाद का प्रभाव अभी पस्त नहीं हुआ है। बिहार में भाजपा-जदयू की संयुक्त शक्ति से लड़ने के लिए राजद को किसी अन्य पार्टी से ऊर्जा और अहसान लेने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि बंद के एलान से लेकर मैदान-ए-जंग तक में भी उसने अपने साथी दलों को भाव नहीं दिया। समान मकसद का वास्ता भी काम नहीं आया।

डाकबंगला चौराहे पर राजद, कांग्रेस और रालोसपा के अलग-अलग विरोध प्रदर्शन की तस्वीर बता रही है कि लोकसभा चुनाव में साथी दलों के मोलभाव को राजद ने सबक की तरह ग्रहण किया है। तभी विरोध का समय, मकसद और जगह एक होने के बावजूद रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भाजपा-जदयू के विरोध में डाकबंगला चौराहे पर शनिवार को अलग नारे लगाते रहे और तेजस्वी यादव अपने समर्थकों को संविधान बचाने की शपथ अलग दिलाते रहे। दोनों नेताओं में से किसी ने इतनी औपचारिकता भी नहीं निभाई कि क्षण भर के लिए ही सही, एक-दूसरे के साथ हो लें या कम से कम हाथ ही मिला लें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की टोली भी अलग से ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को कोसती नजर आई। महागठबंधन के एक और प्रमुख सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का भी प्रदर्शन स्थल पर अता-पता नहीं था। वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी की भी झलक नहीं दिखी, जबकि हफ्ते भर पहले कांग्रेस, रालोसपा, हम और वीआइपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोस्ती का दावा-वादा किया था और यह भी कहा था कि राजद के बिहार बंद में महागठबंधन की एकजुटता दिखेगी। वीआइपी के कुछ नेताओं ने सुबह में ही सबसे पहले अपनी सक्रियता दिखाकर दोस्ती की इतिश्री कर ली। समान मकसद का दावा करने वाले वामदलों के नेता भी नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वामदलों की निष्क्रिय सहयोग का मतलब साफ था कि उनके लिए यह राजद से बदला लेने का मौका था।

पटना में शनिवार को सीएए और एनआरसी के विरोध में आयोजित रैली को संबोधित करते तेजस्वी यादव। प्रेट्र

आभार के लिए भी नहीं निकले शब्द : बिहार बंद की समाप्ति पर सफलता के दावे के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साथ निभाने वाले व्यवसायिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया है। किंतु उसमें भी मदन मोहन झा, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टियों का नाम लेना जरूरी नहीं समझा।

परिणिति पर गरमाई सियासत, कांग्रेस पर भाजपा का पलटवार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▶ अभिनेत्री से मई 2016 में एक साल के लिए हुआ था ब्रांड एंबेसडर के लिए एमओयू

हरियाणा में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणिति चोपड़ा को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एंबेसडर पद से हटाने को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जहां इसे बेटियों की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार और भाजपा संगठन ने पलटवार करते हुए कहा कि मई 2016 में परिणिति के साथ हुआ समझौता ज्ञापन सिर्फ एक साल के लिए था। एमओयू को जब कभी नवीनीकृत नहीं किया गया तो उन्हें हटाने का सवाल कहां उठता है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। तथ्यों के सत्यापन के बिना कोई भी बात कहने से सभी को बचना चाहिए। परिणिति के साथ सरकार का एमओयू अप्रैल 2017 तक था। इसके बाद उसे रिन्यू नहीं किया गया।

दरअसल, विवाद की शुरुआत जामिया के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में परिणिति के ट्वीट से हुई थी। परिणिति ने कहा कि 'जब लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं तब ऐसा ही होता है। नागरिकता कानून को भूल जाइए। हमें एक बिल पास करना चाहिए और अपने देश को लोकतंत्र नहीं कहना चाहिए। अपने मन की बात कहने पर निर्दोष लोगों की पिटाई असभ्य तरीका है।' इस ट्वीट को सियासी गलियारों में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर के रूप में देखा गया जो नागरिकता संशोधन बिल के विरोध और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में है। इसके बाद सरकार ने सफाई दी थी कि अब परिणिति हरियाणा की ब्रांड एंबेसडर नहीं हैं।

83,496 करोड़ रुपये महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने के बावजूद लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। राज्य विधानसभा में रखी गई 2017-18 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 22 दिसंबर 2019

रांची की निर्भया को मिला इंसाफ, दोषी को फांसी की सजा

- दुष्कर्म के बाद की थी बीटेक छात्रा की हत्या, जला दिया था शव
- सीबीआइ के विशेष जज ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया

जागरण संवाददाता, रांची

झारखंड की राजधानी रांची में बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने शनिवार को दोषी राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन (25 वर्ष) को फांसी की सजा सुनाई। 1101 दिन बाद रांची की इस निर्भया को इंसाफ मिला है। दोषी राहुल राज मूलतः बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है और आपराधिक प्रवृत्ति का है।

सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा ने फैसले में घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। कहा कि यह अपराधी समाज के लिए जहर है। सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। फांसी से कम की सजा पीड़िता के साथ अन्याय होगा। अदालत ने कहा कि अभियुक्त पेशेवर अपराधी है और योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया है। फैसला सुनाने के बाद राहुल राज को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में मौजूद मृतका के पिता घटना को याद कर रोने लगे। कहा कि फांसी की सजा भी अपराधी के लिए कम ही है। परंतु, संतोष है अदालत ने न्याय किया है। इससे समाज को संदेश जाएगा।

15 दिसंबर, 2016 की आधी रात

रांची में शनिवार को बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी राहुल राज को अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल ले जाते पुलिसकर्मी। एएनआइ

हैवानियत को दिया था अंजाम : किसी अनहोनी से बेपरवाह पीड़िता बूटी बस्ती स्थित अपने घर में सोयी हुई थी। आधी रात को अभियुक्त ने उसके घर में प्रवेश किया। उसके साथ दुष्कर्म किया और तार से गला दबा कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर और बिस्तर पर मोबिल छिड़ककर कर आग लगा दिया। पीड़िता के परिजन गांव गए हुए थे। सुबह उन्होंने बात करनी चाही तो मोबाइल फोन बंद था। किराएदार ने जब अंदर जाकर देखा, तो घर में धुंआ ही धुंआ था। पीड़िता का शरीर जल रहा था।

> यह अपराधी समाज के लिए जहर के समान है। इसमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। फांसी से कम सजा पीड़िता के साथ अन्याय होगा।
> –जज ने फैसले में कहा

सीबीआइ ने उठाया पर्दा

तीन साल तक पुलिस और उसके बाद सीआइडी केस की छानबीन करती रही, लेकिन हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी। मार्च 2018 में मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया। महज दो-तीन माह में सीबीआइ हत्यारे तक पहुंच गई। सीबीआइ के इंस्पेक्टर परवेज आलम ने हत्याकांड से पर्दा उठाया। राहुल राज नालंदा जिले के एकंगरसराय के धुरगांव का रहने वाला है। वह विभिन्न मामलों में लखनऊ जिला जेल में बंद था। सीबीआइ गत 22 जून को उसे लखनऊ से प्रोडक्शन वारंट पर लायी। एजेंसी ने रिकॉर्ड 16 दिन में 30 लोगों की गवाही पूरी करा ली। कातिल को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 302, 376, 499, 201 में दोषी ठहराया गया है। चारों मामले में अलग-अलग सजा सुनाई गई है। साथ ही, चारों मामले में पांच-पांच हजार रुपये (कुल 20 हजार रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है।

दुष्कर्म के आरोपित की गला काटकर हत्या

संवाद सहयोगी, सांपला (रोहतक) : गांव रुड़की के दुष्कर्म के आरोपित अंकित (22) की अज्ञात बदमाशों ने फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। शनिवार सुबह मृतक का शव ड्रेन से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक करीब चार माह पहले दुष्कर्म के मामले में जेल से बेल पर बाहर आया था। पुलिस को शक है कि गांव के ही एक युवक ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। आइएमटी थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज आरोपितों की तलाश कर रही है।

गांव रुड़की में शनिवार की एक मकान में निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों ने खून से सना एक फावड़ा देखा। बताया जा रहा है कि फावड़ा देखकर मजदूर मौके की ओर चले तो ड्रेन में खून से लथपथ एक शव पड़ा हुआ था। मजदूरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मृतक की शिनाख्त करीब 22 वर्षीय अंकित उर्फ मिंटू पुत्र सुखबीर के रूप में की। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की रात ही आरोपित की फावड़े से काटकर हत्या की गई है। करीब दो वर्ष पूर्व अंकित उर्फ मिंटू पर एक युवती द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने एफआइआर दर्ज करते हुए आरोपित अंकित को जेल भेजा था।

आरोपित पर अवैध हथियार रखने समेत तीन मामले हैं दर्ज : मृतक अंकित उर्फ मिंटू पर दुष्कर्म के अलावा अवैध हथियार रखने और एक अन्य मामले में मुकदमा दर्ज है।

अब पीडीपी नेता जहूर मीर पर भ्रष्टाचार मामले में शिकंजा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जहूर अहमद मीर। फाइल

- निकाय समिति की दुकानें चहेतों को आवंटित करने का है आरोप
- खादी ग्रामोद्योग में नियुक्तियों में भी भूमिका सवालों के घेरे में

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पूर्व मंत्री जहूर अहमद मीर पर भ्रष्टाचार मामले में शिकंजा कस रहा है। उन पर नियमों की अनदेखी कर पांपोर में निकाय कमेटी की दुकानें चहेतों को आवंटित कराने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

जहूर मीर का नाम जेके बैंक घोटाले व फर्जी नियुक्तियों में पहले भी कथित तौर पर आ चुका है। इन मामलों में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। खादी ग्रामोद्योग विभाग में दो वर्ष पूर्व हुई नियुक्तियों में भी उनकी भूमिका सवालों के घेरे में रही थी। उस सूची में भी उनके कई विश्वासपत्र शामिल थे। बाद में यह सूची रद कर दी गई थी।

ताजा मामला वर्ष 2014 का है। पांपोर निकाय समिति के पूर्व सेटलमेंट अधिकारी अब्दुल हमीद वानी का आरोप है कि पीडीपी के तत्कालीन मंत्री जहूर अहमद मीर के दबाव और प्रभाव के चलते 10 दुकानों को पीडीपी से जुड़े लोगों को औने-पौने दाम में आवंटित किया गया। कुछ दुकानें तो बिना औपचारिकता पूरी किए ही आवंटित कर दी गईं। इनमें एक दुकान पूर्व मंत्री के चचेरे भाई को दी गई। दुकानों के आवंटन में हुई गड़बड़ी से सरकारी खजाने को एक करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। अब अदालत ने एसीबी को नए सिरे से जांच करने को कहा है। अदालत ने राज्य सतर्कता संगठन द्वारा 18 मई 2015 को सौंपी जांच रिपोर्ट भी मांगी है।

अदालत ने कश्मीर के स्थानीय शहरी निकाय के निदेशक को पांपोर निकाय कमेटी की सभी परिसंपत्तियों और बिना नीलामी आवंटित दुकानों का पूरा ब्योरा तैयार करने के लिए एक समिति बनाने का आदेश दिया है।

नापाक हरकत ▸ पाक ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन

पाक चौकियां व जैश का लांचिंग पैड तबाह, दो सैनिक भी ढेर

सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशनल मोड में तैयार रहने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू से कश्मीर तक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलाबारी कर रहे पाक के दो सैनिकों को भारत ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के दुदनियाल और एथमुकाम में भी तीन पाकिस्तानी चौकियों और आतंकियों के एक लांचिग पैड को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों तरफ से हो रही गोलाबारी के कारण सीमाई इलाकों में तनाव बना हुआ है। पाक सेना मोर्टार और तोपखाने का इस्तेमाल कर रही है। सैन्य प्रशासन ने एलओसी पर तैनात सभी सैन्याधिकारियों को पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में तैयार रहने का निर्देश दिया है।

कुछ दिन पहले मार गिराए थे तीन बैट कमांडो

पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने के प्रयास कर रहा है। गत दिनों सुंदरबनी के ललयाली क्षेत्र में पाक सेना की बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) ने हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था। वहीं, तीन बैट कमांडो मार गिराए थे।

पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार रात साढ़े नौ बजे एलओसी से सटे प्लांवाला और केरी बट्टल के अलावा उड़ी, टंगडार, करनाह और गुरेज में सैनिक और नागरिक ठिकानों पर भारी गोलाबारी की। इसके बाद भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की। संबंधित सैन्य अधिकारियों ने बताया कि प्लांवाला में छन्नी दमानु चौकी के सामने एलओसी पर एक पाक चौकी को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां दो पाक सैनिक मारे गए हैं और कुछ अन्य जख्मी हुए हैं। इसके बाद पाक सेना की बंदूकें शांत हुईं, लेकिन उत्तरी कश्मीर के केरन, टंगडार व कंजलवान में दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी जारी है। यहां पाक सेना ने नागरिक बस्तियों को निशाना बनाया है।

आंतकी ठिकानों को बनाया निशाना: भारतीय जवानों ने एलओसी पार गुलाम कश्मीर में नीलम और लीपाघाटी में दुदनियाल, एथमुकाम, चिलाना और शारदा में बने पाकिस्तानी सैन्य व आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद का एक लांचिग पैड के अलावा तीन पाक चौकियां भी तबाह हुई हैं। वहीं, इलाके में सुबह कई एंबुलेंस गाडियों को देखा है। इसी आधार पर कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने या जख्मी होने का दावा किया जा रहा है।

गरीब का झोपड़ा गिरे तो भी रात में खुले कोर्ट : जस्टिस सुधीर

जागरण संवाददाता, इटावा : इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने हिंदी भाषा के विकास के लिए उच्च और मध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता बदलने पर जोर देने के साथ ही न्याय व्यवस्था को भी आईना दिखाया। दो टूक कहा कि न्याय व्यवस्था प्रभावशाली लोगों के हाथों में रह गई है, जबकि अमीरों की तरह गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। गरीब का झोपड़ा गिर रहा हो तो उसके लिए भी रात में अदालत खुलें।

वह शनिवार शाम इटावा के इस्लामिया इंटर कॉलेज में सेवा निधि के 27वें सारस्वत सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र का पोषण करने वाले 80-85 फीसद तबके को जब तक चुनाव के बाद व्यवस्था में भी शामिल कर बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हिंदी के प्रवाह का नैसर्गिक स्रोत नहीं खुल सकेगा।

इंग्लैंड से भी पढ़कर आने वाला सरकार बनाने के लिए वोट हिंदी में ही बोलकर मांगता है। समाज का उच्च वर्गीय जनमानस वोट देने के लिए घर से नहीं निकलता, मगर ड्राइंग रूम में लोकतंत्र की बात करता है। इसी दोहरी मानसिकता से हिंदी दोयम दर्जे की भाषा बनती जा रही है।

उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि 400 वर्षों की गुलामी की मानसिकता से पीछा नहीं छूट रहा है। जब तक अमेरिका से सराहना न मिले और इंग्लैंड से प्रशंसा पत्र प्राप्त न हो, तब तक गर्व की अनुभूति नहीं होती। अंग्रेज 1947 में चले गए, लेकिन हमारी संस्कृति खा गए और अंग्रेजी की धूल हमारे दिमाग पर चिपका गए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
साकेत ब्रांच, 181-ए, खिड़की एक्सटेंसन, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली-110017, dbsake@bankofbaroda.co.in
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
[illegible] 30,51,645/- [illegible]
अचल संपत्ति का विवरण
[illegible]
दिनांक: -19.12.2019, स्थान: नई दिल्ली — अखिलेश कुमार पाठक, मुख्य प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
सोहना गुरुग्राम, हरियाणा-122101
अनेक्सर K कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
[illegible] 8,42,434.45/- [illegible]
अचल संपत्ति का विवरण
[illegible]
दिनांक: 19.12.2019, स्थान: गुरुग्राम — मुख्य प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
सोहना गुरुग्राम, हरियाणा-122101
अनेक्सर K कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
[illegible] 12,69,828.52/- [illegible]
अचल संपत्ति का विवरण
[illegible]
दिनांक: -19.12.2019, स्थान: गुरुग्राम — मुख्य प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
सोहना गुरुग्राम, हरियाणा-122101
अनेक्सर K कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
[illegible] 26,65,621.28/- [illegible]
अचल संपत्ति का विवरण
[illegible]
दिनांक: -19.12.2019, स्थान: गुरुग्राम — मुख्य प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

ईको सेंसटिव जोन के दायरे में ही होगा गंगोत्री हाईवे का काम

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : उत्तरकाशी से गंगोत्री तक ऑल वेदर रोड के तहत सड़क चौड़ीकरण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी के चेयरमैन प्रो. रवि चोपड़ा ने कहा कि इस पर काम शुरू किया जाएगा, लेकिन यह काम ईको सेंसिटिव जोन की गाइड लाइन के दायरे में होगा। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर ऑल वेदर रोड में हाईवे की चौड़ाई 19 मीटर की जा रही है, लेकिन ईको सेंसिटिव जोन में यह संभव नहीं है। वर्तमान में उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 100 किमी लंबा हाईवे छह से दस मीटर तक चौड़ा है।

शनिवार को उत्तरकाशी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रवि चोपड़ा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वह यह देखने आए हैं कि क्षेत्र में ईको सेंसिटिव जोन की गाइड लाइन का पालन हो रहा है या नहीं। इस मौके पर गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत भी मौजूद थे। गौरतलब है कि ऑल वेदर रोड निर्माण में पर्यावरण को लेकर उठे सवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना के तहत नए कार्यों पर रोक लगा दी थी। इसी कारण अभी तक उत्तरकाशी से गंगोत्री तक सड़क काम शुरू नहीं हो पाया है।

पहाड़ों पर बर्फबारी थमी, दिल्ली में ठंड बरकरार

जासं, नई दिल्ली

उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों में जहां बर्फबारी रुकने से कुछ राहत मिली है, लेकिन कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक सड़कों के बंद होने और उच्च पर्वतीय इलाकों में तापमान जमाव बिंदू के नीचे जाने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में ठंड और ठिठुरन अब भी बनी हुई है। इसके अलावा कोहरे के कारण हवाई यातायात के प्रभावित होने का सिलसिला शनिवार को भी जारी है।

कोहरे की चादर में मैदानी इलाके : दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब में भी कड़ाके की ठंड के साथ-साथ अब कोहरा भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शनिवार सुबह दृश्यता बहुत कम रही। शुक्रवार देर रात्रि हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आया तो शनिवार को धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। हिसार में पिछले तीन दिनों से रात्रि तापमान चार डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, जो शुक्रवार को आठ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

पहाड़ों पर मौसम ने दी राहत : उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी रुकने से मौसम ने कुछ राहत दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप खिली रही। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी उछाल आया और शीतलहर का प्रकोप भी कम हुआ है। राज्य मौसम विज्ञान

जिला लाहुल स्पीति के गौशल गांव का दृश्य। बर्फबारी के बाद मानों पूरी घाट सफेदचांदी में लिपटी हो। जागरण

केंद्र के मुताबिक अधिकतम तापमान दो से चार और न्यूनतम में एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा।

दिल्ली से लेकर मप्र तक उड़ानें रद : गत 24 घंटे में आइजीआइ एयरपोर्ट पर आने वाली 46 उड़ानों को डायवर्ट कर अन्य एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके अलावा 100 से ज्यादा विमानों का संचालन आधे से दो घंटे की देरी से हुआ। हालांकि इस दौरान किसी भी उड़ान के रद होने की सूचना नहीं है। उड़ानों की इस लेटलतीफी से यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट मौसम विभाग के मुताबिक, कोहरे के कारण शनिवार की सुबह 5.30 बजे एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर 350 मीटर जबकि 8.30 बजे 100 मीटर तक पहुंच गया था। इस दौरान कैट तकनीक से उड़ानों का संचालन किया गया। कोहरे के कारण दिल्ली आ रहीं 46 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया। ज्यादातर को जयपुर और लखनऊ इत्यादि एयरपोर्ट पर उतारा गया।

सेरेंडिपिटी आर्ट महोत्सव में बिखरे कला के रंग

जेएनएन, पणजी

संगीत, नृत्य, दृश्य और चित्रकला के विभिन्न आयामों को समेटता सेरेंडिपिटी कला महोत्सव अब समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। पिछले सात दिनों से गोवा में जारी इस कला महोत्सव में पंद्रह सौ से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। विभिन्न क्षेत्रों के इन कलाकारों ने इस कला महोत्सव के दौरान अपने हुनर का प्रदर्शन किया।

इस प्रदर्शनी के दौरान कलाकारों ने उत्तर औपनिवेशिक काल की कला को भी अपनी रचनात्मकता में समेटने की कोशिश की है। इस फेस्टिवल के दौरान कविता पाठ से लेकर नाटकों के मंचन भी हुए। नाटक फोटो कॉपी में एक मजबूर परिवार की कहानी है जिसमें बड़े भाई के किरदार के माध्यम से परिवार के दर्द और संघर्ष को सामने लाया गया है। इसके अलावा तमिल लोकगीतों पर आधारित संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी हुआ जिसने गोवा के लोगों को सुदूर दक्षिण की लोक संस्कृति के दर्शन करवाए।

गोवा के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस कला महोत्सव में गीत संगीत का कार्यक्रम तो हुआ ही इसमें भारतीय संगीत परंपरा पर

तमिल लोक कला का प्रदर्शन करते कलाकार। सौ. सरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल

बातचीत भी की गई। इस बातचीत में ये बात उभर कर सामने आई कि भारतीय कला लगातार अपने को मांजती रहती है और उसने समय के साथ अपना विकास भी किया। कला की समकालीनता के अलग अलग आयामों पर भी चर्चा हुई। सरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल के दौरान लगाई गई चित्र प्रदर्शनियों को भी लोगों ने पसंद किया।

दुष्कर्म के प्रयास का केस होने पर पिता ने ही मारी थी युवती को गोली

जागरण टीम, सासाराम : बिहार के सासाराम स्थित राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के प्रयास का केस होने के बाद पिता ने अपनी बेटी को ही गोली मार दी थी। पुलिस ने कांड का पर्दाफाश करते हुए उसके पिता समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से दो बंदूक, छह दर्जन कारतूस, चाकू, खोखा समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। एसपी सत्यवीर सिंह ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने जांच के बाद स्वजन और अन्य का मोबाइल सर्विलांस पर रखा। इसके बाद बघैला थाना क्षेत्र के नोनिया टोला निवासी दुखन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में घटना से जुड़ी कई जानकारी हाथ लगीं। उसके पास से बरामद मोबाइल में युवती के पिता से हुई बातचीत की ऑटो रिकॉर्डिंग से घटना के संबंध में कई अहम जानकारी हासिल हुई।

एसपी ने कहा, लड़की के पिता को संझौली थाना क्षेत्र के चरपुरवा निवासी संजय चौधरी ने हथियार उपलब्ध कराया था, ताकि वह बेटी को मार सके। बातचीत में इसका खुलासा खुद पीड़िता के पिता ने किया है। उसके बाद छापेमारी कर संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक एकनाली बंदूक, एक दोनाली बंदूक, 67 कारतूस, दर्जनों खोखा व चाकू भी बरामद किया गया। उससे पूछताछ के बाद लड़की के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश के एक वर्ग और खासकर मुस्लिम तबके के बीच आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं के कैंपस से निकल अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जाने-माने मुस्लिम विद्वानों द्वारा यह भरोसा दिलाए जाने के बाद कि इस कानून से भारतीय मुस्लिमों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी, आंदोलन का हिंसक रूप अख्तियार करना एक बड़े भ्रम की ओर इशारा करता है। यह प्रवृत्ति बताती है कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए युवाओं को बरगला रहे हैं। ताज्जुब होता है कि ये वे युवा हैं जो शिक्षित हैं, जिन्हें भारतीय संविधान पर भरोसा है, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद की गरिमा और महिमा को बाखूबी जानते और बूझते हैं। जिन्हें पता है कि संवैधानिक पद पर आसीन कोई भी प्रधानमंत्री या गृहमंत्री अपने देश के नागरिकों को झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। ऐसा करते पाया जाने के बाद संविधान के तहत वह पद और प्रतिष्ठा के साथ बहुत कुछ गंवा सकता है। अगर हमारी संसद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने देश के मुस्लिमों को भरोसा दिलाया है तो वे बहकावे में क्यों आ रहे हैं? क्या भारतीय समरसता का ताना-बाना इतना कमजोर हो चुका है कि मुस्लिम समाज क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थी तत्वों के हाथ की कठपुतली बनने पर विवश हो जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष देश में हर नागरिक समान है। सबके अधिकार बराबर हैं। इन अधिकारों में कोई सरकार किसी तरह की कटौती नहीं कर सकती है। ऐसा करने पर न्यायपालिका आपकी सरपरस्ती करने को मौजूद है। आप इस देश के उतने ही श्रेष्ठ नागरिक हैं, जितना अन्य कोई। समय-समय पर यह बात आपने साबित भी की है। फिर काहे का डर। देश की गंगा-जमुनी तहजीब और संस्कृति को मजबूत करने के लिए डर को छोड़िए। भरोसा कीजिए। क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है।

शंकाओं के समाधान को उठें प्रभावी कदम

पिछले कई महीनों से भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीयता संशोधन कानून, जनगणना और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के नाम पर भ्रमित करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। उसी के नतीजे में अचानक देश भर में मुसलमान उत्तेजित होकर सड़कों पर आ गए हैं। असम में एनआरसी लागू होने के कुछ ही दिनों के भीतर भारतीय मुसलमानों को भ्रमित करने वाले वीडियो और ऑडियो संदेश भेजकर यह कहा जा रहा था कि सभी मुसलमान अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवाएं क्योंकि भारत सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिससे आप को विदेशी घोषित किया जा सकता है।

कई लोग ऐसे भी मैसेज भेज रहे थे कि असम की तर्ज पर पूरे देश में हिरासत केंद्र बनाये जा रहे हैं जिनमें उन लोगों को रखा जाएगा जो अपनी नागरिकता के दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाएंगे। उधर आम मुसलमान को न तो इस बात का पता था कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है और ना ही उनको यह मालूम था कि एनआरसी क्या बला है? इसलिए उनमें असंतोष फैलना स्वाभविक था। मुसलमानों को भेजे जा रहे संदेशों से सावधान रहने के लिए हमने उर्दू दैनिक इंकिलाब के माध्यम से लगातार यह बताने की कोशिश की, कि एनआरसी या सीएए का भारतीय मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहुत से लोगों ने लिखा भी इंकिलाब के कारण उनका नजरिया बड़ी हद तक बदला भी और वास्तविकता की उन्हें जानकारी हुई। दुःख की बात यह है कि सरकार की ओर से मुसलमानों को विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं की गई। भाजपा के नेताओं की तरफ से देश में नागरिकता कानून के बाद जल्द से जल्द एनआरसी लागू किये जाने की बात बार बार दोहराए जाने के कारण मुसलमानों का भय बढ़ता गया। लिहाजा गांव-गांव तथा जिले-जिले में अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र बनवाने वालों की भीड़ लग गई। इस परिस्थिति का ठगों और दलालों ने खूब फायदा उठाया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने शांति बनाये रखी और देश के किसी भी हिस्से में सीएए या एनआरसी के विरुद्ध कोई प्रदर्शन नहीं किया।

शकील शम्सी
संपादक, इंकिलाब

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमानों में फैले भ्रम को दूर करने के प्रयास किए जाएं और इस बात को प्रभावी तरीके से साफ किया जाए कि सीएए किसी विशेष वर्ग के विरुद्ध नहीं है।

शायद इसकी एक वजह यह थी की मुस्लिम समुदाय को यह बात समझ में आ रही थी कि इन दोनों प्रावधानों से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। क्या यह बात सराहनीय नहीं है कि देश भर के मुसलमान नागरिकता संशोधन अधिनियिम के संसद में पारित होने से पहले तक पूरी तरह खामोश रहे, लेकिन जैसे ही असम में प्रदर्शन शुरू हुए वैसे ही मुसलमानों के सब्र का बांध टूट गया और वह भी खुल कर इस का विरोध करने लगे । सबसे अहम बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए आम मुसलमानों ने ना तो उलेमा को साथ लिया और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लिया बल्कि बिना किसी नेतृत्व के भीड़ निकल पड़ी। वह बात अलग है कि अब कुछ राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शनों को हाई जैक करने की कोशिश में लगे है।

बहरहाल बदलते हुए हालात और मुसलमानों के आक्रोश को समझते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कई उर्दू दैनिकों में एक विज्ञापन देकर एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं उनको दूर करने की कोशिश की। इसके माध्यम से सरकार ने इस बात को साफ किया कि आम नागरिकों को एनआरसी में साधारण दस्तावेज ही चाहिए होंगे। लेकिन यह सब इतनी देर से किया गया कि एनआरसी और सीएए के विरोध ने देशव्यापी रंग अख्तियार कर लिया। कई जगह हिंसा भी फैल गई है। अगर यही काम पहले हुआ होता तो शायद तस्वीर दूसरी होती। विरोधाभासी बयान भी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। गुरुवार को सरकार ने कहा कि एनआरसी देशभर में अभी लागू नहीं होगा। भविष्य में जब लागू होगा तो उसके दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। मगर शाम को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जल्द ही एनआरसी को देशभर में लागू किया जाएगा। हमें नहीं लगता कि ऐसे विरोधाभासी बयान आने से मुसलमानों की चिंताए दूर होंगी। उम्मीद है कि गृहमंत्री अमित शाह ने क्रिसमस के बाद सीएए में कुछ परिवर्तन करने की जो बात कही है उस पर विचार करते समय वह मुस्लिम समुदाय की शंकाओं का निदान करने का काम भी करेंगे।

सच बनाम मिथ्या

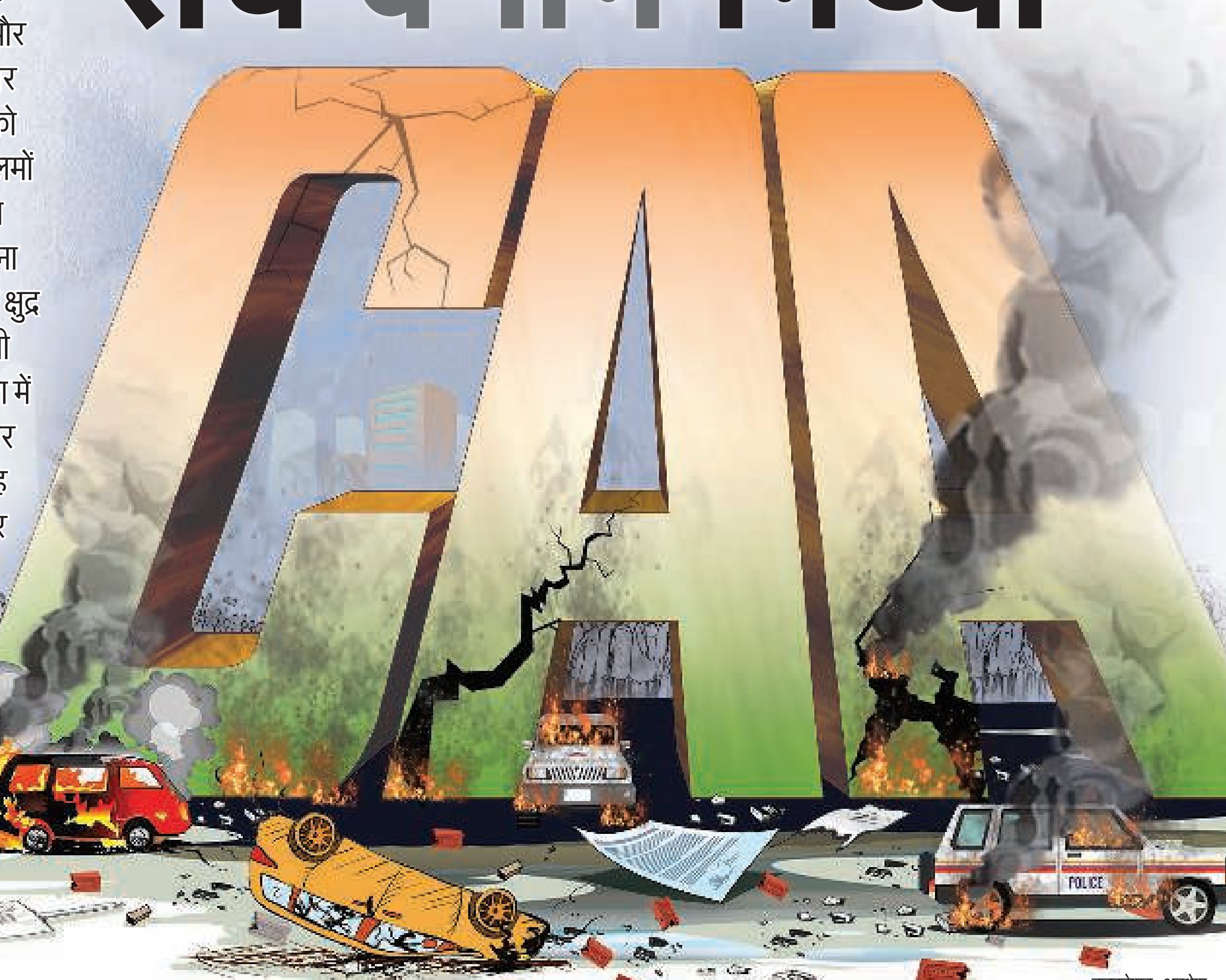

इलस्ट्रेशन : अवधेश

हर सवाल का जवाब

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। विरोध करने वाले सीएए को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का पूर्व कदम मान रहे हैं। इस बीच सरकार ने अपनी बात रखी है और उन भ्रमों को दूर करने की कोशिश की है, जिसमें इस कानून को एक धर्म विशेष के प्रति भेदभाव करने वाला बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने लोगों को भ्रमित करने वाले 13 सवालों के जवाब दिए हैं, जिनके जरिए अफवाहों को बल देकर लोगों को भड़काया जा रहा है।

- **क्या सीएए में ही एनआरसी निहित है?**

ऐसा नहीं है। सीएए अलग कानून है और एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। सीएए संसद से पारित होने के बाद देशभर में लागू हो चुका है, जबकि देश के लिए एनआरसी के नियम व प्रक्रिया तय होने अभी बाकी हैं। असम में जो एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और असम समझौते के तहत की गई है।

- **क्या भारतीय मुसलमानों को सीएए और एनआरसी को लेकर किसी प्रकार परेशान होने की जरूरत है?**

किसी भी धर्म को मानने वाले भारतीय नागरिक को सीएए या एनआरसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है।

- **क्या एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगा?**

बिल्कुल नहीं। इसका किसी भी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। यह नागरिकों का केवल एक रजिस्टर है, जिसमें देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना होगा।

- **क्या एनआरसी में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा?**

नहीं, एनआरसी किसी धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जब एनआरसी लागू किया जाएगा, वह न तो धर्म के आधार पर लागू किया जाएगा और न ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है। किसी को भी सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि वह किसी विशेष धर्म को मानने वाला है।

- **क्या एनआरसी के जरिये मुस्लिमों से भारतीय होने का सबूत मांगा जाएगा?**

सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी जैसी कोई औपचारिक पहल शुरू नहीं हुई है। सरकार ने न तो कोई आधिकारिक घोषणा की है और न ही इसके लिए नियम कानून बने हैं। भविष्य में अगर ये लागू किया जाता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि किसी से उसकी भारतीयता का प्रमाण मांगा जाएगा।

एनआरसी को आप एक प्रकार से आधार कार्ड या किसी दूसरे पहचान पत्र जैसी प्रक्रिया से समझ सकते हैं। नागरिकता रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपना कोई भी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज देना होगा, जैसा कि आप आधार कार्ड या मतदाता सूची के लिए देते हैं।

- **नागरिकता कैसे दी जाती है? क्या प्रक्रिया सरकार के हाथ में होगी?**

नागरिकता नियम 2009 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय की जाएगी। ये नियम नागरिकता कानून, 1955 के आधार पर बना है। यह नियम सार्वजनिक रूप से सबके सामने हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक बनने के पांच तरीके हैं।

1. जन्म के आधार पर नागरिकता
2. वंश के आधार पर नागरिकता
3. पंजीकरण के आधार पर नागरिकता
4. देशीयकरण के आधार पर नागरिकता
5. भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता

- **जब एनआरसी लागू होगा, तो क्या हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता-पिता के जन्म का विवरण उपलब्ध कराना होगा?**

आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म की तारीख, माह, वर्ष और स्थान के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त होगा। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने माता-पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता-पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी। जन्म की तारीख और जन्मस्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर भी निर्णय होना बाकी है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को शामिल करने की संभावना है। इन दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की संभावना है, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशानी न उठानी पड़े।

- **अगर एनआरसी लागू होता है तो क्या मुझे 1971 से पहले की वंशावली को साबित करना होगा?**

ऐसा नहीं है। 1971 के पहले की वंशावली के लिए आपको किसी प्रकार के पहचान पत्र या माता-पिता/पूर्वजों के जन्म प्रमाण पत्र जैसे किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। यह केवल असम एनआरसी के लिए मान्य था, वो भी 'असम समझौता' और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर। देश के बाकी हिस्सों के लिए नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र का मामला) नियम, 2003 के तहत एनआरसी की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है।

- **अगर पहचान साबित करना इतना ही आसान है तो फिर असम में 19 लाख लोग कैसे एनआरसी से बाहर हो गए?**

असम की समस्या को पूरे देश से जोड़ना ठीक नहीं है। वहां घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके विरोध में वहां 6 वर्षों तक आंदोलन चला है। इस घुसपैठ की वजह से राजीव गांधी सरकार को 1985 में एक समझौता करना पड़ा था। इसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च, 1971 कट ऑफ डेट माना गया, जो एनआरसी का आधार बना।

- **क्या एनआरसी के लिए मुश्किल और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिन्हें जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा?**

पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत ही सामान्य दस्तावेज की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की घोषणा होती है तो उसके लिए सरकार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। सरकार की यह मंशा नहीं हो सकती कि वह अपने नागरिकों को परेशान करे या किसी को दिक्कत में डाले।

- **अगर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है और उसके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा?**

इस मामले में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत देंगे। साथ ही अन्य सबूतों और कम्युनिटी वेरिफिकेशन आदि की भी अनुमति देंगे। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक को अनुचित परेशानी में नहीं डाला जाएगा।

- **भारत में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिनके पास घर नहीं हैं, गरीब हैं और पढ़े-लिखे और उनके पास पहचान का कोई आधार भी नहीं है, ऐसे लोगों का क्या होगा?**

यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसे लोग किसी न किसी आधार पर ही वोट डालते हैं और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उसी के आधार पर उनकी पहचान स्थापित हो जाएगी।

- **क्या एनआरसी किसी ट्रांसजेंडर, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला और भूमिहीन लोगों को बाहर करता है, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं।**

नहीं, एनआरसी जब कभी भी लागू किया जाएगा, ऊपर बताए गए किसी भी समूह को प्रभावित नहीं करेगा।

सियासी रुख-रवैया

भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आसानी से संसद के दोनों सदनों से नागरिक संशोधन विधेयक को पारित करा लिया। खासकर तब जब राज्यसभा में भाजपा बहुमत में नहीं है। हालांकि एक ही सप्ताह में कई पार्टियों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। इसी को सियासत कहते हैं। जन उबाल को बड़े वोटबैंक में देख रहे इन सियासी दलों का विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टियों के इस रुख-रवैये पर एक नजर:

भाजपा
करीब डेढ़ दर्जन राज्यों में सत्तासीन भाजपा ने सुनिश्चित किया कि नागरिकता संशोधन कानून पंडित नेहरू के वक्त से केंद्र सरकार की नीति में रहा है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि सीएए को लेकर किसी भी भारतीय मुस्लिम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आक्रोशित लोगों का भरोसा जीतने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की कमी को दूर नहीं किया जा सका।

कांग्रेस
छात्र संगठन एनएसयूआइ हर प्रदर्शन का हिस्सा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जामिया में पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर आयोजित धरने में कुछ घंटों के लिए शामिल हुई। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से छह महीने पहले अपनी छवि एक शिवभक्त की बनाने की कोशिश की थी। यह विरोध मुस्लिम समर्थक के रूप में देखा जा सकता है और यह बैकफायर कर सकता है। वर्तमान में मुस्लिम बहुल सीट से सांसद होने के चलते पहले से ही बैकफुट पर हैं।

तृणमूल
ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री थीं, जिन्होंने यह घोषणा की कि वह सीएए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। न सिर्फ सीएए बल्कि ममता बनर्जी ने मनमोहन सरकार के वक्त 2010 में शुरू की गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है। ममता ने सीएए को भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने धर्म के आधार पर सभी को समान सुरक्षा देने की मांग की है। यह उनके पिछले रुख में एक बदलाव है, जब वह बंगाल में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के पक्ष में थीं।

शिवसेना
शिवसेना ने भाजपा के साथ अपने 35 साल पुराने गठबंधन को खत्म कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जहां भाजपा बहुमत में है, लेकिन बाद में राज्यसभा में उसने मतदान से दूरी बनाई।

एजीपी, बीजेडी और जेडीयू
इन पार्टियों ने विधेयक को पास कराने के लिए संसद में मतदान किया लेकिन बाद में मन बदल लिया। अब एजीपी नए कानून के खिलाफ है और उसने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाल रखी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने गलती होने की बात कही।

एआइएमआइएम
ओवैसी ने संसद में बहस के दौरान इस विधेयक की प्रति को फाड़ दिया था, वे सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान नहीं दिखाई दिए।

वामदल
वाममोर्चा विरोध के खुलकर समर्थन में आया है।

बेखौफ रहें मुसलमान

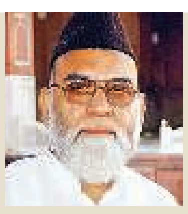

सैयद अहमद बुखारी
शाही इमाम, जामा मस्जिद

नागरिकता कानून का भारत में रहने वाले मुस्लिमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका असर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों पर पड़ेगा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी में फर्क है।

प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस दौरान संयम बरता जाना चाहिए और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी अहम है। नागरिकता कानून का भारत में रहने वाले मुस्लिमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका असर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शरणार्थियों पर पड़ेगा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी में फर्क है। एक नागरिकता संशोधन एक्ट है जो कि कानून बन चुका है और दूसरा एनआरसी है, जिसका अभी एलान ही किया गया है। नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता नहीं ले पाएंगे। इसका भारत में रहने वाले मुस्लिमों से कोई लेना-देना नहीं।

अभी जब नमाज हो रही थी तो मैंने देखा कि एक तरफ नमाज हो रही थी दूसरी तरफ पीछे से नारे लग रहे थे। हम एक मकसद को लेकर यहां एकत्र हुए हैं। जब तक बुनियादी चीजों को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे कामयाब होंगे। कोई भी तहरीर तब तक सफल नहीं होती जब तक कि जिम्मेदारों को ना जोड़ा जाए। मैंने सुना है कि दुकानें बंद कराई जा रही है। पहले बैठकें होती थी, जिसमें इलाके के मौलाना, पार्षद, विधायक समेत आम लोग शामिल होते थे। कौन दायें चलेगा, कौन बायें चलेगा, से लेकर कौन उपद्रवी लोगों को कार्यक्रम में शामिल ना होने देने की निगरानी करेगा, यह बैठकों में तय किया जाता था। लेकिन आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन संयमित होना चाहिए। 70 साल हो गए मुल्क में अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए। हमने कुर्बानियां भी दीं लेकिन हक नहीं मिला। हर सियासी जुबान ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, वादे किए और सत्ता हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद हमसे मुंह फेर लिया। ऐसा कोई भी सियासी दल नहीं है, जिसने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया हो। मैंने इस कानून को लेकर कई लोगों से बात की। अधिकतर को पता ही नहीं कि यह कानून किस बारे में है। कई ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। यह समझना होगा कि कानून में नागरिकता की बात हो रही है। लेकिन युवाओं को यह डर है कि उन्हें हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा। हकीकत में नागरिकता कानून एनआरसी से अलग है और भारत के मुसलमानों से संबंधित नहीं है।

जनमत

हां 95% | 05% नहीं

क्या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय मुस्लिम समाज का तथाकथित भय भ्रम की उपज है?

हां 90% | 10% नहीं

क्या दुनिया की दूसरी सर्वाधिक भारतीय मुस्लिम आबादी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बहुधा आसान निशाना बनती है?

आपकी आवाज

नागरिकता बिल को लेकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहें हैं। इससे माहौल में ऐसी नौबत आ रही है जिससे लोग भाईचारे की राह को छोड़कर नफरत की राह पकड़ रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। **जमील**

राजनीतिक नेतृत्व का स्वार्थ और भ्रम ही मुस्लिम समाज को असलियत से दूर ले गया है। शिक्षित वर्ग को इस बिल का अध्ययन करके सार्थक बहस और मुद्दे को सरकार के सामने रखना चाहिए था। **अमन कुमार**

इस कानून के विरोध करने कि तब जरूरत थी, जब इस कानून के तहत किसी धर्म विशेष के लोगों को देश से जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रावधान होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर बार-बार जब यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि यह कानून किसी भी धर्म के लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं है, फिर क्यों इस पर बेवजह का हो-हल्ला किया जा रहा है। **राजेश कुमार चौहान**

गंदी राजनीति व पूर्वाग्रह की वजह से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है। विरोधी इस कानून से मुस्लिम समाज के भयभीत होने एवं उसे भयभीत करने वाली भ्रामक बातें कर रहे हैं। जिससे संशय उपज रहा है। **गौरीशंकर**

असलियत को समझना होगा

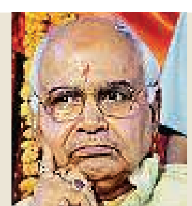

हृदयनारायण दीक्षित
विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

घुसपैठियों की पहचान राष्ट्र का कर्तव्य है। हिंसा, आगजनी के प्रायोजक देश के अभियुक्त हैं। भारतीय मुसलमान राष्ट्र के सम्मानीय अंगभूत हैं। विश्वास है कि वे असलियत समझेंगे।

भारत में ऋग्वैदिक काल से ही भिन्न विचार व विश्वास वाले समूह आनंदमगन रहते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि भिन्न भिन्न धार्मिक समूहों व भिन्न भाषा बोलने वाले जनसमूह यहां पृथ्वी माता की कृपा से रहते हैं। आस्था या विश्वास के आधार पर यहां कभी कोई भेद नहीं किया गया लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए भिन्न राष्ट्र की जरूरत बताई। ब्रिटिश सत्ता और तत्कालीन अग्रणी कांग्रेस नेतृत्व ने धर्म आधारित विभाजन स्वीकार किया। भारी रक्तपात हुआ। धर्म आधारित नागरिकता की शुरुआत भारत विभाजन के समय हुई। विभाजन के पहले भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं था। धर्म आधारित विभाजन के बावजूद भारत ने सबको नागरिकता दी। यहां कोई भेद नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान ने इस्लाम को राजधर्म बनाया। इस तरह पाकिस्तान में हिंदू, पारसी, सिख आदि अल्पसंख्यक हो गए। वे पाकिस्तान में असुरक्षित और उत्पीड़ित हुए। पं. नेहरू के समय ही पाकिस्तानी हिंदू व सिखों को नागरिकता मिली। श्रीलंका के तमिलों को भी नागरिकता दी गई।

भारत का मन मानवीय संवेदना से भरापूरा है। ताजे नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश के पंथ आधारित पीड़ितों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। भारत के किसी भी संप्रदाय के किसी भी नागरिक से इस कानून का कोई संबंध नहीं है। मोदी विरोधी राजनीति ने अल्पसंख्यक मुसलमानों में हमेशा भय बनाए रखने का निंदनीय कृत्य किया है। वे राष्ट्रवाद को मुस्लिम विरोधी बताकर डराते रहे हैं और उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। वे झूठ प्रचारित कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। छह गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों ने इस कानून को अपने राज्यों में न लागू करने की असंवैधानिक चुनौती दी है। संविधान की 7वीं अनुसूची की केंद्रीय सूची पर संसद द्वारा पारित कानून लागू करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। ये संविधान की दुहाई देते हुए संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब नागरिकता संशोधन कानून के साथ नागरिकता रजिस्टर के सवालों का भी घालमेल किया जा रहा है। राष्ट्र के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आग लगाने व हिंसा फैलाने की कार्रवाई क्या राष्ट्र राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं है। मौलिक अधिकार भी लोकव्यवस्था की सीमा में हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकार अंतरराष्ट्रीय संविदा (1966) का अनुच्छेद 27 पठनीय है कि 'अल्पसंख्यकों को अपने समूह के सदस्यों के साथ स्वयं की संस्कृति का आनंद लेने, अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।' भारत के अल्पसंख्यकों को ऐसे अधिकार भारतीय संविधान ने 1949 में ही दे दिए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ऐसे सुस्पष्ट संवैधानिक अधिकार नहीं हैं। इसीलिए इस नए कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। घुसपैठिए और शरणार्थी में भेद है। सर्वोच्च न्यायालय ने घुसपैठ को देश पर आक्रमण बताया था।

दैनिक जागरण
ईमानदारी उत्थान का मार्ग है

संपर्क-संवाद में देरी

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भाजपा ने एक अभियान शुरू करने का जो फैसला किया वह देर से उठाया गया कदम ही दिखता है। इस अभियान के तहत अगले दस दिनों में तीन करोड़ परिवारों से मिलकर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में बताया जाएगा और साथ ही जगह-जगह प्रेस कांफ्रेंस भी की जाएंगी। कायदे से यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। पार्टी के साथ मोदी सरकार को भी आम जनता से संपर्क-संवाद की जरूरत तभी समझ लेनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता कानून पर व्यापक प्रचार-प्रसार की दरकार है। समझना कठिन है कि नागरिकता कानून पर विपक्ष के तीखे विरोध के बाद भी सत्तापक्ष यह क्यों नहीं भांप सका कि उसे आम जनता के बीच भी वैसी ही सक्रियता दिखाने की जरूरत है जैसी उसने नागरिकता संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाते वक्त संसद में दिखाई? लगता है कि उसने इस विधेयक पर संसद की मुहर लगते ही यह मान लिया कि अब इस मसले पर कुछ कहने-बताने और खासकर विरोध कर रहे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि सत्तापक्ष यह भी नहीं समझ सका कि नागरिकता संशोधन कानून के साथ प्रस्तावित एनआरसी को लेकर जनता के बीच किस तरह भ्रम फैलाकर उसे गुमराह करने के साथ उकसाया भी जा रहा है? यह काम विपक्षी नेताओं की ओर से तो किया ही जा रहा, वामपंथी रुझान वाले बुद्धिजीवियों और फिल्म जगत के लोगों की ओर से भी किया जा रहा। इस काम में मीडिया के एक हिस्से की भी भूमिका है। इसी कारण विरोध के नाम पर अराजकता का खुला प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उसे बेशर्मी के साथ सही भी ठहराया जा रहा है। उन्माद भरे उपद्रव का सिलसिला भी इसीलिए कायम है। यह ढोंग की पराकाष्ठा ही है कि पागलपन भरी हिंसा में रेलवे की करीब 90 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो जाने, विभिन्न राज्यों में तीन सौ से अधिक पुलिस वालों के लहूलुहान होने और सैकड़ों वाहन फूंके जाने के बाद भी यह राग अलापा जा रहा है कि हम तो शांति के साथ अपना विरोध कर रहे हैं। अभी तक करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है और फिर भी गांधी, आंबेडकर, संविधान, लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। यह छल-छद्म के अलावा और कुछ नहीं। हैरानी है कि जब सरकार इस सबके बारे में जान रही थी कि लोगों को भ्रमित और भयभीत किया जा रहा है तब फिर उसकी ओर से आम लोगों तक पहुंचने का काम समय रहते क्यों नहीं किया गया?

नशे का मकड़जाल

कई अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी नशे की विषबेल खूब पनप रही है। नशे के सौदागरों की सक्रियता परेशान कर रही हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें यह स्वाभाविक है। खासकर, युवा पीढ़ी का नशे की गिरफ्त में आना खतरनाक संकेत है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऊधम सिंह नगर और हल्द्वानी के साथ ही पर्वतीय जिलों के कस्बों तक में नशे के सौदागरों का नेटवर्क सामने आया है। आए दिन यहां नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी जा रही है। पुलिस यह कहकर बचाव की मुद्रा में दिखती है कि वह नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन अहम सवाल अपनी जगह कायम है कि बावजूद इसके तस्करों का नेटवर्क कैसे फैलता जा रहा है। आलम यह कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और आवासीय कॉलोनियों तक तस्करों की पहुंच बन गई है। यह भी कह सकते हैं ये सब इलाके तस्करों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। पैडलरों के जरिये तस्कर स्कूली बच्चों को नशे का आदी बना रहे हैं। पूरे परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो यह बात साफ हो रही कि पुलिस शहरों में नशीले पदार्थ बेचने वालों को तो पकड़ रही है, लेकिन असल तस्करों तक पहुंच ही नहीं रही है। पैडलरों तक नशीले पदार्थ कौन पहुंचा रहा है और किस माध्यम से पहुंच रहा है, इसकी पड़ताल के दावे होते जरूर हैं, पर ठोस परिणाम सामने नहीं आते। शायद यही वजह है कि पैडलरों के गिरफ्त में आने के बाद तस्कर आसानी से नया नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं। इन्हीं के जरिये तस्कर बेधड़क नशीले पदार्थों की खेप उत्तराखंड के विभिन्न शहरों को पहुंचा रहे हैं। स्थिति कितनी विकट होती जा रही है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड उन सात राज्यों में शुमार है, जो नशे को लेकर न केवल चिंतित हैं, बल्कि इससे निपटने के लिए साझा रणनीति बना रहे हैं। हाल में ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसी मसले पर सातों राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने मंथन किया। उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ और हिमाचल प्रदेश इसमें शरीक हुए थे। अच्छी बात यह कि इन सभी राज्यों की चुनौतियां कमोबेश एक सी हैं, ऐसे में तस्करों पर नकेल डालने के लिए अब जो रणनीति बनी है, उससे सकारात्मक परिणाम आने के उम्मीद की जानी चाहिए। यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि साझा बैठक में जो कुछ तय हुआ, उस पर अमल के लिए ईमानदार प्रयासों की जरूरत है।

नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता की पहल को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। शिक्षण संस्थाओं को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए

अराजकता फैलाने वाली राजनीति

संजय गुप्त

नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर लोगों को बरगलाने-भड़काने वाली राजनीति देश को शर्मिंदा करने वाली है

राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य कई शहरों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से धरने-प्रदर्शन के साथ बड़े पैमाने पर आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले की घटनाएं हो रही हैं वे गंभीर चिंता का विषय हैं। इसलिए और भी, क्योंकि अराजक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यह अंदेशा बढ़ रहा है कि इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो समाज में टकराव की स्थिति बन सकती है। नागरिकता कानून के विरोध में धरना-प्रदर्शन के साथ हिंसक घटनाओं के बढ़ते जाने के बाद भी नेताओं, कलाकारों और मीडिया के एक हिस्से के लोग नागरिकता कानून के हिंसक विरोध की या तो अनदेखी कर रहे या फिर उसे जायज ठहरा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी मसले का विरोध हो सकता है। हर मसले पर लोगों को अपनी बात कहने-रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के नाम पर हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता और उस हिंसा को तो बिल्कुल भी नहीं जिसमें सरकारी-गैर सरकारी संपत्ति जलाई जा रही हो और पुलिस को निशाना बनाया जा रहा हो।

यह हर दिन साफ हो रहा है कि नागरिकता कानून का विरोध करने उतरे तमाम लोगों को यही नहीं पता कि यह कानून किसके लिए है और उसका देश के किसी भी नागरिक से कोई मतलब नहीं, भले ही वह चाहे जिस पंथ का हो। इस अज्ञानता से तमाम सेलेब्रिटी कहे जाने वाल लोग भी ग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, उनके पास हर सवाल के जवाब में एक कुतर्क है। इन्हीं कुतर्कों से लैस लोग धरना-प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। इनमें तमाम तो बहकाकर या फिर भाड़े पर लाए जा रहे हैं। उन्हीं के बीच अराजक तत्व हिंसा फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार की घटनाएं खास तौर पर यही बता रही हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन धरना-प्रदर्शन करने वाले उनका बचाव कर रहे हैं। अराजक विरोध से पल्ला झाड़ कर वे खुद को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी करार दे रहे हैं और हिंसा के लिए पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। यह अंध विरोध की अति है।

हालांकि सरकार बार-बार कह रही है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय मुसलमान का अहित नहीं होने जा रहा है, फिर भी यह अफवाह सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही है कि यह कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है। इसी के साथ शरारतपूर्ण तरीके से यह भी जोड़ा जा रहा कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी के जरिये धर्म के आधार पर पहचान की जाएगी और ऐसा करते समय मुस्लिम नागरिकों को घुसपैठिया बता दिया जाएगा। ऐसा शरारत भरा दुष्प्रचार तब किया जा रहा जब एनआरसी की प्रक्रिया और उसके नियम तय किए जाने शेष हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित एनआरसी असम में लागू एनआरसी से अलग होगा, लेकिन उसे असम जैसा ही बताने की होड़ मची है। आम जनमानस को भयभीत करने के लिए यहां तक कहा जा रहा है कि लोगों और खासकर भारत के मुसलमानों को खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। सरकार ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को एनआरसी को लेकर आशंकित होने की जरुरत नहीं है, लेकिन नेताओं का एक वर्ग एनआरसी पर सरकार को घेरने के लिए लगातार समाज में भ्रम फैला रहा है। एनआरसी को एक हौवे का रूप तब दिया जा रहा है जबकि दुनिया का हर देश अपने नागरिकों का रजिस्टर तैयार करता है। सरकार अपनी इसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की प्रतिबद्धता जता रही है, लेकिन उसे इस रूप में पेश किया जा रहा जैसे सरकार कोई नया और गैर जरूरी काम कर रही हो। ध्यान रहे आजादी के बाद 1951 में जनगणना के बाद पहला एनआरसी तैयार किया गया था।

हर देश अपने नागरिकों के लिए कुछ अलग नियम बनाता है और शरणार्थियों के लिए अलग। वे शरणार्थियों को नागरिकता भी प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ नियमों और शर्तों के साथ। असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों को राहत देने की बात समय-समय पर तमाम दलों के नेता करते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। खुद मनमोहन सिंह ने 2003 में वाजपेयी सरकार से यह मांग की थी कि बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी चाहिए। यह मांग उन्होंने राज्यसभा में नेता विपक्ष के रूप में की थी। उनका यहां तक कहना था कि बांगलादेश जैसे देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के मामले में हमें उदारता दिखानी चाहिए, क्योंकि यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है। क्या यह अजीब नहीं कि जिसे 2003 में नैतिक दायित्व बताया जा रहा था वह 2019 में अनावश्यक काम करार दिया जा रहा है? यह भी ध्यान रहे कि कुछ इसी तरह की मांग माकपा नेता प्रकाश कारत ने तब की थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। करात ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह भी याद दिलाया था कि इस बारे में नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने क्या कहा था? अब जब ऐसा ही किया गया तो एक तूफान सा खड़ा कर दिया गया। आखिर इस नतीजे पर क्यों न पहुंचा जाए कि नागरिकता कानून का विरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और लोगों को जानबूझकर बरगलाया जा रहा है? आज मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस भी यह भूलना पसंद कर रही है कि बांग्लादेश से पलायन करके आए अल्पसंख्यकों को लेकर उसकी क्या मांग थी? क्या वह एक दिखावटी मांग थी और इसीलिए दस साल तक संप्रग सरकार ने बांग्लादेशी शरणार्थियों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया? कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि असम में एनआरसी तैयार करने का काम उस समझौते के तहत किया गया जो राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते समय वहां के नेताओं से किया था। कम से कम असम से राज्यसभा सदस्य रहे मनमोहन सिंह तो इस सबसे भली तरह परिचित ही होंगे। किसी मसले पर वोट बैंक की राजनीति नई नहीं है, लेकिन नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर तो देश को शर्मिंदा करने वाली अराजक राजनीति की जा रही है। सोनिया गांधी नागरिकता कानून के विरोधियों के साथ खड़ी होना पसंद कर रही हैं, लेकिन शांति की अपील करना जरूरी नहीं समझ रहीं।

अवधेश राजपूत

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल नागरिकता कानून को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो उसके फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? वे इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या संसद से पारित कानून को खारिज करना संविधान और लोकतंत्रसम्मत है? आखिर जब सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून की संवैधानिकता की परख करने को तैयार है तो फिर अनावश्यक धरना-प्रदर्शन और हिंसा के जरिये देश को अशांति की आग में क्यों झोंका जा रहा है?

response@jagran.com

धरने-प्रदर्शन का प्रशिक्षण

हास्य-व्यंग्य

अब मुझे पता चला कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा झोल है और वह यह कि मार्केट में जिस टाइप का रोजगार सबसे ज्यादा होता है, उसका कायदे का कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में होता ही नहीं है। जैसे इन दिनों फिर विरोध-प्रदर्शन की बहार आई हुई है, लेकिन उसके गुर सिखाने वाला कोई पाठ्यक्रम ही नहीं। जिस तरह बारात में आया हर बाराती नागिन नृत्य नहीं कर सकता उसी तरह हर प्रदर्शनोत्सुक व्यक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रदर्शन एक कला है। आगजनी, गाड़ियां रोकना, आंसू गैस के गोले फेंके जाने पर सांस रोककर खड़े रहना और भयंकर सर्दी में भी वाटर कैनन के आगे सीना तानकर खड़े होने में एक्सपर्टीज की भी दरकार होती है। पहली बार प्रदर्शन कर रहा व्यक्ति इतना योग्य नहीं होता कि पुलिस से सीधे पंगा ले सके। चूंकि ऐसा कोई कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में संचालित नहीं हो रहा, इसलिए प्रदर्शन के पूर्व अनुभवों के आधार पर कुछ बिंदुओं पर प्रदर्शनोत्सुकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसे प्रदर्शनकारी बनने का क्रैश कोर्स भी कहा जा सकता है।

इसका पहला सबक यही है कि यदि आप नए-नए प्रदर्शनकारी हैं तो कृपया बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर प्रदर्शन करें, क्योंकि असली उपद्रवी और दंगाई अक्सर तोड़फोड़-हंगामा और आगजनी के बाद मौका-ए-वारदात से रफूचक्कर हो जाते हैं और पुलिस के हत्थे आप जैसे नए रंगरूट लग जाते हैं। पुलिस नए-पुराने चावलों की कुटाई में कोई अंतर नहीं करती। दूसरे सबक में समझ लें कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन सिर्फ टीवी कैमरों के सामने तुर्रम खां बनने के लिए होता है। इसमें तमाम प्रदर्शनकारियों को पता ही नहीं होता कि वे जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वह वास्तव में है क्या? अगर नागरिकता कानून के विरोधी प्रदर्शनकारियों से इस पर सवाल करेंगे तो 90 फीसद नहीं बता पाएंगे कि यह क्या है? वे सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं,क्योंकि उनके साथी कर रहे हैं या फिर उन्हें खुद को सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी दिखाने वाली तस्वीर लगानी है। तीसरे सबक में गांठ बांध लें कि आपकी पत्थरबाजी आपके साथियों का भी मुंह तोड़ सकती है।

पीयूष पांडे

यदि आप नए, पुराने या फिर आदतन प्रदर्शनकारी हैं तो यह जरूर समझें कि किस मुद्दे पर और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं?

चौथा सबक यही होगा कि टेलीविजन चैनल के कैमरों के सामने आते ही किस मुद्रा में कितने डेसिबल में नारे लगाने हैं, ये सिर्फ एक्सपर्ट प्रदर्शनकारी ही जानता है। इसलिए प्रदर्शन के दौरान हमेशा चिल्लाते रहकर गले पर बोझ नहीं डालना चाहिए। केवल कैमरा सामने आते ही भीड़ से आगे निकलकर चिल्लाने की कोशिश करें। पांचवा सबक यही कि प्रदर्शन की योजना से पहले अच्छे से खा-पी लें, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान कई बार काफी भागना दौड़ना पड़ता है, जिसमें काफी कैलोरी नष्ट होती है। कुछ मौकों पर पुलिस की धरपकड़ के बाद प्रदर्शनकारी को थाने में घंटों बैठना भी पड़ता है।

छठा सबक यही कि हंगामेबाजी के दौरान पुलिस पकड़ ले तो घबराएं नहीं। पहले हाथ जोड़कर माफी मांगें और खुद को बेकसूर बताएं। पुलिसवाले नहीं मानें तो पहला डंडा पड़ते ही जमीन पर गिर जाएं और पैरों को पेट की तरफ मोड़कर गुड़ीमुडी हो जाएं। अब सातवां सबक समझ लें कि अगर आप ट्रेनी प्रदर्शनकारी हैं या बिना कुछ जाने-समझे प्रदर्शन करने आ गए हैं तो यह जान लें कि तोड़फोड़ आगजनी करने पर भी आप संविधान, लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो अपनी फजीहत ही कराएंगे। थाना-कचहरी के चक्कर अलग से लगाएंगे।

आठवां सबक यही रहेगा कि यदि आप छात्र हैं तो भी प्रदर्शन सीखें। पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी और एक बार क्लास में फेल भी हो गए तो कोई नहीं। प्रदर्शन में एक्सपर्टीज आपको राजनीति में भी दूर तक ले जा सकती है। आपको शायद मालूम न हो, लेकिन हर नेता पर प्रदर्शन के पांच-दस केस तो दर्ज हैं ही, जिन्हें वह झूठा बताता है। नौवें सबक के तहत प्रदर्शन से पहले एक्टिंग की छोटी वर्कशॉप कर सकें तो और भी बेहतर इससे आपके प्रदर्शन में भावप्रवणता बढ़ेगी। और अंत में दसवां एवं अंतिम सबक यह कि प्रदर्शन आपका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन को दंगा न बनाएं, क्योंकि दंगाई को गोली लगने पर किसी को अफसोस नहीं होता।

response@jagran.com

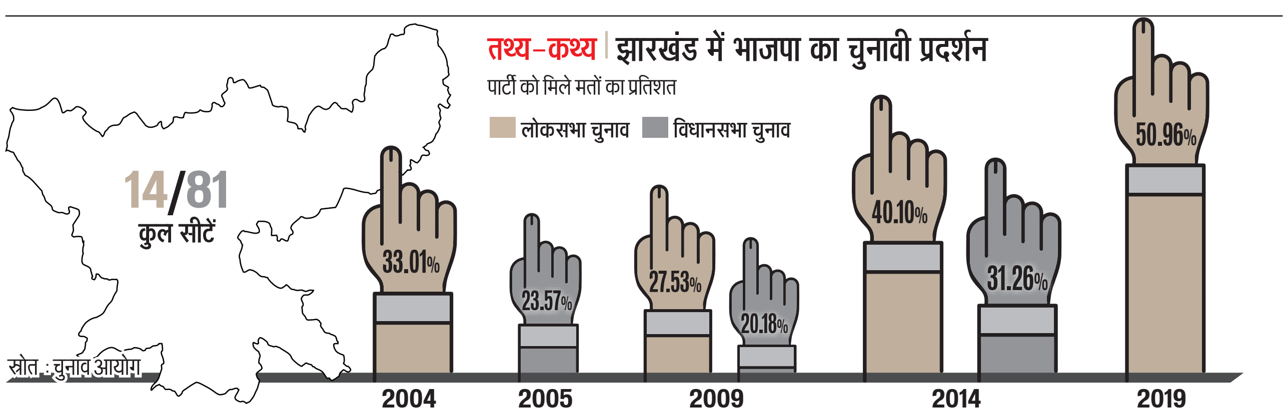

ऊर्जा

मानव धर्म

वर्तमान भौतिक युग में यदि मनुष्य ने मनुष्य के साथ सद्व्यवहार नहीं सीखा तो भविष्य में इसकी भारी क्षति उठानी होगी। आज मूल्यों से रहित शिक्षा मनुष्य को मानवता के बजाय दानवता की ओर लिए जा रही है। मानवता मनुष्य का धर्म है। मानव धर्म सभी मनुष्यों के साथ स्नेह भाव का मूल मर्म समझाता है। जाति, संप्रदाय, वर्ण, धर्म और देश आदि के विभिन्न भेदभावों के लिए यहां कोई स्थान नहीं। मानव धर्म का आदर्श एवं इसकी मनोभूमि अत्यंत ऊंची है तथा इसके पालन में मानव जीवन की वास्तविकता निहित है। मानव धर्म सभ्यता एवं संस्कृति की रीढ़ सदृश है। इसके बिना सभ्यता-संस्कृति का विकास असंभव है। मानव धर्म की वास्तविकता एवं उपादेयता इसी में है कि मनुष्यत्व के विकास के साथ ही विश्व भर के लोग सुख, शांति और प्रेम भाव से रहें। प्राणिमात्र में रहने वाली आत्मा उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है। प्रत्येक में एक ही जगतनियंता प्रभु का प्रतिबिंब झलकता है, यह समझकर प्रत्येक मनुष्य की ओर आदरभाव बनाए रखें। ऐसा करके ही सभी तरह के आदर्श मूल्यों का विकास संभव है।

मानव धर्म का आध्यत्मिकता तथा नैतिकता से महत्वपूर्ण संबंध है। यदि कोई मानव सदाचारी नहीं है। चारित्रिक एवं नैतिक आदर्शों में उसकी आस्था नहीं। ईश्वरीय सत्ता में भी उसका लेशमात्र विश्वास नहीं और इनके अतिरिक्त सौजन्य, सहृदयता, सात्विकता, सरलता, परोपकारिता आदि सद्गुण उसमें नहीं हैं तब यह स्वीकार करना होगा कि अभी उसने मानव धर्म का स्वर-व्यंजन भी नहीं सीखा है। वास्तव में मानव-धर्म के विनाश हेतु मानव ने चहुंओर स्वार्थवश एक संकीर्ण घेरा बना रखा है जिसके बाहर वह निकल नहीं पाता। वहीं उसे तोड़े बिना, उससे बाहर निकले बिना कोई भी मानव मानवतावादी नहीं बन सकता। अतः अपने हृदय को परमोदार तथा सरल बनाने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए प्रेम पयोधि में स्नान परमापेक्षित है जो अत्यंत आनंद की अनुभूति भी कराएगा।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

कोशिकाओं को लेकर बड़ी कामयाबी

मुकुल व्यास

यह खोज अल्जाइमर, स्नायु तंत्र और हृदयाघात के इलाज में प्रभावी उपकरण बनाने में खासी मददगार साबित हो सकती है

वैज्ञानिकों ने ऐसी स्नायु कोशिकाएं विकसित की हैं जो वास्तविक कोशिकाओं जैसा व्यवहार करती हैं। यह अपने तरह की पहली उपलब्धि है। इससे हृदयाघात, अल्जाइमर और स्नायु तंत्र की बीमारियों में उपचार के लिए चिकित्सा उपकरण बनाए जा सकते हैं। सिलिकॉन चिप पर निर्मित ये कृत्रिम स्नायु कोशिकाएं जैविक स्नायु कोशिकाओं की तरह काम करते हुए बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं। उन्हें एक माइक्रोप्रोसेसर के महज एक अरबवें हिस्से के बराबर ऊर्जा चाहिए। इससे ये मेडिकल इंप्लांट और दूसरे जैविक-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इन स्नायु कोशिकाओं का विकास यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ के नेतृत्व में ब्रिस्टल, ज्यूरिख और ऑकलैंड विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने किया है।

उन्होंने स्नायु कोशिकाओं का ब्योरा 'नेचर' पत्रिका में दिया है। स्नायु तंत्र के विद्युतीय संकेतों का पालन करने वाली कुदरती स्नायु कोशिकाओं की तरह काम करने वाली कृत्रिम स्नायु कोशिकाओं का विकास चिकित्सा विज्ञान का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रहा है जिसमें वैज्ञानिक लंबे समय से जुटे हैं। नई सफलता के बाद ऐसी बीमारियों के इलाज की उम्मीदें जगी हैं जहां स्नायु कोशिकाएं उपयुक्त ढंग से काम नहीं करतीं या स्पाइनल कॉर्ड में चोट की वजह से उनकी प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है अथवा वे मृत हो चुकी हैं। कृत्रिम स्नायु कोशिकाएं कुदरती कोशिकाओं के कार्य को दोहराकर रुग्ण जैविक सर्किट की मरम्मत कर सकती हैं। हृदयाघात के मामले में मस्तिष्क के तल स्थित स्नायु कोशिकाएं स्नायु तंत्र के फीडबैक का उपयुक्त जवाब नहीं देतीं जिसकी वजह से वे दिल को सही संकेत नहीं भेज पाती हैं। ऐसे सही संकेतों के अभाव में दिल अपेक्षित तेजी से पंपिंग नहीं कर पाता और हृदयाघात हो जाता है।

बहरहाल जीव विज्ञान की जटिल चुनौतियों और अनिश्चित स्नायु प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायु कोशिकाओं का विकास एक बड़ी चुनौती थी। शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन चिप विकसित करने के बाद यह सिद्ध किया कि उनकी कृत्रिम स्नायु कोशिकाएं विद्युत संकेतों का जवाब देने के मामले में वास्तविक स्नायु कोशिकाओं की हूबहू नकल करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर एलेन नॉगरेट ने इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि अभी तक स्नायु कोशिकाएं ब्लैक बॉक्स जैसी थीं, अब हम इस ब्लैक बॉक्स को खोलकर उसके भीतर झांकने में सफल रहे हैं। हमारा शोध इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने वास्तविक स्नायु कोशिकाओं के विद्युतीय गुणों को उनकी बारीकियों के साथ दोहराने की उपयुक्त विधि बताई है। कृत्रिम कोशिकाओं को सिर्फ 140 नैनोवाट्स की दरकार होती है।

इस कारण ये असाध्य रोगों के इलाज में प्रयुक्त होने वाले बायो-इलेक्ट्रॉनिक इंप्लांट्स के लिए मुफीद हैं। प्रो. नॉगरेट का कहना है कि वे ऐसे स्मार्ट पेसमेकर विकसित कर रहे हैं जो न केवल हृदय को सतत रूप से सटीक तरीके से पंपिंग के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि हृदय की जरूरतों पर कार्रवाई के लिए इन कृत्रिम स्नायु कोशिकाओं का इस्तेमाल भी करेंगे।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

बैरंग वापसी...

राजनीति में अक्सर दूसरों की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में एक विधायक के साथ हुआ। विधानसभा में नहीं बोलने देने के विरोध में कई विधायकों का समर्थन और उनके साथ धरने पर बैठना उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचा गया। हुआ यूं कि इस घटना के बाद एक दिन मुख्यमंत्री ने कई विधायकों को मिलने के लिए बुलाया। वहां ये विधायक जी भी पहुंचे, लेकिन मुलाकात के इंतजार में बैठे-बैठे जब काफी समय बीत गया तो उन्होंने दरख्वास्त की। इन्हें बताया गया कि आपको तो बुलाया ही नहीं गया था। नतीजतन उन्हें वहां से बैरंग लौटने की नौबत आ गई। हालांकि पता चला कि कुछ समय बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए समय दे ही दिया।

बाइट के लिए कुछ भी...

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा राजनीति में आने से पहले कई वर्षों तक उद्योग चैंबर फिक्की के महासचिव रहे हैं। अपने तब के कार्यकाल में उन्हें इस बात के लिए जाना जाता था कि अर्थ से जुड़ा कोई भी मामला हो तो वह मीडिया में आने का रास्ता निकाल ही लेते थे। वित्त मंत्री बनने के बाद भी उनकी यह आदत बनी हुई है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जब वह बाहर निकले तो तुरंत प्रतीक्षारत मीडिया के पास पहुंचे और कई आर्थिक मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। ऐसा लगा कि बंद कमरे में हो रही बैठक में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों को जमकर सुनाया होगा, लेकिन भीतर से आए अधिकारियों और दूसरे वित्त मंत्री मीडिया के सामने उनके रुख को देखकर अचंभित थे, क्योंकि उनके मुताबिक बैठक में तो वह बहुत ही शांत बैठे थे। किसी भी मुद्दे पर आक्रामक नहीं थे, लेकिन बाहर आते ही उनके तेवर एकदम बदल गए।

जारी है धींगामुश्ती

कृषि भवन स्थित एक मंत्रालय में अफसरों की धींगामुश्ती के चलते वहां कामकाज प्रभावित होने लगा है। नियम कानून के पचड़े में कामकाज रुक गया है। इसमें बड़े साहब की सुस्ती भी इसे और हवा दे रही है। लिहाजा कई अहम मसलों पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस बाबत चिट्ठियों के आदान-प्रदान के चक्कर में फाइलों का बोझ लगातार भारी होता जा रहा है। एक ही मंत्रालय के दो विभागों के आला अफसरों के बीच ठनी हुई है। दोनों साहब एक दूसरे के कामकाज में टांग अड़ाने से गुरेज नहीं करते। नियमों का हवाला देकर एक साहब ने तो बड़े साहब तक अपनी फरियाद लगा दी है, लेकिन अभी तक वहां भी सुनवाई नहीं हो पाई है। लिहाजा कई बड़े फैसले अटके हुए हैं। मंत्रालय में चौतरफा आवाज उठ रही है कि भला है कोई ऐसा महारथी जो इन अफसरों में संघर्षविराम करा सके।

कुर्सी-कुर्सी का फेर

कुर्सी के मोह से अफसरों के जकड़े होने के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जब ट्रांसफर आदेश जारी होने की खबर मिलते ही अफसर ने कुर्सी छोड़ दी हो। पिछले दिनों शास्त्री भवन में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब पढाई-लिखाई से जुड़े मंत्रालय के बड़े साहब ने ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत अपने सहयोगी को बुलाकर चार्ज दे दिया और नई जगह पर आमद दर्ज करा दी। बड़े साहब ने यह सब इतनी जल्दबाजी में तब किया, जब वह लंबे समय से महकमे के सर्वेसर्वा थे। इसके लिए वह और कुछ समय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में आनन-फानन उन्होने जिस तरह से कुर्सी छोड़ी, उसे लेकर शास्त्री भवन के गलियारों में चर्चा शुरू हो जाना स्वाभाविक ही था। बताया तो यह भी जा रहा है कि साहब को जिस ऑफिस में भेजा गया है, वह काफी भाग्यशाली है। उसी ऑफिस में और उसी कुर्सी पर बैठने वाली अफसर को हाल ही में एक राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। तभी से यह सीट खाली थी।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

365 वादों को 365 दिनों में पूरा करने का दावा किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में।

आजकल

पुरस्कार प्रक्रिया से प्रपंच बेनकाब

अनंत विजय

साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संबंध में विवाद अक्सर सामने आते रहे हैं। हालांकि इनके कारण अलग-अलग रहे हैं, लेकिन पुरस्कार की प्रक्रिया पर जब सवाल खड़े किए जाएं तो पहले हमें इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। वैसे इन पुरस्कारों के संदर्भ में वर्षों तक राजनीति भी होती रही है जिनका कई बार एक कालखंड के बाद अर्थ भी बदलता गया है, जिससे कई बार कई लेखकों ने फायदा भी उठाया है

शशि थरूर

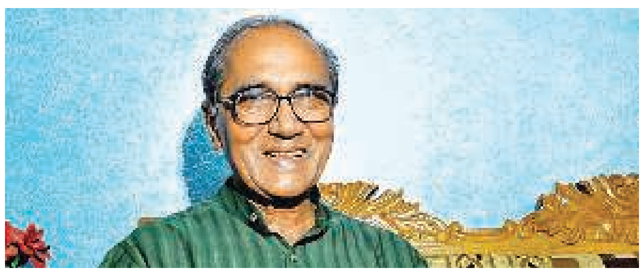

नंद भारद्वाज

देश भर को साहित्य अकादमी पुरस्कारों का इंतजार रहता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं, इस वर्ष भी हुआ। मैथिली भाषा के संयोजक प्रेम मोहन मिश्र ने इस्तीफा का मेल भेजकर विवाद को हवा देने की कोशिश की। मिश्र को पुरस्कार की प्रक्रिया से परेशानी थी। खबरों के मुताबिक प्रेम मोहन मिश्र ने अकादमी को जो पत्र भेजा उसमें पुरस्कार देने की लिए जूरी के गठन पर सवाल उठाते हुए वहां एक 'रैकेट' के सक्रिय होने का आरोप जड़ा। उनका आरोप है कि इस बार जूरी के सदस्यों का नाम पहले ही सार्वजनिक हो गया और यह भी सबको पता था कि इस वर्ष का पुरस्कार किसको दिया जाएगा। उनकी मांग है कि जूरी के चयन और पुरस्कार की प्रक्रिया गोपनीय होनी चाहिए। अभी तक की प्रक्रिया के मुताबिक हर भाषा के प्रतिनिधि ही जूरी के सदस्यों का नाम प्रस्तावित करते हैं। जब नई आम सभा का गठन होता है तो सभी सदस्यों को पत्र भेजा जाता है और उनसे आधार सूची बनाने के लिए, प्राथमिक सूची पर विचार करने के लिए और फिर अंतिम जूरी के सदस्यों के लिए संभावित लोगों के नाम मांगे जाते हैं। इन सबसे एक विस्तृत सूची तैयार की जाती है। इसी सूची से पांच वर्ष तक हर प्रकार की जूरी का चयन किया जाता है।

इसके बाद अध्यक्ष के सामने जूरी के सदस्यों का नाम रखने के पहले ये जांच लिया जाता है कि कोई भी नाम पिछले वर्ष के दौरान तो जूरी का सदस्य नामित नहीं हुआ। नियम यह है कि एक बार जो व्यक्ति जूरी का सदस्य नामित हो जाता है उसे अगले साल नामित नहीं किया जाता है। इस जांच पड़ताल के बाद जो भी नाम अध्यक्ष के सामने आते हैं, उसमें से वह तीन का चयन करते हैं जो वर्ष और भाषा विशेष की जूरी में शामिल होते हैं। अगर साहित्य अकादमी में नियमानुसार जूरी के सदस्यों का चयन किया गया है तो प्रेम मोहन मिश्र भी उसके सहभागी माने जा सकते हैं, क्योंकि नाम तो उन्होंने भी प्रस्तावित किया होगा। मिश्र जी के हवाले से जो खबर छपी है उसके मुताबिक उन्होंने दस दिसंबर को पहली बार आपत्ति की। दस दिसंबर को आपत्ति का अर्थ इस वजह से नहीं रह जाता है कि तब तक पुरस्कार का काम लगभग पूरा हो चुका था। अंतिम चयन पर विचार बाकी रह गया था।

मिश्र का एक आरोप पुरस्कार के रैकेट का भी है। इस तरह का रैकेट वामपंथियों के दबदबे वाले काल में सक्रिय रहता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से ऐसी बात सामने नहीं आई हैं। उस वक्त महीनों पहले से साहित्य जगत को पता होता था कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको दिया जाना है। इस स्तंभ में कई बार इसकी चर्चा भी हो चुकी है और बता भी दिया गया था कि किसको पुरस्कार मिलनेवाला है, उसको ही मिलता भी था।

राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के अलावा वामपंथी बुद्धिजीवी भी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार संस्थाओं को नष्ट कर रही है। उसकी परंपराओं को भंग कर रही है और स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन इस बार साहित्य अकादमी में एक ऐसी घटना हुई जो कांग्रेस और वामपंथियों के इन आरोपों को नकारने के लिए काफी है। इस वर्ष अंग्रेजी के लिए कांग्रेस के तिरुअनंतपुरम से सांसद और लेखक शशि थरूर को उनकी पुस्तक 'एन एरा ऑफ डार्कनेस' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। अगर साहित्य अकादमी की स्वायत्तता को बाधित करने या उसको कमजोर करने की कोशिश होती तो क्या शशि थरूर को पुरस्कार के लिए चुना जाता? क्या साहित्य अकादमी के पिछले छह दशक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि विरोधी विचारधारा ही नहीं प्रमुख विपक्षी दल के सांसद को पुरस्कृत किया गया हो? संभवतः नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लेखकों की तो छोड़िए भारतीयता की बात करनेवाले लेखकों के नाम पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए विचार हुआ हो, ऐसा ज्ञात नहीं है। नरेंद्र कोहली के नाम पर कभी विचार भी हुआ। पाठकों को तय करना चाहिए कि असहिष्णु कौन है या अपनी विचारधारा को सृजनात्मकता पर थोपने की कोशिश किस विचारधारा के लोग करते हैं। प्रेम मोहन मिश्र को इन सब पर भी प्रकाश डालना चाहिए था।

पिछले सप्ताह के स्तंभ में इस बात की चर्चा की गई थी कि वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पुरस्कार वापसी का जो अभियान चला था उसमें शामिल उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अशोक वाजपेयी जैसे लेखक कैसे अकादमी पुरस्कारों को अपने परिचय में शान से शामिल करते हैं। इस बार इस तरह के लेखक और बेनकाब हो गए और इस बात को और बल मिला कि पुरस्कार वापसी अभियान ना केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था, बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर उनके राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए साहित्य का इस्तेमाल किया गया। लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के खिलाफ माहौल बनाना था। उनको अभिव्यक्ति की आजादी की ना तो चिंता थी और ना ही वो लेखकों पर हो रहे हमलों से व्यथित थे।

शशि थरूर को जिस जूरी ने पुरस्कार योग्य माना उसमें शामिल लेखकों के नाम देख लेते हैं। इससे कुछ और लोग बेनकाब होंगे। पहला नाम है जीएन देवी, दूसरा के सच्चिदानंदन और तीसरा है सुकांत चौधरी। जीएन देवी वही शख्स हैं जिन्होंने जोर-शोर से पुरस्कार वापस करने की घोषणा की थी और मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप जड़े थे। दूसरे शख्स हैं के सच्चिदानंदन जिन्होंने पुरस्कार तो वापस नहीं किया था, लेकिन उस वक्त अंग्रेजी की सलाहकार समिति से विरोधस्वरूप इस्तीफा दे दिया था। साहित्य अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी को एक ईमेल भेजकर विरोध जताया था और तिवारी को अहंकारी आदि कहा था। तब सच्चिदानंदन ने साहित्य अकादमी से भविष्य में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखने का ऐलान भी किया था। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद वो सब भूल गए और अकादमी से अपना संबंध बना लिया और इस वर्ष तो जूरी में भी शामिल रहे। अब यह समझ से परे है कि बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अभिव्यक्ति की आजादी कैसे बहाल हो गई और लेखक सुरक्षित कैसे हो गए। यदि दोनों चीजें हो गईं तो स्वीकार की घोषणा भी होनी चाहिए।

ये बात सिर्फ इन दोनों तक सीमित नहीं है, हिंदी की जूरी में रहे नंद भारद्वाज ने भी अपना पुरस्कार वापस किया था, लेकिन उनको भी अकादमी से कोई परहेज नहीं है। अकादमी के लोग बताते हैं कि नंद भारद्वाज ने चंद दिनों के बाद ही पुरस्कार वापसी का अपना फैसला चुपचाप वापस ले लिया था और अकादमी को भेजे चेक आदि भी वापस ले लिए थे। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सार्वजनिक घोषणा और सुर्खियां बटोर लेने के बाद अकादमी के कार्यक्रमों में चुपके से भागीदारी की यह कला पता नहीं कहां से सीखते हैं ये बौद्धिक। ऐसे ही कई और लेखक हैं जिनमें पंजाबी के सुरजीत पातर, अंग्रेजी के केकी एन दारूवाला, जिन्होंने पुरस्कार वापस किया था, लेकिन अब सक्रिय रूप से साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में भागीदार दिखते हैं। नैतिकता की मांग तो ये है कि इस तरह से सभी लेखक सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करें कि मोदी सरकार के उस दौर में लेखकों को डर लगता था, लेकिन अब मोदी सरकार के दौरान ही लेखकों का वो कथित डर समाप्त हो गया और अभिव्यक्ति की आजादी बहाल हो गई। क्या पुरस्कार वापसी करनेवाले इन लेखकों से इस नैतिकता की उम्मीद की जा सकती है? क्या इनमें इतना नैतिक साहस बचा है या यह मान लेना चाहिए कि लेखकों में जो नैतिक आभा होती है उसको स्वार्थ और लाभ-लोभ ने ढंक लिया।

साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है और लेखक समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि इसकी स्वायत्तता बरकरार रहे। यह तभी संभव है जब लेखक समुदाय इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाएं और यहां सृजन की ऐसी जमीन तैयार करें जहां रचनात्मकता की फसल लहलहा सके।

फिर से

पढ़ें, समझें, फिर करें विरोध

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें रामचंद्र गुहा और योगेंद्र यादव जैसे विद्वान भी हैं। ये विद्वान केवल सीएए का विरोध कर रहे हैं, विरोध के समर्थन में कोई तर्क नहीं दे रहे। ये केवल इतना कह रहे हैं कि यह संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि इन विद्वानों को सीएए के बारे में पता नहीं है। वे सब जानते हैं कि किसी भी देश का संविधान वहां के नागरिकों पर लागू होता है और यह अधिनियम विदेशी नागरिकों के लिए है। भारतीय नागरिक पूर्व की भांति स्वतंत्र हैं और यह अधिनियम उनके अधिकारों को किसी भी तरह से कम नहीं कर रहा है। इनमें मुस्लिम भी शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं उन पर सीएए लागू होता है।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव जरूरी है। सीएए भी उसी बदलाव का वाहक है जो गैर कानूनी ढंग से घुसपैठ करने वालों पर लगाम लगाएगा। किसी भी समुदाय के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए वर्तमान कानूनी प्रक्रिया 'प्राकृतिकरण' (नागरिकता अधिनियम की धारा छह) या पंजीकरण (नागरिकता अधिनियम की धारा पांच) का पालन करना होगा। सीएए इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करता। मुसलमान भी इन अधिनियमों के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अदनान सामी जैसे कई पाकिस्तानी भी भारत में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीएए लागू होने के बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। अदनान सामी ने पाकिस्तानी नागरिकता त्याग भारत की नागरिकता ग्रहण की है। जब वे भयभीत नहीं हैं तो जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों भयभीत हैं? इनको पता नहीं वे क्यों विरोध कर रहे हैं।

दरअसल सीएए 'शरणार्थियों' और 'घुसपैठियों' में अंतर स्पष्ट कर रहा है। 'शरणार्थी' किसी देश के शोषण-उत्पीड़न या जीवन जीने की न्यूनतम सुविधा के अभाव में किसी दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं, जबकि घुसपैठिये गलत कार्यों और तरीकों से दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन देशों में बड़ी तेजी से धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी घटी है। इन देशों से लोग धार्मिक शोषण से तंग आकर भारत में शरण लेने आते हैं। सीएए इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की पहल करता है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं। यहां इस्लाम धर्म को मानने वालों पर किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव का प्रश्न नहीं है। इसीलिए यहां से आने वाले

प्रतीकात्मक

मुसलमान किसी धार्मिक शोषण से तंग होकर नहीं, बल्कि घुसपैठियों के रूप में भारत आते हैं। सीएए इन्हीं लोगों को भारत आने से रोकेगा। जो मुसलमान भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं वे नागरिकता अधिनियम की धारा पांच और छह के तहत आवेदन कर सकते हैं।

भारत में नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीके हैं- भारत में जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से, प्राकृतिकरण (भारत में विस्तारित निवास) से और भारत में किसी क्षेत्र विशेष के शामिल होने से। इन पांच तरीकों से कोई मुसलमान भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आंदोलनकारियों से निवेदन है कि वे अधिनियम पढ़ें, विमर्श करें, फिर जरूरत महसूस करें तो शांतिपूर्ण आंदोलन करें। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है।

(प्रो. अरुण कुमार की फेसबुक वॉल से संपादित अंश, साभार)

ट्वीट-ट्वीट

मैं भी नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी के विरोध में हूं। मैं हिंदुत्व की विचारधारा का भी विरोधी हूं, पर धर्मनिरपेक्ष भारतीय व श्रद्धावान हिंदू होने के नाते मैं विरोध प्रदर्शन में पवित्र हिंदू प्रतीकों के खिलाफ आपत्तिजनक प्रयोगों के खिलाफ हूं। हिंदुओं से नफरत का पोस्टर थामने वाले सेक्युलरिस्टों से सावधान रहें।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर यह दस्तूर बन गया है कि इन्हें अंजाम देने वालों को यह कम जोखिम में अधिक फायदा दिलाने वाला लगने लगा है। अब इसे बदलना होगा ताकि हिंसक गतिविधियां इतनी जोखिम भरी हो जाएं कि उन्हें अंजाम देने वालों को उसके घातक नतीजे भुगतने पड़ें और वे भविष्य में इसका दुस्साहस न करें।
गौतम चिकरमाने@gchikermane

हर भारतीय का एक ही पहचान पत्र क्यों नहीं हो? जनगणना के समय ही नागरिकता क्यों तय नहीं हो सकती? करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर मतदाता सूची, आधार, राशन कार्ड आदि बनाने का क्या अर्थ है? यहां तक कि लोकसभा-विधानसभा के लिए अलग और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अलग मतदाता सूचियां क्यों?
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

आज देश को किस रजिस्टर की जरूरत है? एनआरसी- राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर? या फिर एनआरयू- राष्ट्रीय बेरोजगार रजिस्टर?
योगेंद्र यादव@_YogendraYadav

जागरण जनमत
कल का परिणाम

क्या नागरिकता संशोधन कानून का हिंसक विरोध राजनीतिक दुष्प्रचार का नतीजा है?

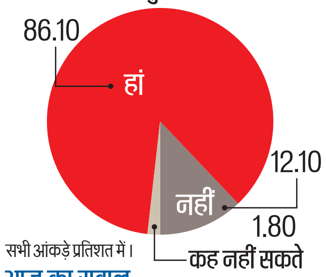

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अफवाहों के नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रतिबंध बेहतर होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y**, **N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जुम्मा-जुम्मा चार दिन हुए बने कानून,
बिला वजह कुछ सिरफिरे बहा रहे हैं खून।
बहा रहे हैं खून कर रहे पत्थरबाजी,
बजें पुलिस के लट्ठ तभी ये होते राजी।
राजनीति का खेल धर्म का ओढ़ मुलम्मा,
हैं करके पथराव कलंकित करते जुम्मा।
– ओमप्रकाश तिवारी

रचनाकर्म

विभिन्न लोकों में विचरण की अनुभूति

अमित तिवारी

मूलत: गुजरात में कच्छ के रन की यात्रा पर केंद्रित यह पुस्तक महज किसी क्षेत्र विशेष का यात्रा वृत्तांत होने का अनुभव नहीं देती है, बल्कि एक साथ कई लोकों में विचरण की अनुभूति कराती है...

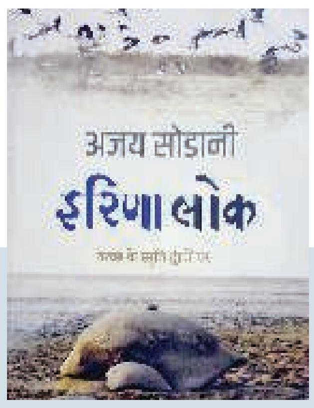

पुस्तक का नाम : इरिणा लोक
लेखक : अजय सोडानी
प्रकाशक : सार्थक, राजकमल प्रकाशन का उपक्रम
मूल्य : 299 रुपये

यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक आपको अपनी देखी जगहों की सैर पर ले जाता है। पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है कि मानो आप पड़ाव दर पड़ाव किसी सफर पर बढ़ रहे हैं। एक सधा हुआ लेखक अक्सर अपनी लेखनी से ऐसे जीवंत चित्र बना देता है कि आप उसके स्थान पर स्वयं को ही उस कथानक का मुख्य पात्र मान बैठते हैं। यात्रा-वृत्तांत के मामले में अजय सोडानी भी ऐसा ही नाम हैं। 'दर्रा दर्रा हिमालय' और 'दरकते हिमालय पर दर-ब-दर' जैसे यात्रा आख्यानों से उन्होंने पहले ही लोगों को अपनी शैली का चहेता बना लिया है। अब 'इरिणा लोक' इससे भी कुछ कदम आगे ले जाती है।

यह किताब मूलतः गुजरात में 'कच्छ के रन' की यात्रा पर केंद्रित है, लेकिन इसे पढ़ते हुए आप एक साथ कई लोकों में स्वयं को विचरण करता पाते हैं। यह आपके मानस की कई परतों को खोलती प्रतीत होती है। इसका कथानक एक ओर भौगोलिक रूप से अस्तित्वमान क्षेत्र के कोने-कोने से आपको परिचित कराता है, तो दूसरी ओर आपकी आत्मा एक अलग लोक में विचरण का आनंद ले रही होती है। हर पंक्ति के साथ आप कच्छ के स्मृति द्वीपों को अपने निकट अनुभव करते जाते हैं, तो साथ ही आपकी आत्मा स्वयं को गहरे कहीं ऐसी स्मृतियों में डूबा अनुभव करती है, जो आपके भीतर होकर भी आपकी अनुभूतियों से अछूती रह जाती हैं।

अजय सोडानी कहते हैं कि स्मृतियां उन्हें पुकारते हुए स्वयं ही इस सफर पर लेकर निकल पड़ी थीं। इस किताब में जिस इरिणा लोक की कथा मूल में है, उसमें कच्छ का रन (रण) तो समाहित है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। रन से मूलतः रेगिस्तान और रेत के टीलों का अनुभव होता है। इरिणा उससे व्यापक है। इरिणा में रन है, किंतु इरिणा केवल रन नहीं है। लेखक का कहना है कि कच्छ के संदर्भ में जिसे रन कहा जाता है, वह कुछ अधूरा अनुभव देता है। इरिणा में एशिया के वृहद घास के मैदानों में शुमार 'बन्नी' भी है। ऐसे में लेखक को इसे मात्र रन कहते संकोच होता है। जैसे-जैसे आप किताब के सफर पर आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे आपको स्वयं ही उस पूरे क्षेत्र को मात्र रन कहना अधूरा लगने लगता है। सच कहा जाए तो यही लेखक की उपलब्धि भी है।

नई दिल्ली स्थित एम्स से न्यूरोलॉजी में पढ़े अजय सोडानी इस समय सेम्स मेडिकल कॉलेज, इंदौर में तंत्रिका तंत्र विभाग के प्रोफेसर हैं। जिस तरह से एक-एक घटनाक्रम और शब्दों-भावों से वह आपके अंतर को छूते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आपके ही मस्तिष्क में बैठा अपनी बातों को दर्ज करता जा रहा है। किताब इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति और लोगों के संस्कारों से भी आपका साक्षात्कार कराती है। इन्हें पढ़कर समझ में आता है कि समाज में कितना कुछ है, जो कथित सभ्य और शहरी समाज की पहुंच से दूर है। विभिन्न लोककथाएं भी रह-रहकर आपको अतीत की सैर पर ले जाती हैं। कच्छ के द्वीपों की कथा आपकी स्मृति का हिस्सा बनती चली जाती है।

अजय सोडानी रास्ते, पड़ाव और मंजिल सबको बेहद करीने से सजाते हुए सामने रखते हैं। किताब की शुरुआत में मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर बढ़ते हुए एक रास्ते पर बटमारों से भय का जिक्र कुछ ऐसे होता है कि आपका स्वयं ही मन हो उठता है कि वहां से लेखक सपत्नीक सुरक्षित निकल जाएं। किताब में ऐसे ही कई घटनाक्रम हैं, जो आपको बांध लेते हैं। शब्दों का यह बंधन आपको अध्याय के आखिर तक खींचता चला जाता है। एक अध्याय पूरा होते ही आपको किसी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लेने का अनुभव होता है। स्मृतियों और वर्तमान से घटनाक्रमों का जुड़ता हुआ तार अनूठी अनुभूति प्रदान करता है। यदि आप कच्छ के द्वीपों की सैर करना चाहते हैं, तो निस्संदेह इस किताब को पढ़ना सहायक सिद्ध होगा। किताब आपको यह तय करने में भी सहायता करती है कि अगर कभी उस ओर जाना हो, तो आपको क्या-क्या देखना चाहिए। लेखन शैली और भाषायी समृद्धि के लिहाज से भी यह पुस्तक पठनीय बन पड़ी है।

पटना का स्वर्णिम अतीत

अजय कुमार राय

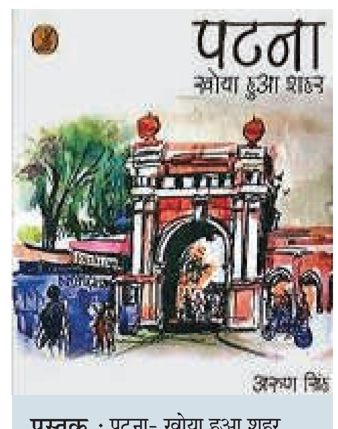

पुस्तक : पटना- खोया हुआ शहर
लेखक : अरुण सिंह
प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 595 रुपये

पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात प्राचीन पटना की स्थापना 490 ईसापूर्व में मगध सम्राट अजातशत्रु ने की थी। कालांतर में यह नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त व पाल साम्राज्यों की राजधानी बनी। पूर्व में इसे पाटलिग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद के नाम से भी जाता रहा है। माना जाता है पटना नाम पठान शासक शेरशाह सूरी की देन है। गंगा किनारे बसा पटना दुनिया के उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है, जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। अरुण कुमार की किताब 'पटना खोया हुआ शहर' पटना के ऐतिहासिक तथ्यों से आपको रूबरू करा रही है।

किताब के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अफगानिस्तान तक फैला था। मौर्यों के वक्त से ही विदेशी पर्यटक पटना आने लगे थे। तब पटना उत्पादन और व्यापार के केंद्र के रूप में देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जाना जाने लगा था। 17वीं सदी में पटना की शोहरत हिंदुस्तान के ऐसे शहर के रूप में हो गई थी, जिसके व्यापारिक संबंध यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे महादेशों के साथ थे। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया में पटना और उसके आसपास के इलाकों में अफीम, पॉटरी, चावल, सूती व रेशमी कपड़े, दरी और कालीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था।

यह पुस्तक लेखक के वर्षों के शोध का प्रतिफल प्रतीत होती है। इसके अध्याय छोटे, लेकिन कौतूहल पैदा करने वाले हैं। शीर्षक भी इसी तरह के हैं। जैसे-जब गुरुनानक पटना आए, मैनचेस्टर के बने कपड़ों से भी बढ़िया था पटना का कपड़ा, 19वीं सदी में अंग्रेजों ने पटना को नए सिरे से बसाया, खुदाबख्श ने पटनावासियों को दिया किताबों का नायाब तोहफा, यहीं संविधान पर हस्ताक्षर किए थे डॉ. सच्चिदानंद ने, पटना संग्रहालय कभी शेरशाह का किला था, एक वक्त पटना कॉलेज पूरब का कैंब्रिज था, पटना में बैंकिंग की शुरुआत गुजरी परिवार ने की थी, जब अकबर आया पटना आदि। लेखक ने ऐसी ढेरों घटनाओं के जरिये पटना के प्राचीन गौरव को उभारा है तथा पाठकों का उस दौर के सामाजिक- आर्थिक हालात से परिचय करवाया है।

मध्य प्रदेश डायरी

कमलनाथ के काम-काज का एक साल

आशीष व्यास
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश

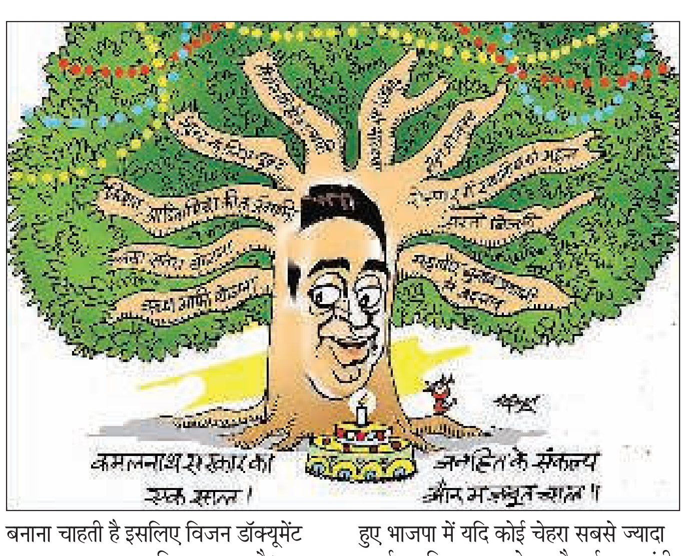

बीते शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। इसी के साथ पक्ष-विपक्ष के आरोप- प्रत्यारोप का शोर भी थम गया। लेकिन विधानसभा के इसी शीतकालीन सत्र में उछला एक जुमला रह-रहकर गूंज रहा है! आमतौर पर कम बोलने वाली अपनी छवि से इतर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है।' पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तत्काल जवाब दे दिया, 'हमने मुंह नहीं सरकार चलाई है।'

ऐसी ही जुमले-जुगाली और अल्पमत-अंतर्विरोध के साथ सत्ता स्वीकार करने वाली कमलनाथ सरकार एक वर्ष पूरा कर चुकी है। इस अवसर को विशेष बनाते हुए राजधानी भोपाल में कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। मुख्य समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 'विजन-टू-डिलेवरी रोडमैप 2020-25 डॉक्यूमेंट' जारी किया। साथ ही यह दावा भी किया कि हमने 365 दिन में 365 वादे पूरे किए हैं। प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर संतुष्टि व सहमति जताते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने माना कि कमलनाथ को विषम परिस्थितियों में प्रदेश का कार्यभार मिला था, लेकिन फिर भी हर वचन पूरा किया गया। जय किसान फसल ऋण माफी योजना, नया सवेरा योजना प्रदेश की जन हितैषी योजनाएं साबित हुईं। सरकार की निवेश संबंधी योजनाओं को प्रमाण पत्र देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने 'मैग्नीफिसेंट एमपी' की भी सराहना की। विजन डॉक्यूमेंट 2020-25 को सुनियोजित और फोकस्ड बताते हुए वे यह कहने से भी नहीं झिझके कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उससे प्रदेश में जल्द ही नए निवेश आएंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

बहुत स्वाभाविक है कि कांग्रेस की शीर्ष राजनीतिक पंक्ति से मिला यह प्रोत्साहन प्रदेश सरकार के उत्साह में वृद्धि करेगा। शायद यही वजह है कि अपना रोड मैप दिखाते-समझाते हुए मुख्यमंत्री ने दावों-वादों की अगली किस्त जनता के सामने रख दी। भाजपा के तमाम आरोपों के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ यह कहने से भी नहीं चूके कि प्रदेश सरकार अब किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। चूंकि कांग्रेस सरकार आने वाले वर्षों में प्रदेश को आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध बनाना चाहती है इसलिए विजन डॉक्यूमेंट 2020-25 पर काम किया जा रहा है। विरोधियों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।

यह तो हुई सरकार की बात। अब यह भी समझने की जरूरत है कि विपक्ष के तौर पर भाजपा की भूमिका पिछले एक साल में कैसी रही। धरना, प्रदर्शन और आंदोलनों के जरिये सरकार की नीति-नीयत पर सवाल उठाते हुए भाजपा में यदि कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, तो वह है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश पर पुरानी पकड़ और मुद्दों की जड़ तक जाने में माहिर शिवराज सिंह ने सरकार के एक साल पूरा होने पर फिर अलग अंदाज में अपनी बात रखी। एक बार फिर खुद को टाइगर बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि 'टाइगर अभी जिंदा है।' यहां यह जरूर याद रखा जाना चाहिए कि 13 वर्षों तक मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने वाले इस नेता ने मुख्यमंत्री निवास को खाली करने से पहले लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, 'टाइगर अभी जिंदा है।' यह सत्ता छिनने का दर्द हो या खुद को अपदस्थ नहीं मानने की जिद, शिवराज सिंह चौहान बीते साल भर में सरकार से मोर्चा लड़ाते रहे हैं। भाजपा के दूसरे खेमे में खड़े नेता भी यह मानते हैं कि शिवराज सिंह ने पूरी सक्रियता से प्रदेश के दौरे किए, इससे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में वे आज भी स्वीकार किए जाते हैं। मसला चाहे कर्ज माफी का हो, बाढ़ से फसलों के बर्बाद होने का हो, राहत राशि का हो या फिर यूरिया संकट पर चल रही सियासी बहस का, शिवराज सिंह हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर ही लेते हैं। वैसे भाजपा के पास इस बात का जवाब नहीं है कि तमाम परेशानियों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कुछ काम ऐसे कर लिए हैं, जो वह अपनी उपलब्धि के रूप में बार-बार दर्ज करवा रही है। जैसे- खस्ता वित्तीय हालात और केंद्र में विपरीत विचारधारा की सरकार होने के बावजूद किसान और आदिवासियों की कर्ज माफी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निवेश के लिए मैग्नीफिसेंट एमपी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और कमजोर रूप से आर्थिक वर्ग को 10 फीसद आरक्षण, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, उद्योगों में 70 फीसद रोजगार में स्थानीय लोगों की अनिवार्यता, इंदौर और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत, महापौर चुनाव प्रणाली में बदलाव। बहरहाल, एक वर्ष की इस यात्रा में कांग्रेस इस बात को लेकर तो संतोष व्यक्त कर सकती है कि अस्थिरता की अटकलों को उसने अब विराम दे दिया है।

कोर्ट के पाले में हनीट्रैप मामला : बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। 390 पन्नों के चालान में आठ आरोपित हैं, इनमें से छह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और 57 लोगों को गवाह भी बनाया है। चालान के साथ पुलिस ने जांच में जब्त मोबाइल, नकदी, मोबाइल के स्क्रीन शॉट, निजी डायरियां, एग्रीमेंट, वॉइस रिकॉर्डिंग, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में ऑडियो-वीडियो सहित अन्य सबूतों का कच्चा-चिट्ठा भी पेश किया है। इसी के साथ अब यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, नए-नए नाम और अनेक नए तथ्य सामने आ सकते हैं। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि यह जांच कितनी ईमानदारी से चलेगी? क्योंकि इस हाइ प्रोफाइल हनीट्रैप में जो नाम तेजी से चर्चा में आए थे, वे अब धीरे-धीरे गुम होने लगे हैं!

1010 लोगों को सितंबर 2019 में विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा बोर्डिंग (विमान में यात्रा) से वंचित रखा गया। इसके एवज में कंपनियों ने यात्रियों को 39.29 लाख का मुआवजा दिया गया। वहीं अक्टूबर 2019 में 1,102 यात्री बोर्डिंग से वंचित रहे, जिसके एवज में 47.32 लाख का मुआवजा दिया गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 22 दिसंबर 2019

बदलती तस्वीर

अगले साल नए वर्जन में मोटेरा

वरुण आनंद, नई दिल्ली

कभी 53 हजार दर्शक क्षमता वाला अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम 2020 में 1.10 लाख दर्शकों को मैच का साक्षी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी के साथ क्रिकेट की दुनिया में बादशाहत रखने वाले भारत के नाम इस खेल से जुड़ा एक और कीर्तिमान दर्ज होगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। एक नजर पुराने स्टेडियम के इतिहास और नए की सुविधाओं पर...

गुजरात के अहमदाबाद में इन दिनों ऐतिहासिक सरदार पटेल स्टेडियम के नवीनीकरण का काम तेजी से चल रहा है। (फाइल) प्रेट्र

2018 में गुजरात की धरती पर देश ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। वह था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा। 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।' दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित होने के बाद अब 2020 में पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर उसी गुजरात की जमीं की तरफ होंगी। खासकर खेल प्रेमियों की। वजह है अहमदाबाद में तैयार हो रहा ऐतिहासिक सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। पुराने स्टेडियम को विकसित करने के लिए जनवरी 2017 में आधारशिला रखी गई थी, हालांकि काम 2015 में शुरू हो गया था। तब से इसका नवीनीकरण जारी है। 90 फीसद से अधिक काम पूरा हो चुका है और संभावना जताई जा रही है कि अगले साल मार्च में यह तैयार हो जाएगा।

छिन जाएगा मेलबर्न का ताज : कल्पना कीजिए, जब 1.10 लाख क्रिकेट प्रशंसकों से खचाखच भरे स्टेडियम में इंडिया... इंडिया... की गूंज सुनाई देगी तो भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और हौसला कितने चरम पर होगा। जी हां, यही इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता होगी, जो पुराने स्टेडियम की क्षमता (53 हजार) से दोगुना से भी अधिक होगी। इसी के साथ मोटेरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के सर्वाधिक दर्शक क्षमता के ताज को भी अपने नाम कर लेगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1,00,024 दर्शक एक साथ मैच का आनंद ले सकते हैं। एक समय था जब कोलकाता के ईडन गार्डेंस को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता था, जिसमें कई मौकों पर एक लाख से ज्यादा दर्शक मैच के साक्षी बने। हालांकि, आधिकारिक रूप से यह कीर्तिमान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम ही रहा क्योंकि ईडन गार्डेंस में बैठने वाले दर्शकों की कभी सटीक गिनती नहीं हो सकी। 2006 में ईडन गार्डेंस को रेनोवेट किया गया तो यहां एक स्वीमिंग पूल, प्रेस सेंटर आदि बनाए गए। इसके बाद यहां सीटों की संख्या 94 हजार से घटकर 68 हजार हो गई।

कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह : इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि क्रिकेट की दुनिया का यह कीर्तिमान भी गुजरात की उसी धरती पर बनने जा रहा है, जिस पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही एक संयोग यह भी है कि दोनों का संबंध देश को एकता के सूत्र में पिरोहने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल से है। एक ओर जहां उनकी विशाल मूर्ति दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है, वहीं अब यह स्टेडियम विश्वभर के क्रिकेट प्रेमियों को इतनी बड़ी संख्या में मैचों का साक्षी बनने का मौका देगा। हालांकि, 1983 में बनकर तैयार हुआ पुराना स्टेडियम कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह रह चुका है। 2014 तक यहां 12 टेस्ट और 24 एकदिवसीय मैच खेले गए, जिनमें 2006 की आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप 2011 के मैच भी शामिल हैं। इन्हीं में शामिल रहा सात मार्च, 1983 को पाकिस्तान के खिलाफ वह मैच जिसमें सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। इसके बाद आठ फरवरी, 1994 को कपिल देव ने इसी मैदान पर जब अपना 432वां विकेट लिया तो रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर के उस दोहरे शतक को शायद ही कोई खेल प्रशंसक भुला पाए, जब उन्होंने अपनी खराब फॉर्म से बाहर निकलते हुए बल्ला आकाश की ओर उठाया था। यह उनका पहला दोहरा शतक था। अब वही क्रिकेट ग्राउंड नए रूप-रंग और दर्शकों की बढ़ी हुई क्षमता के साथ जल्द ही कई और मैचों का होस्ट बनने के लिए तैयार होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में जब यह बनकर तैयार होगा, तब एशिया इलेवन और वर्ल्ड इलेवन के बीच उद्घाटन मैच यहां आयोजित कराया जाएगा।

ऐसा होगा नया स्टेडियम

पूरी तरह तैयार होने के बाद 63 एकड़ में फैला यह स्टेडियम कई सुविधाओं से लैस होगा। इसमें तीन हजार कारों और 10 हजार दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके समीप दो प्रैक्टिस ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड, एक ओलंपिक साइज पूल, थ्रीडी प्रोजेक्ट थिएटर और टीवी रूम के साथ क्लब हाउस भी बनाया जा रहा है। मैदान पर लाल और काली मिट्टी की 11 क्रिकेट पिच तैयार की जा रही हैं। कुछ पिच लाल, कुछ काली, जबकि कुछ मिश्रित मिट्टी से तैयार हो रही हैं। इससे जरूरत के हिसाब से उछाल भरी या स्पिन के लिए मुफीद पिचों पर मैच कराए जा सकेंगे। इसके अलावा यहां 76 कॉरपोरेट बॉक्स की व्यवस्था होगी, प्रत्येक में 25 व्यक्ति बैठ सकेंगे। चार टीमों के लिए ड्रेसिंग रूम होगा। फील्ड ऑफ प्ले एलईडी लाइट्स वाला यह देश का पहला स्टेडियम होगा। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस जैसे खेलों के लिए यहां पर स्पोर्ट्स अकादमी भी होंगी।

सिर्फ एक स्टेडियम आगे

यदि क्रिकेट नहीं, खेल स्टेडियमों की बात की जाए तो तैयार होने के बाद मोटेरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। यह दर्शक क्षमता के मामले में सिर्फ उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बने रनग्राडो मे डे स्टेडियम से पीछे होगा, जिसकी क्षमता 1.14 लाख है।

वर्चुअल क्लासरूम से उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम आगे

नई शुरुआत

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

उत्तराखंड में 300 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत हो चुकी है। प्रतीकात्मक

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जिलों व दूरस्थ गांव-कस्बों में प्राथमिक-माध्यमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था कई कमियों से दो चार है। कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं फंड (सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय मदद) पहुंचने में देरी से व्यवस्था पटरी से उतरी दिखाई पड़ती है। इन दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा मुहैया कराने का खाका खींचा और वर्चुअल क्लासरूम परियोजना की शुरुआत की। इसके लिए देहरादून के ननूरखेड़ा में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के परिसर में चार केंद्रीय स्टूडियो स्थापित किए गए हैं, जिन्हें सेटेलाइट के माध्यम से क्लासरूम से जोड़ा गया है।

इन स्टूडियो में शिक्षक संबंधित विषय को पढ़ाते और समझाते हैं, जो स्मार्ट टीवी स्क्रीन के माध्यम से विद्यालय में बैठे कक्षाओं में दिखाई और सुनाई देता है। शिक्षक वार्तालाप के जरिये छात्र-छात्राओं की शंकाओं का निवारण भी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट उन स्कूलों के लिए मददगार होगा, जहां गणित, भौतिकी, रसायन और अंग्रेजी जैसे किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

500 विद्यालयों का लक्ष्य 300 में शुरू हो गई क्लास : योजना के तहत सूबे के 500 सरकारी स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, जिनमें से 13 जिलों के 300 स्कूलों को अब तक इससे जोड़ा जा चुका है। इस परियोजना को संचालित करने पर राज्य सरकार के खजाने पर बहुत अधिक भार भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नब्बे फीसद खर्च केंद्र सरकार खुद वहन कर रही है।

वर्चुअल क्लासरूम स्टूडियो : राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के परिसर में स्थापित स्टूडियो और क्लासरूम को एक सेटेलाइट के माध्यम से जोड़ा गया है। प्रत्येक स्टूडियो में दो कैमरे, एक वॉल पेपर आउटपुट के लिए एक स्मार्ट टीवी, दो माइक्रोफोन होते हैं। प्रत्येक दिन के टॉपिक्स वालपेपर पर लिखे जाते हैं। संबंधित शिक्षक उन टॉपिक्स को समझाता है जो स्मार्ट टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है। स्टूडियो से जुड़े हुए स्कूलों में एक एलईडी स्क्रीन के साथ माइक्रोफोन, स्पीकर के साथ एक कैमरा प्रदान किया जाता है। छात्र स्क्रीन देखते हैं और शिक्षक स्क्रीन पर जो कुछ लिखते हैं उसे सुनने में सक्षम होते हैं।

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भौगोलिक और प्राकृतिक कारणों से जिदंगी मैदानी इलाकों जैसी आसान नहीं हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आबाद गांवों-कस्बों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना शासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। इन्हीं हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए वर्चुअल क्लासरूम योजना की शुरुआत की। दावा है कि ऐसी सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश है। इस प्रयास का सुखद पहलू यह है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने लगी है।

1.90 लाख छात्र-छात्राएं इन कक्षाओं से होंगे लाभान्वित

इन जिलों को होगा फायदा

जिला	वर्चुअल स्कूल
पौड़ी	82
नैनीताल	61
अल्मोड़ा	52
टिहरी	52
देहरादून	46
चमोली	45
पिथौरागढ़	40
रुद्रप्रयाग	21
चंपावत	15
बागेश्वर	10
हरिद्वार	10

मेडिकल-इंजीनियरिंग में दाखिले की भी कराई जाएगी तैयारी : अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इन्हीं वर्चुअल क्लासरूम से 23 दिसंबर से छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद प्रदान की जाएगी। तैयारी से जुड़े विशेष टॉपिक कवर किए जाएंगे और शंकाओं का निवारण किया जाएगा।

पेंसिल पकड़ने से पहले सीखा तीर साधना

उभरता सितारा

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

अगर किसी काम को करने की ठान ली जाए तो उम्र और परिस्थितियां रुकावट नहीं बन सकतीं। बस जुनून और जज्बा होना चाहिए। यह बात वाराणसी के अर्जुन सिंह पर एकदम सटीक बैठती है, जिन्होंने हाल ही में तीरंदाजी में चीन और मलेशिया में देश को मेडल दिलाए। इसमें सबसे बड़ी बात जो मायने रखते ही वो है अर्जुन की उम्र, जो अभी पूरी छह भी नहीं हुई है...

जिस उम्र में बच्चे पेंसिल पकड़ना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में न केवल तीर-कमान से सही निशाना साधना, बल्कि देश को मेडल भी दिलाना कोई छोटी उपलब्धि तो नहीं हो सकती। यहां बात हो रही है वाराणसी के रहने वाले आदित्य सिंह राठौर उर्फ अर्जुन सिंह की। माता-पिता ने अर्जुन नाम रखते हुए शायद ही यह सोचा होगा कि वह सिर्फ नाम से ही नहीं, कर्म से भी अर्जुन बन जाएगा और वो भी छह साल का होने से पहले। जी हां, यही उम्र है अर्जुन की, जो अगले साल 14 जनवरी को छह साल का होगा।

उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उपलब्धियां कई हासिल कर चुका है जयपुरिया स्कूल में अपर केजी में पढ़ने वाला यह नन्हा तीरंदाज। गत नवंबर में चीन के मकाऊ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय इंडोर तीरंदाजी प्रतियोगिता ग्लोबल आर्चरी एलियंस यूथ इंडोर वर्ल्ड कप में अर्जुन ने देश की झोली में रजत पदक डाला। वहीं, 13 दिसंबर को मलेशिया में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया।

बाहुबली से बना तीरंदाज: कहते हैं छोटे बच्चों का मन-मस्तिष्क कोरे कागज की तरह होता है। शुरू में जैसी छाप पड़ जाए, वे वैसे ही बनते चले जाते हैं। अर्जुन के मस्तिष्क पर छाप पड़ी फिल्म बाहुबली-2 की। 2017 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तब अर्जुन की उम्र केवल तीन साल थी। उसमें बाहुबली (प्रभाष) की शानदार तीरंदाजी अर्जुन के मन-मस्तिष्क पर छप गई। वह दृश्य जिसमें बाहुबली देवसेना को कमान पर एक साथ तीन तीर चढ़ाकर दुश्मनों से लड़ना सिखाता है उसने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। फिल्म देखने के बाद वह माता-पिता से तीर-कमान दिलाने को कहने लगा। वाराणसी में प्राइवेट क्लीनिक चलाने वाले अर्जुन के पिता डॉ. अजय सिंह के मुताबिक, हमें लगा कि इस उम्र में बच्चे जैसे किसी खिलौने की जिद करते हैं, वैसे ही अर्जुन तीर-कमान की जिद कर रहा है। हमने उसे प्लास्टिक का तीर-कमान दिला दिया, जिससे वह घर के पीछे अभ्यास करने लगा।

इस तरह आगे बढ़ा सफर : प्लास्टिक का तीर-कमान तो सिर्फ शुरुआत थी। जब अर्जुन के माता-पिता ने देखा कि यह खेल उसके लिए जुनून बनता जा रहा है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए उसका साथ देने का फैसला किया। बकौल डॉ. अजय, फिर हमने उसे लकड़ी का तीर-कमान दिलाया। वाराणसी में यह कहीं नहीं मिला, इसलिए मणिपुर से खरीदकर लाए। इसके साथ ही हमने अर्जुन के लिए एक कोच की व्यवस्था भी कर दी। फिर पटियाला से ढाई लाख रुपये का प्रोफेशन तीर-कमान दिलवाया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ही अक्टूबर 2017 में अर्जुन पहली बार नेशनल ट्रायल में उतरा। तब उसकी उम्र महज साढ़े तीन साल थी। अर्जुन के ईमानदार प्रयासों ने कानपुर में आयोजित इनडोर आर्चरी स्टेट चैंपियनशिप में उसे दो रजत पदक दिलवाए। मेडल जीतने का जो कारवां तब शुरू हुआ, वो बदस्तूर जारी है। इसके बाद मार्च 2018 में अर्जुन ने कानपुर में ही आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा अर्जुन ने मुंबई में आयोजित मेयर कप इंडोर आर्चरी नेशनल्स में एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया। अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह में लॉस वेगास में वेगास शूट में हिस्सा लेने जा रहे इस नन्हे खिलाड़ी के नाम और भी कई मेडल और उपलब्धियां दर्ज हैं।

अर्जुन सिंह फाइल

कभी सोचा न था

अर्जुन की मां शशीकला के मुताबिक, हमने बेटे का नाम अर्जुन रखते समय यह कभी नहीं सोचा था कि वो अपने नाम की तरह सच का अर्जुन बन जाएगा। आज वो इस खेल के प्रति इतना समर्पित है कि सुबह 3:30 बजे उठ जाता है। रोजाना चार से सात बजे तक अभ्यास करता है। मौसम जितना भी खराब हो, वो अभ्यास नहीं छोड़ता। उसकी एक ही कोशिश रहती है कि उसका तीर लक्ष्य से कभी न चूके।

रूबेला भी नहीं रोक पाई रुद्राक्ष के कदम

इनसे मिलिए

सुभाष शर्मा, उदयपुर

भले ही शरीर साथ न दे, लेकिन अगर मन मजबूत है और मां का साथ है तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है उदयपुर के रुद्राक्ष ने, जो रूबेला नामक लाइलाज बीमारी को धता बता जुटे हैं स्पेशल ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए तैयारी में...

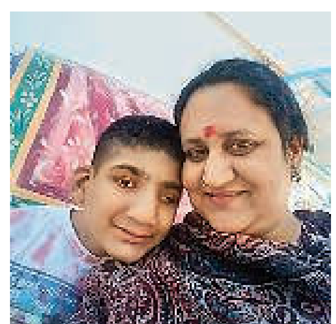
उदयपुर के रुद्राक्ष मां दीपा गोस्वामी के साथ। सौजन्य : दीपा

हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन इसमें दो हैं। एक रुद्राक्ष और दूसरी उनकी मां दीपा गोस्वामी। रुद्राक्ष, जिन्होंने लाइलाज बीमारी के साथ जन्म लिया, लेकिन हार नहीं मानी। दीपा, जिन्होंने बेटे को सक्षम बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। आज रुद्राक्ष न सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, बल्कि स्पेशल ओलंपिक में देश को मेडल दिलाने के लिए तैराकी का अभ्यास भी कर रहे हैं। वह 2021 में स्वीडन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक में भाग लेंगे।

रूबेला, वो बीमारी है जो रुद्राक्ष को जन्म के साथ अभिशाप के रूप में मिली। इस बीमारी ने रुद्राक्ष को शारीरिक रूप से अक्षम बना दिया। वह सुन तो नहीं पाते, लेकिन बोल पाते हैं। एक आंख से कम दिखाई देता है। पांच बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है, लेकिन हौसला इतना कि फतेह सागर झील को तैर कर पार कर जाते हैं। रुद्राक्ष को सक्षम बनाने में सबसे अहम योगदान उनकी मां दीपा का है। पावर लिफ्टिंग, कबड्डी और रेसलिंग में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकीं दीपा का सपना अपनी संतान को अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना था। रुद्राक्ष के जन्म के दो माह बाद जब उन्हें बेटे की बीमारी का पता चला तो यह उनके लिए किसी सपने के टूटने जैसा था। ऐसे वक्त में पति ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन दीपा ने जो सपना देखा था उसे बिखरने नहीं दिया। रुद्राक्ष को उचित माहौल में शिक्षा दिलवानी शुरू की। एक दिन दीपा ने देखा कि शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद रुद्राक्ष का मन पानी में खेलने में ज्यादा लगता है। फिर क्या, मानों उन्हें मंजिल पाने का रास्ता सामने दिखने लगा हो। बेटे को तैराक बनाने की ठान ली। इतना ही नहीं, बेटे के साथ स्वयं महाराणा भूपाल यूनिवर्सिटी स्थित तरणताल में तैराकी सीखने के लिए प्रवेश लिया। दीपा स्वयं भी अच्छी तैराक बनीं और बेटे को भी पानी को चीर कर आगे बढ़ना सिखाया। रुद्राक्ष स्पेशल ओलंपिक में भाग ले पाएं इसके लिए दीपा ने उनका प्रवेश पुणे की एक संस्था में कराया, जहां वह शिक्षा लेने के साथ तैराकी का अभ्यास कर रहे हैं। आज मां की बदौलत ही 14 वर्षीय रुद्राक्ष स्पेशल ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हैं।

आसान नहीं रहा सफर : रूबेला से पीड़ित रुद्राक्ष का यहां तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। शुरुआत में वह सिर्फ एक-दो मिनट ही तैर पाते थे, लेकिन अब एक बार में दो से तीन किलोमीटर आराम से तैरते हैं। आगामी स्पेशल ओलंपिक में भाग ले सकें, इसके लिए अगले साल जनवरी में एक और बाईपास सर्जरी से गुजरेंगे। वह स्पेशल ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होने के सभी जरूरी मापदंड पूरे कर चुके हैं। अपने इस मुकाम का श्रेय वह पूरी तरह से मां दीपा को देते हैं।

चीन ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतारा

समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटे चीन ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग को मंगलवार को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया है। 55 हजार टन वजनी जहाज पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवीज (पीएलएएन) की महत्वकांक्षाओं में उल्लेखनीय उभार है। लिओनिंग के बाद यह चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। लिओनिंग वास्तव में 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ में बना था और इसे डेलियान में पुन: निर्मित किया गया। इसे पीएलएएन में 2012 में एक ट्रेनिंग शिप के तौर पर शामिल किया गया।

अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर

एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कोई भी देश अमेरिका के नजदीक भी नहीं पहुंच सका है। अमेरिका के पास फिलहाल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उसका सबसे नवीनतम एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है, जिसे उसने जुलाई 2017 में ही अपने बेड़े में शामिल किया है। परमाणु शक्ति से चलने वाला यह एयरक्राफ्ट अपने विशालकाय कर्मी दल जिसमें 6 हजार लोगों के साथ 90 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है।

परेशानियों से जूझ रहा रूस

अमेरिका नौसेना के पास 8 वॉस्प श्रेणी के और एक अमेरिकन श्रेणी का हमलावर जहाज (एक अन्य जहाज 2020 में बेड़े का हिस्सा बनने वाला) है। यह फ्रांस के चार्ल्स डे गोल्ले के आकार के हैं, जो कि काफी अधिक विमानों को ले जाने में सक्षम हैं। रूसी नौसेना फिलहाल परेशानियों से जूझ रही है। उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर आग में घिर गया। पिछले अक्टूबर में एक क्रेन जहाज पर गिर गई और यह ताजा मामला उसके कफन में आखिरी कील साबित हुआ।

वैश्विक स्तर पर एयरक्राफ्ट कैरियर

अमेरिका	11
चीन	2
इटली	2
ब्रिटेन	2
फ्रांस	1
भारत	1
रूस	1
स्पेन	1
थाइलैंड	1

चार देशों के पास हैं दो से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर

दुनिया में महज चार देश हैं, जिनके पास दो या दो से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें चीन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और इटली शामिल हैं। रॉयल नेवी ने हाल ही में एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स को बेड़े में शामिल कर बड़ी छलांग लगाई है। यह 65 हजार टन का जहाज एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ के साथ होगा। ये दोनों एयरक्राफ्ट करीब 40 एफ-35बी लाइटनिंग टू स्टील्थ फाइटर विमानों को ले जाने में सक्षम हैं।

83 हजार करोड़ रुपये सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने के बावजूद महाराष्ट्र को लाभ नहीं मिला। विधानसभा में रखी गई 2017-18 की कैग रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 15 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद 198 परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ है और इनमें 67 परियोजनाएं तो 30 वर्षों में भी पूरी नहीं हुई हैं।

...क्योंकि दौड़ने के लिए जूते नहीं जिद और जज्बा चाहिए

रविवार विशेष

- अभ्यास को जूते नहीं थे, फिर भी खेले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंडर-14
- देवघर की इस फुटबॉल टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से जीत लिया दिल

कंचन सौरभ मिश्रा, देवघर

अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी बौनी साबित होती हैं। देवघर के एक स्कूली फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि जीतने के लिए संसाधन नहीं, जिद और जज्बा होना चाहिए। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में आयोजित सुब्रतो कप अंडर-14 में इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से लोगों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी।

देवघर से दिल्ली तक का सफर तय करने के पीछे इनकी लंबी कहानी है। पागल बाबा ट्रस्ट की ओर से संचालित लीलानंद पागलबाबा उच्च विद्यालय की इस फुटबॉल टीम के मैनेजर कुणाल कुमार चौधरी बताते हैं कि प्रतिभा पैसे की मोहताज नहीं होती। बस उसे पहचान कर निखारने की जरूरत होती है। इस टीम ने कई बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। प्रखंड, जिला, प्रमंडल व राज्य स्तर की प्रतियोगिता में धमाकेदार जीत दर्ज कर दिल्ली का सफर तय किया। इनका जज्बा अपने आदर्श फुटबॉलर मेसी, रोनाल्डो और सुनील छेत्री जैसा बनने का है। इनकी कहानी संघर्षों से भरी है। दिनभर स्कूल में पढ़ाई करने के बाद ये रोज साइकिल से तीन किमी दूर अभ्यास करने कुमैठा स्टेडियम जाते हैं। इन्होंने घरवालों से न तो जूते के लिए पैसे मांगे, न किट के। जो जूता मिला, उसी से अभ्यास किया। नहीं मिला तो नंगे पैर मैदान में उतर पड़े।

नहीं करने दिया अभ्यास : दिल्ली में आयोजित सुब्रतो कप अंडर-14 में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। मगर इस दौरान ऐसी बात हुई जो उनका कलेजा छलनी कर गई। इनके पास केवल बूट थे। वहां आंबेडकर स्टेडियम में कृत्रिम घास यानी एस्ट्रो टर्फ पर अभ्यास हो रहा था। जब ये बूट पहनकर वार्मअप करने गए तो रोक दिया गया। आयोजकों ने कहा कि इस बूट से टर्फ खराब हो जाएगी। आप प्राकृतिक घास के मैदान पर उद्घाटन मैच खेलिए।

हरियाणा, लक्षद्वीप और आइबीएसओ की टीम को हराया : उद्घाटन मैच में टीम को रिलायंस फाउंडेशन की टीम से भिड़ना था। पहले हॉफ में तीन गोल से पिछड़े। दूसरे हॉफ में एक गोल किया। मगर रिलायंस फाउंडेशन ने 4-1 से हरा दिया। इस मैच के बाद टीम ऐसी एकजुट हुई कि हरियाणा, लक्षद्वीप और आइबीएसओ की टीम को हरा दिया। उज्बेकिस्तान से वॉकओवर मिला। बावजूद रिलायंस की हार से अंकों के आधार पर अगले दौर में टीम नहीं पहुंची। मगर, जता दिया कि भविष्य सुनहरा है।

माता-पिता के साथ आशुतोष। जागरण

मिट्टी और फूस के घर में रहते हैं ये खिलाड़ी

आदिवासी बहुल गांव सुजानी में टीम के कप्तान आशुतोष हेंब्रम अपने माता-पिता के साथ एक झोंपड़ी में रहते हैं। पिता बबुआ हेंब्रम और मां सुमी मरांडी मजदूरी करती हैं। नौवीं कक्षा का छात्र आशुतोष गोलकीपर है। उपकप्तान निर्मल मुर्मू दुमका के जामा प्रखंड के ढाका गांव के हैं। पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं। 2016 में निर्मल का चयन कुमैठा स्टेडियम के फुटबॉल कैंप में हुआ था। मां मजदूरी करती हैं। सभी बच्चों की कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। आशुतोष कहते हैं कि हम सभी का मकसद है कि ऐसा कुछ करें, जिससे परिवार व देश का नाम दुनिया में हो।

टीम के अन्य सदस्य : संतोष सोरेन, दीपक मरांडी, अरविंद मरांडी, प्रेम किस्कू, सुशाल सोरेन, दीपक टुडू, अजय हांसदा, रवि हेंब्रम, राम बेसरा, आकाश हेम्ब्रम।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

लीलानंद पागलबाबा उच्च विद्यालय फुटबॉल टीम के सदस्य। जागरण

37 साल से जुटे हैं निराश्रित मरीजों की सेवा में

मिसाल ▶ उत्तराखंड में हरिद्वार के हरमिलाप जिला अस्पताल में स्थापित है छह बेड का निराश्रित वार्ड

जिनका कोई नहीं या अपनों ने ठुकरा दिया, उनकी सेवा करते हैं अस्पताल कर्मी

विनोद श्रीवास्तव, हरिद्वार

हरमिलाप जिला अस्पताल हरिद्वार के चिकित्सक एवं कर्मचारी वर्ष 1983 से ऐसे बीमारों की सेवा में जुटे हैं, जिनका अपना कोई नहीं है या फिर जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है। उनके लिए अस्पताल में बाकायदा छह बेड का निराश्रित वार्ड बनाया गया है। यहां भर्ती कुछ मरीज तो अपनी याददाश्त तक खो चुके हैं। जबकि, कई ठीक होने के बाद भी अस्पताल नहीं छोड़ना चाहते और बीमारी का बहाना बना बार-बार यहां लौट आते हैं। उन्हें अकेलेपन का अहसास न हो, इसके लिए अस्पताल कर्मी भी तीज-त्योहार की खुशी उनके साथ बांटते हैं। इसमें जो भी खर्चा आता है, उसे वह अपनी जेब से वहन करते हैं।

स्वस्थ समाज

वर्तमान में अस्पताल के निराश्रित वार्ड में पांच मरीज भर्ती हैं। इनमें दो महीने से भर्ती गुजरात का युवक रवि भी है। वह न तो ठीक से बोल पाता है, न लिख पाता है। अभी तक रवि केवल इतना ही समझा सका है कि वह मूलरूप से गुजरात का रहने वाला है। पर, गुजरात में कहां, इसकी कोई जानकारी उससे नहीं मिल पाई है। इसी तरह आरा (बिहार) की रहने वाली बुजुर्ग फूलेश्वरी देवी भी अपना मूल पता नहीं जानती। उसे हरिद्वार के ब्रह्मपुरी में रहने वाले व्यक्ति ने भर्ती कराया था। अब पुलिस आरा में उसका पता-ठिकाना तलाशने में जुटी है। अस्पताल के इस वार्ड में बीते पांच वर्षों के दौरान 1255 मरीज भर्ती हुए

हरमिलाप जिला अस्पताल में बना निराश्रित वार्ड स्थापना काल से ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। अस्पताल का निर्माण श्री हरमिलाप साहिब ट्रस्ट सोसायटी हरिद्वार के अध्यक्ष संत शिरोमणि मुनि हरमिलापी की प्रेरणा से हुआ। इसका उद्घाटन तीन सितंबर 1982 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था।

हरिद्वार स्थित हरमिलाप जिला अस्पताल। जागरण

निराश्रितों में कई उनके परिवार के ही ठुकराए हुए हैं तो कई परिजनों से मिली उपेक्षा के कारण अपनी पहचान नहीं बताते। सहयोग धनराशि स्वेच्छा से एकत्रित होती है। इसका हिसाब संबंधित सिस्टर, नर्स व अन्य स्टाफ मिलकर रखता है। इसलिए खर्चे की कोई समस्या नहीं रहती।

-डॉ. राजेश गुप्ता, सीएमएस, हरमिलाप जिला अस्पताल, हरिद्वार

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

हरिद्वार स्थित हरमिलाप जिला अस्पताल में बना निराश्रित वार्ड। जागरण

139 व 182 नंबर ही होंगे रेल यात्रियों के रहनुमा

राकेश श्रीवास्तव, वाराणसी

- संशय खत्म करने को रेलवे बोर्ड दो हेल्पलाइन का करेगा केंद्रीयकरण
- सफर के दौरान परेशानी होने पर एक कॉल करते मिलेगी मदद
- अलग-अलग नंबरों पर फोन करने से मिलेगी मुक्ति

139 और 182 नंबर रेल यात्रियों का मददगार होगा। यात्रियों को संशय से बचाने के लिए रेलवे बोर्ड दोनों हेल्पलाइनों का केंद्रीयकरण करेगा। यात्री आपातकाल में संशय में पड़ जाते कि आखिर किस नंबर पर काल करें, जिससे फौरी मदद मिल सके।

नए साल में पहले दिन से मिलेगी सुविधा: रेलवे बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। नए साल के पहले दिन से ही प्रचलन में रहे छह अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर काम करना बंद कर देंगे। रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एन मधुसूदन राव ने इस आशय का आदेश जारी किया है।

जोन स्तर पर कुछ नया नहीं होगा : जोन स्तर पर अफसर यात्रियों की मदद में कुछ नया नहीं कर सकेंगे। मसलन, अतिरिक्त हेल्पलाइन, पोर्टल आदि। रेल प्रशासन केंद्रीयकरण के बाद दोनों नंबरों के प्रचार-प्रसार पर जोर देगा, ताकि यात्रियों तक बदलाव की जानकारी पहुंचाई जा सके।

बंद होंगे ये हेल्पलाइन नंबर

- 1800111321 कैटरिंग सर्विस
- 1072 एक्सीडेंट सर्विस
- 9717430982 एसएमएस कंप्लेंट
- 138 जनरल कंप्लेंट्स
- 152210 विजिलेंस
- 58888/138 क्लीन माइ कोच

सात महीने ढका रहेगा ताजमहल का गुंबद

निर्लोष कुमार, आगरा

ताजमहल का पूरा गुंबद करीब आठ महीने तक ढका रहेगा। ऐसा इस पर मिट्टी का लेप (मडपैक ट्रीटमेंट) चढ़ाने के लिए किया जाएगा। इससे ताज के फीके पड़ रहे पत्थरों को फिर से चमकीला किया जा सकेगा। यह काम 78 वर्ष बाद होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रसायन शाखा इस काम को करेगी।

इसके लिए पूरे गुंबद को पाड़ (स्केफोल्डिंग) बांधकर कवर किया जाएगा। इससे पूर्व संरक्षण कार्य के चलते 1941-44 के दौरान गुंबद ढका गया था। संसद की पर्यावरण संबंधी समिति की सिफारिश पर एएसआइ की रसायन शाखा ने वर्ष 2015 में गुंबद को छोड़कर स्मारक के अन्य भागों को मडपैक ट्रीटमेंट से निखारा गया। मकबरे के छत की धारण क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) का अध्ययन एएसआइ की इंजीनियरिंग शाखा ने किया। उसने पाड़ बांधने में एल्यूमीनियम के पाइप का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। मगर, एल्यूमीनियम की कम मजबूती के कारण रसायन शाखा ने लोहे के पाइप से ही पाड़ बांधने का निर्णय लिया है। सूत्र बताते हैं कि फरवरी, 2020 के अंत से गुंबद पर पाड़ बांधने का काम शुरू होगा। सितंबर के अंत तक गुंबद को साफ किया जाएगा।

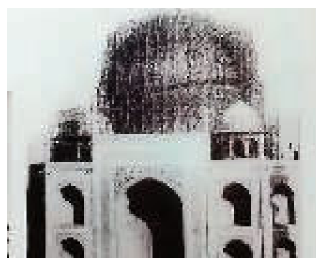
ताज के गुंबद पर वर्ष 1941-44 के दौरान संरक्षण कार्य के लिए पाड़ बांधी गई थी। यह फोटो वर्ष 1941 का है। सौ. एएसआइ

यह हैं चुनौतियां : गुंबद पर मडपैक करने में कई चुनौतियां हैं। ताज का गुंबद मकबरे की छत पर बने 11.45 मीटर ऊंचे ड्रमनुमा ढांचे पर आधारित है। इसके ऊपर बना गुंबद 22.86 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर 9.89 मीटर ऊंची फिनियल (कलश) लगी है। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव मडपैक ट्रीटमेंट में बाधा बनेगा। एएसआइ की रसायन शाखा ने दिल्ली मुख्यालय को गुंबद पर मडपैक के लिए 30 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार कर भेजा है। इसके फरवरी तक स्वीकृत होने की उम्मीद है।

तब बदले गए थे खराब पत्थर : एएसआइ ने ताज की छत और गुंबद पर वर्ष 1941-44 के बीच संरक्षण का काम कराया था। तब गुंबद के चटके पत्थरों को रीसेट करने के साथ पच्चीकारी के निकले पत्थरों को दोबारा लगाया गया था। तब इसके संरक्षण पर 92 हजार रुपये खर्च हुए थे। वर्ष 1975-76 में भी ताज के गुंबद पर काम हुआ था।

मडपैक ट्रीटमेंट : मडपैक ट्रीटमेंट कुछ और नहीं मुल्तानी मिट्टी का लेप है। इसे स्मारक की संगमरमरी सतह पर लगाया जाता है। यह स्मारक की सतह पर जमा धूल कण और गंदगी को सोख लेता है। बाद में उसे डिस्टिल्ड वाटर से धोकर साफ कर दिया जाता है।

चार चांद लगाएगा कुंभ मेला आस्था पथ

अनूप कुमार, हरिद्वार

हरिद्वार कुंभ-2021 को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए कुंभ मेला अधिष्ठान व्यापक स्तर पर 'कुंभ मेला आस्था पथ' के निर्माण की तैयारी में है। सनातनी संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म के रंग में रंगा यह आस्था पथ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र तो होगा ही, धर्मनगरी की सुंदरता में भी चार चांद लगाएगा। कुंभ मेला अधिष्ठान की ओर से आस्था पथ का निर्माण इस तरह किया जा रहा है, जिससे इसकी गिनती 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' में भी हो सकेगी।

कुंभ मेला आस्था पथ के निर्माण में मेला अधिष्ठान आधुनिक तकनीकी के साथ-साथ मंझे हुए कलाकारों की सेवाएं लेने की तैयारी में भी है। क्योंकि, आस्था पथ के दोनों किनारों की दीवारों पर कुंभ मेला, गंगा अवतरण, सनातनी परंपरा से संबंधित जानकारियां, प्रमुख तीर्थस्थल और देवी-देवताओं से संबंधित प्रसंग आकर्षक ढंग से उकेरे जाने हैं। कई स्थानों पर तो डिजिटल तकनीकी के सहारे इनके सजीव प्रस्तुतिकरण पर भी विचार हो रहा है। इसके लिए स्थानों को उसी काल एवं परिस्थिति के अनुरूप ढाला जाएगा।

स्मार्ट और हेरिटेज पोल निखारेंगे सुंदरता: कुंभ मेला आस्था पथ 'हेरिटेज और स्मार्ट पोल' से सुसज्जित होगा और अपनी खास 'वाम-व्हाइट लाइट' से मुसाफिरों को अलग दुनिया में होने का अहसास कराएगा। स्मार्ट पोल अपनी तरह का अनोखा पोल है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा और एक साथ कई तरह की सेवाएं मेला प्रशासन को देगा। इसमें यूसबी पोर्ट, अनाउंस सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, वाई-फाई जैसी सेवाएं प्रमुख हैं।

सूखी नदी के पुल का होगा जीर्णोद्धार: आस्था पथ में हरकी पैड़ी क्षेत्र के एतिहासिक स्थल भीमगोड़ा की पहचान सूखी नदी भी शामिल है। इसके तहत नदी पर बने पुल का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत के अनुसार इसके लिए कुंभ मेला आस्था पथ की कार्ययोजना में संशोधन किया जा रहा है।

इसलिए खास है वाम-व्हाइट लाइट: एलईडी लाइट्स में 'वाम-व्हाइट' सर्वाधिक प्रचलित और डिमांडिंग लाइट कलर कोड होता है। यह सफेद और बल्ब वाली पीली रोशनी का चमकदार मिश्रण है। रात के समय इसकी रोशनी नैसर्गिक छटा का अद्भुत नजारा पेश करती है।

हरिद्वार में कुंभ मेला आस्था पथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पथ की दीवारों पर इस तरह पौराणिक महत्व की धरोहरों का चित्रण किया जाएगा जागरण

मां ने चूड़ियां बेच बेटी को दिया मुकम्मल आसमां

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

- हरिद्वार जिले के घिस्सुपुरा गांव निवासी अकमल अंसारी बनीं जज

अक्सर चूड़ियों को महिलाओं की कमजोरी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हरिद्वार जिले की एक मां ने साबित कर दिखाया कि चूड़ियां बेड़ियां नहीं, फलक तक उड़ान भरने का जरिया भी हो सकती हैं। जिले के घिस्सुपुरा गांव निवासी हाशमी बेगम की बेटी अकमल अंसारी ने जज बनकर अपनी मां का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। धनपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल से तालीम की शुरुआत करने वाली अकमल की सफलता ने क्षेत्र की मुस्लिम लड़कियों को भी एक नई राह दिखाई है।

दैनिक जागरण से बातचीत में हाशमी बेगम बताती हैं, वर्ष 2007 में पति निसार अहमद का साया परिवार के सिर से उठ गया था। इसके बाद तीन बेटों और एक बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। ज्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं की थी तो उन्होंने घर में ही चूड़ी की दुकान खोल ली। अकमल ने बताया कि कक्षा आठ में ही ठान लिया था कि मुझे जज बनना है। फेरुपुर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले बीए एलएलबी और फिर एलएलएम की पढ़ाई की। उसी दौरान पीसीएस जे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अकमल के दो बड़े भाई साजिद और राशिद ऑटो चलाते हैं। जबकि, छोटा भाई हसनैन अलीगढ़ में रहकर बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। अकमल अपनी कामयाबी का श्रेय मां हाशमी बेगम और परिवार को देती हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में उन्हें इस काबिल बनाया।

हरिद्वार निवासी अकमल अंसारी के जज बनने पर मिठाई खिलातीं मां हाशमी बेगम। जागरण

कोलकाता की पहचान बचाने में जुटे हैं 'ट्राम बाबू'

संडे बॉक्स जरा हटके...

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

- ट्राम के संरक्षण के लिए तीन वर्षों से मुहिम चला रहे हैं देवाशीष भट्टाचार्य
- लोगों को ट्राम की सवारी के लिए करते हैं उत्साहित

कभी देश की धरोहर रही ट्राम अब सिर्फ कोलकाता की पहचान है। गुजरते वक्त के साथ दिल्ली-मुंबई, पटना और कानपुर सहित तमाम शहरों से ट्राम लाइनें उखड़ती चली गईं, लेकिन कुछ लोगों के अथक प्रयास से 'सिटी ऑफ ज्वॉय' यानी कोलकाता में आज भी ट्राम का वजूद है।

देवाशीष भट्टाचार्य उर्फ 'ट्राम बाबू' उन्हीं गिने-चुने लोगों में से एक हैं। 63 साल के देवाशीष पिछले 30 वर्षों से ट्रामों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। वह अपने संगठन 'कलकत्ता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन' के जरिए ट्रामों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाते हैं। लोगों को इसकी सवारी के लिए उत्साहित करते हैं। ट्राम सेवा बेहतर करने की मांग पर विभिन्न डिपो में जाकर प्रदर्शन भी करते हैं। उनके संगठन से वर्तमान में 14,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें इटली, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम सहित कई देशों के ट्राम प्रेमी भी शामिल हैं।

कोलकाता के जादवपुर इलाके में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बॉयोलाजी से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक देवाशीष ने कहा कि वर्षों पहले जब ट्राम डिपो को तोड़कर बसों को उतारा जा रहा था, तभी महसूस हुआ कि यह सही नहीं हो रहा। दुनियाभर के सभी प्रमुख शहरों में ट्राम ही परिवहन का प्रमुख साधन है जबकि भारत के बाकी शहरों की तरह कोलकाता से भी ट्राम को हटाने की कोशिश की जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय परिवहन विशेषज्ञों ने बार-बार आगाह किया है कि दिन-ब-दिन बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ट्राम सेवा का बरकरार रहना जरूरी है। इसे हटाना खुदकशी करने जैसा है। यूरोपीय देशों में ट्राम का काफी चलन है। रूस के सभी शहरों में ट्रामें चलती हैं।' कहा कि ट्राम की सवारी बेहद सस्ती व आरामदेह है। दुर्घटना का खतरा कम है। एक ट्राम 60-70 साल तक सेवा देती है।

कोलकाता में चल रहीं सिर्फ 30-35 ट्रामें : ट्राम बाबू ने कहा, कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के पास अभी 258 ट्रामें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 30-35 ही चल रही हैं। साप्ताहांत में संख्या घटकर 10-11 हो जाती है। बहुत से ट्राम डिपो में बेकार पड़े हैं। कुछ तो मरम्मत की बाट जोहते-जोहते कबाड़ में तब्दील हो गए। फिलहाल टॉलीगंज-बालीगंज, एप्स्लानेड-श्यामबाजार, एस्प्लानेड-गरियाहाट, एस्प्लानेड-खिदिरपुर और बड़ाबाजार-विधाननगर रूट पर ही ट्रामें चल रही हैं। कोलकाता में सात ट्राम डिपो और नोनापुकुर में सेंट्रल वर्कशाप है। वर्तमान में 70 से 80 हजार लोग ट्राम की सवारी करते हैं।

बचपन से ही ट्राम से गहरा लगाव : कालीघाट इलाके के रहने वाले देवाशीष को बचपन से ही ट्राम से गहरा लगाव है। ट्राम पर चढ़कर ही स्कूल-कालेज-यूनीवर्सिटी गया, इसलिए इसे मिटते नहीं देख सकता। कोलकाता में ट्रामों के कायाकल्प के साथ ही देश के दूसरे शहरों में भी इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। नई दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में फिर से ट्राम चलाने की बात चल रही है। मुंबई में भी ऐसी परियोजना पर विचार हो रहा है।

1873 में कोलकाता में चली थी देश की पहली ट्राम : देश में पहली ट्राम 24 फरवरी, 1873 को कोलकाता में ही चली थी। दिलचस्प बात यह है कि इसे घोड़े ने खींचा था। पहली बिजली चालित ट्राम भी कोलकाता में ही 27 मार्च, 1902 को चली थी।

कोलकाता के टालीगंज ट्राम डिपो में देवाशीष भट्टाचार्य उर्फ ट्राम बाबू। बिमल कर्मकार

हौसला

छत्तीसगढ़ के 90 फीसद दिव्यांग विक्रम प्रतिदिन 30 किलोमीटर ट्राइसाइकिल चलाकर बांटते हैं अखबार, एमए, डीएड होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, बच्चों को पढ़ाकर बढ़ा रहे खुद का भी ज्ञान

दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, हौसले से भर रहे उड़ान

जीना इसी का नाम है

रामाधार यादव, धमतरी

दिव्यांगता से लड़ने की जीवटता तो विक्रम से सीखनी चाहिए। 90 फीसद दिव्यांग विक्रम राजनीति शास्त्र में एमए हैं। डीएड भी किया है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। बावजूद इसके जिंदगी को निराशा के अंधेरे में डूबने नहीं दिया। हाथ फैलाने के बजाय हौसला और मेहनत के दम पर स्वाभिमान का दीप जलाए हुए हैं। सुबह चार बजे से शाम चार बजे तक बिना मोटर वाली ट्राइसाइकिल से जिंदगी का सफर तय कर संघर्ष की ऐसी गाथा लिखते हैं, जिसे सुनकर हर किसी की जुबां से शाबाश निकल जाता है। जीवन संघर्ष की इस गाथा में उनकी आमदनी नहीं, बल्कि परिश्रम लोगों को प्रेरणा देता है।

छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम परेवाडीह के विक्रम साहू (35) एक सामान्य परिवार से हैं। घर में मां-पिता, छोटा भाई है। बचपन से किशोरावस्था और फिर युवा होने तक समाज और दुनिया ने उन्हें कमजोर साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह डिगे नहीं। शिक्षा को ताकत बनाया और श्रम को पूजा। अब प्रतिदिन करीब 30 किलोमीटर ट्राइसाइकिल चलाते हैं, जितना एक सामान्य व्यक्ति शायद ही साइकिल चलाता हो।

इस तरह है उनकी दिनचर्या : विक्रम के दिन की शुरुआत सुबह चार बजे अखबार बांटने से होती है। वे ट्राइसाइकिल से 12 किलोमीटर दूर धमतरी आते हैं और अखबार बांटते हुए 8.30 बजे परेवाडीह लौटते हैं। स्नान-भोजन के बाद दस बजे गांव से तीन किलोमीटर दूर ग्राम देमार स्थित श्रीकृष्ण शिशु मंदिर में पढ़ाने जाते हैं। वहां से शाम चार बजे लौटते हैं। बारह घंटे के इस परिश्रम के बाद भी उनकी जिंदगी ठहरती नहीं। गांव का कोई बच्चा पढ़ाई में मदद मांगता है, तो उसके लिए भी तत्पर रहते हैं।

पंक्चर होने या फिर बारिश में होती है दिक्कत : विक्रम कहते हैं कि बारिश के मौसम में जरूर परेशानी होती है, लेकिन रेनकोट से इसका समाधान हो जाता है। हां, ट्राइसाइकिल पंक्चर होने पर ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में उसी हालत में किसी तरह पंक्चर दुकान तक पहुंचते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बाधा मेरा रास्ता नहीं रोक पाती।

दिव्यांगता को न मानें अभिशाप : विक्रम दिव्यांगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि वे इसे अभिशाप न मानें, बल्कि अपनी ताकत बनाएं। वे कहते हैं कि नौकरी के लिए परीक्षाएं देते रहते हैं। मंत्रियों को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। स्कूल में तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन अपने ज्ञान का सही उपयोग वे पढ़ाकर ही करना चाहते हैं।

ट्राइसाइकिल से पेपर बांटने के लिए निकले विक्रम साहू। नईदुनिया

बैंक अकाउंट के लिए धर्म बताना जरूरी नहीं

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म में धर्म का विवरण देने की कोई जरूरत नहीं है। वित्त सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को उन अफवाहों को बेबुनियाद बताया, जिसमें भारतीय नागरिकों को बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए धर्म का विवरण देना जरूरी बताया गया था। एक ट्वीट में कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिकों को खाता खुलवाने या केवाईसी समेत वर्तमान खाते से संबंधित किसी तरह की गतिविधियों के लिए धर्म बताना कतई जरूरी नहीं है। (प्रेट्र)

देश में सामाजिक सुरक्षा का चक्र बेहद कमजोर है। ऐसे में बैंकों के सामने मजबूरी है कि वे लोन और डिपॉजिट पर ब्याज दरों में एक सीमा से ज्यादा कटौती नहीं कर सकते।
— रजनीश कुमार
चेयरमैन, एसबीआइ

देश में डिस्कॉम को सुधारने पर होगा सारा जोर : आरके सिंह

साक्षात्कार

बिजली मंत्री आरके सिंह की फाइल फोटो। जागरण

हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंच जाने के बावजूद बिजली व नवीन ऊर्जा मंत्री **आरके सिंह** मानते हैं कि अभी सेक्टर में कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। किसानों के लिए बिजली की सुगम पहुंच से सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति को सुधारना उनका अगला एजेंडा है। नए वर्ष में पावर सेक्टर की भावी योजनाओं पर उन्होंने दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता **जयप्रकाश रंजन** से बात की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश :

● बिजली क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने में आपने कितनी सफलता हासिल की है?

- हमारी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बिजली क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान निकाल लिया है। सबसे पहले तो हर गांव व हर घर तक बिजली पहुंचा दी जा चुकी है। पूरे देश के बिजली वितरण को एक नेटवर्क में जोड़ा जा चुका है। फिर, बिजली आपूर्ति में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वर्तमान में स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि देश में बिजली की मांग 1.83 लाख मेगावाट की है और हमारी बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 3.66 लाख मेगावाट है। यानी मांग के मुकाबले उत्पादन क्षमता दोगुनी है। वर्ष 2014 में बिजली की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। रिन्युएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति आप देख लीजिए।

● हां, मेरा दूसरा प्रश्न भी रिन्युएबल एनर्जी से ही है। इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं...

- मैं इसका भी जवाब दूंगा। लेकिन पहले यह बता दूं कि राजग सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की वजह से देश में ऊर्जा उत्पादन के मिक्स में बड़ा बदलाव आ चुका है। अभी देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में रिन्युएबल एनर्जी का हिस्सा 20 फीसद है। हम इसे 35 फीसद करने की राह में बढ़ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रदूषण कम करने में हमें भारी मदद मिलेगी। सारे रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्र को मिलाकर हमारी स्थापित क्षमता अभी 1.20 लाख मेगावाट है जो तीन वर्षों में 1.65 लाख मेगावाट हो जाएगी। आपको पता है कि रिन्युएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देने का एक फायदा यह हुआ है कि देश में बिजली की कीमत कम करने में मदद मिली है। पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान बिजली की कीमतें कमोबेश स्थिर रही हैं, जबकि इस दौरान कोयला 40 फीसद तक महंगा हुआ है। रिन्युएबल एनर्जी के ज्यादा उत्पादन से यह संभव हुआ है।

● इन उपलब्धियों के बावजूद बिजली की मांग में इतनी कमी कैसे हो गई है?

- 18 दिसंबर को बिजली की मांग 1,56,782 मेगावाट रही, जबकि पिछले वर्ष 18 दिसंबर को यह 1,55,600 मेगावाट थी। इस वर्ष अप्रैल-नवंबर के दौरान कुल मांग औसतन 1,83,804 मेगावाट की रही है जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1,77,022 मेगावाट की थी। यानी बिजली की मांग बढ़ी है। यह सही है कि इस वर्ष अगस्त से नवंबर तक बिजली की मांग कम रही है, जिसका मुख्य कारण उस दौरान औसत से ज्यादा बारिश है। कुछ इलाकों में सामान्य से 35 फीसद तक ज्यादा बारिश हुई है। मैं कुछ राज्यों का आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा जहां कृषि क्षेत्र में मांग 40 फीसद तक कम हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में होने वाली बिजली की खपत में 10 फीसद तक कमी आई है। लेकिन बिजली की मांग फिर से सामान्य होने लगी है।

● आने वाले वर्ष के लिए आपके मंत्रालय का क्या फोकस रहेगा?

- अगले वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों पर हमारा होगा। यह ऐक ऐसा क्षेत्र है जो समूचे बिजली ढांचे में कमजोर कड़ी बना हुआ है। बहुत सारे राज्यों में उनकी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सारे डिस्कॉम को लाभ में लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए देशभर में स्मार्ट प्री-पेड मीटर के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से हम राज्यों की मदद से बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं। राज्यों से बात हो रही है कि जिलावार उन इलाकों की सूची बने जहां बिजली की चोरी अभी तक नहीं रोकी जा सकी है और फिर इन इलाकों में बिजली चोरी रोकने के उपाय किए जाएंगे। यह राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की माली हालत सुधारने में बेहद मददगार साबित होगा। इसी क्रम में हमें राज्यों के दूसरे विभागों पर बकाये डिस्काम की राशि को लौटाने काम करना है। इसके लिए राज्यों से बात हो रही है। ये विभाग अगर बकाया राशि का भुगतान कर दें तो डिस्कॉम को 42 हजार करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होगा जो उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। दूसरा लक्ष्य हमारा रिन्युएबल एनर्जी को लेकर है। इस क्षेत्र में हमें पहले से निर्धारित लक्ष्य हासिल करने का काम करना है। एक अन्य काम हमें किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराने को लेकर करना है।

● शायद आप कुसुम योजना की बात कर रहे हैं जिसे सरकार दोबारा लांच करने जा रही है..

- हां, कुसुम योजना को हम दोबारा लांच करने जा रहे हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री को भी बता दिया गया है। यह कृषि सिंचाई के मौजूदा तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। इसके तहत किसान खेतों में सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाएंगे। इसकी लागत का 30-30 फीसद केंद्र और राज्य देंगे, 30 फीसद लोन होगा और शेष 10 फीसद हिस्सा किसान को स्वयं देना होगा। इसके जरिये उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को भी अतिरिक्त आय का जरिया मिलेगा।

स्टील सेक्टर की चुनौतियां बढ़ीं : सेल चेयरमैन

नई दिल्ली, प्रेट्र : इनपुट लागत बढ़ने और देश में पर्याप्त कोकिंग कोल उपलब्ध नहीं होने की वजह से घरेलू स्टील सेक्टर को चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकारी स्टील उपक्रम सेल के चेयरमैन एके चौधरी ने शनिवार को कहा कि सरकार इस परेशानी से वाकिफ है और इसका हल निकालने के लिए उचित कदम उठा रही है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन ने उद्योग संगठन फिक्की की तरफ से आयोजित एक विशेष सत्र में कहा कि स्टील इंडस्ट्री के लिए ऊंची इनपुट लागत चिंता का विषय है। उनके मुताबिक भारत में स्टील की उत्पादन लागत फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। टैक्स की ऊंची दर इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है।

चौधरी ने कहा, 'अच्छी बात यह है कि सरकार स्टील सेक्टर की दिक्कतें जानती-समझती है और इनका हल निकालने के लिए वह उचित कदम भी उठा रही है।' सेल के चेयरमैन के मुताबिक देश में इस्पात संयंत्रों की कच्चे माल पर लगभग 20 प्रतिशत रॉयल्टी लगती है, चाहे बात कोयले की हो या फिर लौह अयस्क की। इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोल और लौह अयस्क प्रमुख कच्चा माल होते हैं। इसके अलावा माल ढुलाई की लागत भी अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 'नेशनल स्टील पॉलिसी' के तहत सरकार ने सालाना 30 करोड़ टन स्टील उत्पादन की क्षमता हासिल करने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसे पाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान जरूरी है।

चौधरी ने कहा, 'भारत में स्टील उत्पादन की औसत लागत प्रति टन करीब 450 डॉलर है, जबकि चीन में यह लागत 350 डॉलर प्रति टन बैठती है। कारण यह है कि चीन की कंपनियों को कम टैक्स और सरकारी प्रोत्साहनों का अतिरिक्त लाभ मिलता है।'

मार्च 2020 के बाद नई चुनौती : सेल के चेयरमैन ने कहा कि अगले साल मार्च के बाद घरेलू स्टील उद्योग को एक नई और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तब ढेर सारी खानों की पट्टा अवधि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कोयले और लौह अयस्क की किल्लत बढ़ जाएगी।

इकोनॉमी के रोडमैप पर चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के चुनिंदा शीर्ष कारोबारियों ने शनिवार को उन तमाम उपायों पर चर्चा की, जो भारत की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने के लिए जरूरी हैं। उन्होंने इस मामले में सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, जिनमें निर्यात बढ़ाने पर जोर और नीतियों को लेकर स्थिरता शामिल है। अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर ये तमाम विचार-विमर्श फिक्की की तरफ से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किए गए। इसमें सेल के चेयरमैन के अलावा आइटीसी के चेयरमैन एवं एमडी संजीव पुरी, कैडिला हेल्थकेयर के चेयरमैन पंकज आर पटेल, भारती इंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राजन भारती मित्तल और जेके पेपर के वाइस चेयरमैन एवं एमडी हर्षपति सिंघानिया शामिल थे। सभी कॉरपोरेट हस्तियों ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा स्पर्धी बनाने पर जोर दिया। ज्यादातर दिग्गजों का कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देना है तो कॉरपोरेट सेक्टर को ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा।

न्यूज गैलरी

फिलहाल जीएसटी स्लैब बदलने की कोई संभावना नहीं

नई दिल्ली : आइजीएसटी पर मंत्रिसमूह के संयोजक और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि फिलहाल जीएसटी स्लैब में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। फिक्की के सालाना आयोजन में मोदी का कहना था कि इस वक्त खपत में कमी दिख रही है और यह जीएसटी के स्लैब में बदलाव या बढ़ोतरी का सही वक्त नहीं है। राज्य इसके पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक भी राज्य या केंद्र सरकार इस वक्त जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है। खपत का जैसा माहौल अभी है उसमें अगर सरकार जीएसटी दरों में कटौती नहीं कर सकती, तो उसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। जब तक जीएसटी राजस्व में स्थायित्व नहीं आता, इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। (प्रेट्र)

रिलायंस और बीपी दें संपत्तियों की जानकारी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और ब्रिटिश गैस (बीजी) से उनकी संपत्तियों की जानकारी देने को कहा है। केंद्र ने याचिका के माध्यम से आग्रह किया था कि अदालत दोनों कंपनियों को अपनी संपत्तियां नहीं बेचने का निर्देश दे। दोनों कंपनियों पर पन्ना-मुक्ता और ताप्ती (पीएमटी) के लिए प्रोडक्शन शेयरिंग करार तोड़ने का आरोप है। इस आरोप के तहत एक मध्यस्थता अदालत ने दोनों कंपनियों से केंद्र सरकार को 385 करोड़ डॉलर (वर्तमान भाव पर करीब 26,500 करोड़ रुपये) के भुगतान का आदेश दिया था, जिसमें दोनों कंपनियां विफल रहीं। इसी के बाद केंद्र ने याचिका के माध्यम से दोनों कंपनियों की संपत्ति बिक्री पर रोक लगाने का आग्रह किया था। दोनों कंपनियों से कहा गया है कि वे सिविल प्रोसीजर कोड (सीपीसी) में वर्णित फॉर्म 16 के प्रारूप में संपत्तियों की जानकारी दें। (प्रेट्र)

तीन दिनों में डीजल के दाम में 50 पैसे से ज्यादा का उछाल

नई दिल्ली : डीजल के दाम में पिछले तीन दिनों के दौरान कुल 50 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि इस दौरान पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ाया गया है। शनिवार को दिल्ली व कोलकाता में डीजल का दाम 20 पैसे और मुंबई व चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इसे मिलाकर पिछले तीन दिनों में डीजल 50 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हुआ है। शनिवार को नई दिल्ली में डीजल 66.54 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा था। (आइएएनएस)

आइटी विभाग लेगा जीएसटीएन की मदद

तैयारी ▶ राजस्व बढ़ाने के लिए कारोबारियों की आइटीसी और टैक्स रिटर्न का होगा मिलान

जीएसटी में कम टर्नओवर दिखा टैक्स चोरी करने वालों पर भी होगा फोकस

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

रेवेन्यू की रफ्तार बढ़ाने को आयकर विभाग जीएसटी के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास करेगा। इसके लिए आयकर विभाग करदाताओं की इनपुट टैक्स क्रेडिट और आयकर रिटर्न की सूचनाओं का मिलान करेगा। इसके लिए दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच सूचनाएं साझा करने पर सहमति बनी है।

रेवेन्यू विभाग में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में तय हुआ कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आयकर विभाग और जीएसटी के अधिकारी आपस में सूचनाएं साझा करेंगे ताकि करदाताओं की तरफ से दी जा रही जानकारियों का मिलान किया जा सके। गड़बड़ी पाए जाने पर न केवल रिटर्न दोबारा दाखिल करने को कहा जा सकता है, बल्कि जान-बूझकर गलत जानकारी देने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बैठक रेवेन्यू सचिव अजय भूषण पांडेय के नेतृत्व में हुई और इसमें जीएसटी और सीबीआइसी के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे कारोबारी करदाताओं के आयकर रिटर्न का मिलान उसके जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से करने को कहा गया है। खासतौर पर जिन कारोबारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत ऊंची राशि प्राप्त की है, उनके आयकर रिटर्न का मिलान अवश्य किया जाए। अधिकारियों से यह देखने को कहा गया है कि दोनों रिटर्न आपस में मेल खाते हैं अथवा नहीं।

सूत्रों ने बताया कि जीएसटी अधिकारियों से आयकर विभाग को मिलने वाली जानकारी से यह भी पता लगाने में आसानी होगी कि कहीं कारोबारी कम टर्नओवर दिखाकर कर चोरी का प्रयास तो नहीं कर रहे। साथ ही जानकारी साझा होने से यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कारोबारी धोखाधड़ी करके जीएसटी रिफंड तो नहीं ले रहे हैं।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद टैक्स अधिकारियों से डाटा एनालिसिस और जानकारियां साझा करके टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा गया है। इस आशय के निर्देश भी दिए गए हैं कि फर्जी ई-वे बिल और इनवॉयस के जरिये टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टैक्स अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस अभियान के दौरान ईमानदार टैक्सपेयर को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाए। टैक्सपेयर तक यह संदेश भी पहुंचाने को कहा गया है कि वे आयकर रिटर्न दाखिल करने में ईमानदारी बरतें।

इस सप्ताह की शुरुआत में ही वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष की शेष बची अवधि में जीएसटी रेवेन्यू की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इसके तहत चार महीने की अवधि में 4.45 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपये और चार में से किसी एक माह में 1.25 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। जबकि प्रत्यक्ष कर संग्रह के मामले में 13.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों से स्पष्ट कह दिया गया है कि कारोबारियों को कॉरपोरेट टैक्स में 1.45 लाख करोड़ की जो छूट कुछ समय पहले दी गई थी, उसे प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

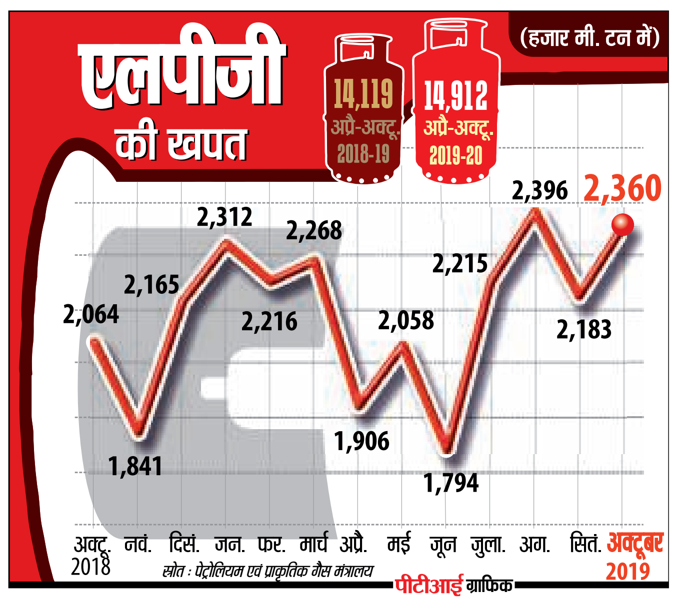

उत्तर भारत में खुद को मजबूत करेगी टीटीके प्रेस्टीज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ नए प्रोडक्ट के साथ साथ सेल्स नेटवर्क का भी विस्तार करेगी कंपनी

प्रतीकात्मक

प्रेस्टीज ब्रांड के नाम से किचनवेयर बनाने वाली कंपनी टीटीके प्रेस्टीज उत्तर भारत के बाजार में अपनी हिस्सेदारी को और मजबूत बनाएगी। इसके लिए कंपनी ने बाजार की जरूरत के मुताबिक नए प्रोडक्ट उतारने की योजना बनाई है। इसके साथ ही कंपनी अपने सेल्स नेटवर्क का भी कंपनी विस्तार करेगी।

कंपनी के चेयरमैन टीटी जगन्नाथ ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि अगले एक वर्ष के दौरान उत्तर भारत में डीलरों की संख्या में 10 परसेंट की वृद्धि का लक्ष्य है। अभी देशभर में कंपनी के डीलरों की संख्या 30 हजार है। जगन्नाथ ने बताया कि इस क्रम में कंपनी बाजार में एक टेबल आटा चक्की उतार रही है। रसोई में इस्तेमाल के हिसाब से इसका आकार भी छोटा रखा गया है। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए गेहूं पीसा जा सकता है। इसे मुंबई, पुणे और गुजरात के बाजार में लांच किया जा चुका है। अब इसे उत्तर भारत में पेश किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कंपनी एक नया इंडक्शन कुकटॉप ला रही है। इसे खासतौर पर प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने के हिसाब से बनाया गया है।

कंपनी ने हाल ही में प्रेशर कुकर का एक नया मॉडल उत्तर भारत के बाजार में उतारा है। जगन्नाथ ने बताया कि प्रेशर कुकर की इस रेंज को 'स्वच्छ' नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सीटी बजते वक्त उसमें से खाद्य पदार्थों या पानी का रिसाव बिल्कुल नहीं होता है।

पी-नोट का निवेश 13 माह के निचले स्तर पर

नई दिल्ली, एजेंसी : भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पीनोट) के जरिये नवंबर अंत तक 69,670 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। यह पिछले 13 माह के दौरान सबसे कम है। इससे पिछले महीने इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। पी-नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो आधिकारिक तौर पर पंजीकृत हुए बिना भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करना चाहते हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय पूंजी बाजार में पी-नोट के जरिये किया गया निवेश नवंबर अंत में घटकर 69,670 करोड़ रुपये रह गया। इससे पिछले महीने अक्टूबर में यह 76,773 करोड़ रुपये रहा था। अक्टूबर में इस तरह के कोष में यह पहली वृद्धि दर्ज की गई थी। पी-नोट के जरिये किया यह निवेश इक्विटी, बांड्स और वायदा एवं विकल्प कारोबार में किया जाता है। पी-नोट के जरिये नवंबर में पूंजी बाजार में हुआ निवेश प्रवाह अक्टूबर, 2018 के बाद सबसे कम रहा है। उस समय इस तरह का कुल निवेश 66,587 करोड़ रुपये रहा था।

प्याज के बाद महंगाई पर तेल की धार

नई दिल्ली, आइएएनएस : किचन का बजट बिगाड़ने में अब खाद्य तेल भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आयात महंगा होने के कारण इनकी कीमतों में तेज इजाफा हुआ है। प्याज और लहसुन जैसी चीजें पहले से काफी महंगी हैं। पिछले दो महीनों में पाम ऑयल का भाव 20 रुपये प्रति लीटर यानी 35 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया है। इसके असर से अन्य खाद्य तेल के दाम भी तेजी से बढ़े। तेल उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक कीमतें आगे और बढ़ने की अशंका है।

तिलहन बाजार के विशेषज्ञ सलिल जैन ने कहा, 'पिछले दो महीनों से हालात तेजी से बदले हैं। पाम ऑयल महंगा होने के कारण करीब-करीब सभी तरह के खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। चूंकि मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात महंगा हो गया है, लिहाजा खाद्य तेल की कीमतें आगे भी बढ़ने की आशंका है।'

तेल-तिलहन उद्योग के एक अन्य विशेषज्ञ ने देश में तिलहन किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमतें मुहैया कराने की सलाह दी। ऐसा करने पर खाद्य तेल के मामले में देश आत्मनिर्भता की दिशा में आगे बढ़ेगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसइए) ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी.वी. मेहता ने कहा, 'देश में खाद्य तेल की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से इनका महंगा आयात किया जा रहा है। हालांकि अब घरेलू किसानों को तिलहन के बेहतर भाव मिल रहे हैं। इससे इनकी खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।'

बढ़ सकता है आयात

भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि बारिश का सीजन लंबा खींचने के कारण देश के कई उत्पादक इलाकों में सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस साल रबी सीजन में तिलहन की खेती भी कम हुई है।

वायदा बाजार के संकेत

एमसीएक्स पर पिछले करीब दो महीनों में सीपीओ का वायदा भाव 37 प्रतिशत बढ़ा है। 24 सितंबर को इसका दिसंबर कांट्रैक्ट 543.2 रुपये प्रति 10 किलो था, जो 20 दिसंबर को बढ़कर 744 रुपये प्रति 10 किलो के स्तर पर पहुंच गया। इससे बाजार में तेजी के रुझान का संकेत मिलता है।

भारत के लिए चुनौतियां

1. अर्जेंटीना की नीति

एक बड़ी दिक्कत यह है कि अर्जेंटीना ने सोया ऑयल के निर्यात पर शुल्क 25-30 प्रतिशत बढ़ा दिया है। जाहिर है, भारतीय निर्यातकों के लिए यह तेल महंगा पड़ेगा। इसके कारण घरेलू बाजार में कीमतें आगे चलकर और बढ़ सकती हैं।

2. बोयो-डीजल प्रोग्राम

पाम ऑयल के सबसे बड़े निर्यातक मलेशिया और इंडोनेशिया ने क्रमश : बी-28 और बी-30 बोयो-डीजल प्रोग्राम शुरू किया है। इसके कारण इन देशों में पाम ऑयल की घरेलू खपत बढ़ जाएगी, जिसका असर निर्यात पर पड़ेगा। इसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ सकता है।

एसआइपी में निवेश के लिए फायदेमंद ही होता है शेयर बाजार में उथल-पुथल

धीरेंद्र कुमार, सीईओ, वैल्यू रिसर्च

बोनस

बड़ा सवाल है कि क्या शेयर बाजार की उथल-पुथल निवेशकों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। आमतौर पर निवेशक उथल-पुथल से घबराते हैं क्योंकि उन्हें इससे नुकसान होने का अंदेशा रहता है लेकिन एसआइपी के जरिये लंबे अरसे तक नियमित करने निवेश से बाजार की उथल-पुथल के नुकसान से न सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि इसे फायदे में तब्दील किया जा सकता है। एसआइपी आम निवेशकों के लिए सबसे बेहतरीन रणनीति है।

नाजुक का विलोम शब्द क्या होगा? लेबनानी-अमेरिकन रिस्क एनालिस्ट नासिम निकोलस तालेब अपनी पुस्तक एंटीफ्रेजाइल के बारे में बात करते हुए यह सवाल हमेशा पूछते हैं। लोग इस सवाल के जवाब में मजबूत, सुदृढ़ या अटूट जैसे शब्द बताते हैं। इस पर तालेब पूछते है - अच्छा, यह बताइए कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है। स्पष्टतया लोग इसके जवाब में निगेटिव यानी नकारात्मक बताते हैं। तो वह लोगों से पूछते हैं कि आपने पॉजिटिव का विलोम जीरो यानी शून्य क्यों नहीं नहीं बताया? अगर नाजुक यानी फ्रेजाइल का विलोम सुदृढ़ यानी रोबस्ट है, तो पॉजिटिव का विपरीत जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? आमतौर पर वे इसकी व्याख्या भी करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।

तालेब बताते हैं कि अगर आप कोई कांच की वस्तु भेज रहे हैं तो आमतौर पर उसके पैकेट पर लिखते हैं, 'सावधानी बरतें।' लेकिन अगर आप कोई लोहे की वस्तु भेज रहे हैं तो आप ऐसा कोई संदेश नहीं लिखते हैं, क्योंकि लोहे की वस्तु मजबूत और सुदृढ़ होती है और पैकेट गिर जाने पर उसके टूटने की संभावना नहीं होती है। लेकिन नाजुक यानी फ्रेजाइल का सुदृढ़ सही विलोम शब्द नहीं है। अगर आप कोई पैकेट भेज रहे हैं जिसमें नाजुक के विपरीत वस्तु है तो क्या आप उस पर लिखेंगे, 'कृपया असावधानी बरतें या मिसहैंडल करें?' अगर नाजुक वस्तुओं को किसी भी तरह के झटके से नुकसान हो सकता है तो इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जिन्हें झटकों से कोई लाभ हो।

पहला तर्क पढ़कर अटपटा लगता है। ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो झटकों को झेल सकती हैं पर निश्चित ही ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसे झटकों से फायदा मिले। हालांकि जब तालेब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं तो आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पूरी तरह नाजुक के विपरीत हैं।

जब हम शेयर निवेश के बारे में समाचारों पर नजर डालते हैं तो हमें अहसास होता है कि उथल-पुथल निवेशकों के लिए सबसे खराब होती है। जैसे पिछले कुछ महीनों से शेयर बाजार में काफी उथल-पुथल रही है। बिजनेस टीवी चैनल्स के एंकरों के चेहरे लटके हुए होते हैं। समाचार लिखने वाले हमेशा यह मानते हैं कि शेयर बाजार काफी गिर चुके हैं और अगले कुछ दिनों तक गिरावट रह सकती है लेकिन इसके बाद सुधार होने लगेगा। तमाम निवेशक जिनकी सफलता या विफलता अगले दिन बाजार की दिशा की भविष्यवाणी पर निर्भरती है, उन्हें भी इसमें नुकसान उठाना पड़ जाता है।

लेकिन क्या कोई निवेश रणनीति ऐसी है जो आम बचतकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो और जिसके जरिये शेयर बाजार में फायदा उठाया जा सके। उथल-पुथल के दौर में भी यह रणनीति फायदा देने वाली साबित हो। क्या कोई एंटीफ्रेजाइल (नाजुक के विपरीत यानी सुदृढ़) निवेश रणनीति है जिसका हम और आप इस्तेमाल कर सकें।

निश्चित ही ऐसी रणनीति है। यह वही रणनीति है जिसे स्मार्ट म्यूचुअल फंड निवेशक पहले से ही अपना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसआइपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) की। एसआइपी इसी धारणा पर आधारित है कि लंबे समय तक निवेश करने से आपकी निवेश लागत की एवरेजिंग हो जाती है यानी घट जाती है। यह सबसे आसान फिर भी सबसे प्रभावित टेक्निक है जिससे उथल-पुथल के दौर में भी फायदा उठाया जा सकता है। आप नियमित रूप से निश्चित राशि हर महीने निवेश करते रहते हैं और यह प्रक्रिया लंबे अरसे तक जारी रहती है। जब बाजार गिरते हैं तो शेयर मूल्य कम होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंडों की एनएवी कम हो जाती है। इससे आपके द्वारा निवेश की गई राशि से आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट मिलती हैं। लेकिन जब आप अपना निवेश निकालते हैं तो सभी यूनिटों की कीमत समान होती है। हालांकि इसमें उथल-पुथल के दौर में फायदा ज्यादा होता है क्योंकि गिरावट के समय आपने निवेश किया है। यही एंटीफ्रेगाइल है। उथल-पुथल से वास्तव में आपको फायदा मिलता है।

लंबे समय तक शेयर मूल्य धीरे-धीरे बढ़ने से एसआइपी में फायदा होता है। लेकिन बीच-बीच में बाजार में उथल-पुथल होती है तो इसमें रुकावट आती है। निवेश की सबसे उत्तम एंटीफ्रेगाइल रणनीति है। आप ज्यादा फायदा उठाते हैं क्योंकि बाजार में उथल-पुथल होती है। कल्पना कीजिए, अगर बाजार में गिरावट न आए, हर दिन शेयर मूल्य बढ़ते रहें तो आपको एसआइपी में निवेश का फायदा नहीं होगा।

एसआइपी अनिवार्यतया नियमित रूप से निवेश जारी रखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक चाल है। बाजार में तेजी-मंदी से एसआइपी निवेश पर कोई असर नहीं होता है। यह निवेशकों के लिए ऐसा नियमित बंधन है जिसका उन्हें फायदा होता है। इसमें एंटीफ्रेजाइल का तत्व छिपा लाभ है जो लंबे अरसे के बाद मिलता है।

जब कोई निवेश को फ्रेजाइल-एंटीफ्रेजाइल के लिहाज से देखेगा तो उसे तुरंत अहसास हो जाएगा कि शेयर या डेरिवेटिव्स में शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में निवेश सबसे नाजुक है जबकि लंबे अरसे तक एसआइपी निवेश सबसे सुदृढ़ रणनीति है।

भेदभाव खत्म करने को हटाया गया अनुच्छेद 370 : अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन, प्रेट्र : एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार से लड़ने और जातीय व धार्मिक भेदभाव खत्म करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के तहत लिया गया था।

अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए विल्सन ने कहा, 'दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में अमेरिकी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को सफल होते देखने के लिए आभार व्यक्त करते हैं।' अगस्त में विल्सन ने मुंबई की यात्रा की थी और 26/11 आतंकी हमले वाले स्थानों पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। उन्होंने कहा, '15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस संबोधन बेहद प्रेरणादायी था।' विल्सन ने आगे कहा, 'सितंबर में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में मौजूद रहना भी असाधारण था जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। 52 हजार लोगों की मौजूदगी के साथ अमेरिका के इतिहास में किसी देश के प्रमुख का यह सबसे भव्य स्वागत समारोह था।'

गांधी के विचारों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी संसद में बिल पेश

▸ अगले पांच वर्ष के लिए एक हजार करोड़ से अधिक अनुदान देने की मांग

वाशिंगटन, प्रेट्र : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचारों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया है। प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता व सांसद जॉन लुईस द्वारा पेश बिल में इस कार्य के लिए अगले पांच वर्ष में एक हजार करोड़ से अधिक रुपये के अनुदान की मांग की गई है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पेश 'हाउस बिल (एचआर 5517)' दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मित्रता और गांधी एवं लूथर किंग जूनियर के विचारों और योगदान को दर्शाता है।

गांधीवाद के प्रोत्साहन के लिए पेश इस विधेयक के अन्य प्रस्तावों में गांधी-किंग डेवेलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना करना भी शामिल है, जिसे भारतीय कानूनों के तहत 'यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआइडी)' द्वारा गठित किया जाएगा। विधेयक में इस फाउंडेशन के लिए यूएसएआइडी को अगले 5 वर्ष तक हर वर्ष तीन करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 210 करोड़ रुपये देने की मांग की गई है।

विधेयक में कहा गया, यह फाउंडेशन अमेरिका और भारत की सरकारों द्वारा गठित एक परिषद होगा, जो स्वास्थ्य, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान मुहैया कराएगी। इस विधेयक को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद डॉ. एमी बेरा, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल के अलावा ब्रेंडा लॉरेंस, ब्रांड शेरमैन और जेम्स मैकगवर्न का भी समर्थन हासिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा, यह भारत और अमेरिका के बीच 'घनिष्ठ सांस्कृतिक और वैचारिक' संबंधों को मजबूत करता है।

अमेरिकी संसद। फाइल

अकाल तख्त के जत्थेदार को भेजा जाएगा अमेरिकी संसद का प्रस्ताव

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में सिखों के सम्मान में पारित किए गए एक प्रस्ताव की विशेष प्रति अकाल तख्त के जत्थेदार को भेजा जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इसकी प्रतियां भेजी जाएंगी। इस प्रस्ताव में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के साथ ही अमेरिका के विकास में सिखों के योगदान की भी सराहना की गई है।

रिपब्लिकन सांसद टॉड यंग और डेमोक्रेटिक सांसद बेन कार्डिन की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को गत 14 नवंबर को सर्वसम्मिति से पारित किया गया था। यंग ने बताया, 'हम अकाल तख्त के जत्थेदार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समति के अध्यक्ष को प्रस्ताव की प्रतियां भेज रहे हैं। प्रस्ताव की प्रतियों के साथ पत्र भी इंडियाना में रहने वाले जानेमाने सिख नेता गुरिंदर सिंह खालसा को सौंपा गया है।' प्रस्ताव की प्रतियों और पत्र लेकर इसी माह भारत की यात्रा पर आने वाले गुरिंदर ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले करीब दस लाख सिखों के लिए यह गर्व की बात है।

सीनेट में किया गया पेश

सीनेट में गत 31 अक्टूबर को प्रस्ताव पेश करते समय यंग ने कहा था, 'यह प्रस्ताव अमेरिकी सिखों का सम्मान करता है, जो हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता का अहम हिस्सा हैं।' जबकि कार्डिन ने सिखों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ ही नस्ली और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होने के लिए सिखों के साहस की सराहना की थी।

विदेशी मंत्री पर सांसद से मिलने के लिए डाला गया था दबाव

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतवंशी अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल से विदेश मंत्री एस जयशंकर के नहीं मिलने के मुद्दे पर भारत का रुख सामने आया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने जयशंकर को जयपाल से बैठक करने पर जोर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया। खास बात यह है कि जयपाल विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाली समिति की सदस्य भी नहीं थीं।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सांसदों के साथ बैठक को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। दरअसल, विदेश मंत्री से सीनेट और विदेश मामलों की संसदीय समितियों के नेताओं से मिलने का आग्रह किया गया था। सीनेट नेताओं के साथ बातचीत खुले मन से हुई। वहीं विदेश मामलों की संसदीय समितियों के कुछ नेता जयशंकर से मिले और कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान संसदीय समितियों ने बिना विदेश मंत्री की सहमति कुछ उन लोगों को बुला रखा था, जिनका कश्मीर जैसे मुद्दे पर रुख सर्वविदित है। किसी भी देश के विदेश मंत्री को किसी विशेष राजनेता से मिलने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। गुरुवार को जयशंकर ने कहा था कि उन्हें जयपाल से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता दें कि प्रमिला जयपाल प्रतिनिधि सभा में कश्मीर मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाई थीं और भारत से जम्मू-कश्मीर में लागू प्रतिबंधों में छूट देने का आग्रह किया था।

जयपाल के समर्थन में उतरे सैंडर्स और वॉरेन

वाशिंगटन, प्रेट्र : डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की मजबूत दावेदार बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन सहित दो अन्य अमेरिकी सांसद अब जयपाल के समर्थन में उतर आए हैं। सैंडर्स, वॉरेन और अन्य सांसदों ने शुक्रवार को जयपाल के समर्थन में ट्वीट किया, जिसमें जयशंकर और भारत पर अमेरिकी सांसद की आवाज को खामोश कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। वॉरेन ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका और भारत महत्वपूर्ण साझेदार हैं, लेकिन यह तभी सफल हो सकता है, जब बातचीत में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए।

रूस और तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों के विधेयक को राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी

बड़ा मामला ▸ राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून पर किए दस्तखत, बढ़ेगा देश का रक्षा बजट

एनडीएए करेगा यूरोपीय ऊर्जा की जरूरतों की रक्षा

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध के प्रावधान वाले 738 अरब डॉलर (करीब 52 लाख करोड़ रुपये) के रक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीएए) 2020 को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही अमेरिकी सैन्य खर्च में लगभग 20 अरब डॉलर (डेढ़ लाख करोड़ रुपये) की वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक पर शुक्रवार रात वाशिंगटन के निकट ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर हस्ताक्षर किए गए।

विधेयक में कहा गया है कि एनडीएए रूसी ऊर्जा पाइपलाइनों वाली परियोजना - नार्ड स्ट्रीम 2 और तुर्कस्ट्रीम पर प्रतिबंध लगाकर यूरोपीय ऊर्जा की जरूरतों की रक्षा करेगा। विधेयक में तुर्की द्वारा रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 के अधिग्रहण के खिलाफ उसे अमेरिकी नेतृत्व वाले एफ-35 लड़ाकू जेट कार्यक्रम से बाहर रखने के फैसले को दोबारा लागू किया गया है। बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लेवरोव ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में कहा था कि ना तो नार्ड स्ट्रीम 2 और ना ही तुर्कस्ट्रीम परियोजना को बंद किया जाएगा। दरअसल, एनडीएए विवेकाधीन कोष के तहत अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के लिए लगभग 635 अरब डॉलर (45 लाख करोड़ रुपये) के बजट की व्यवस्था करता है। इतना ही नहीं इसमें 3.1 फीसद वेतन वृद्धि भी शामिल है, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। बिल में स्पेस फोर्स (अंतरिक्ष सेना) की स्थापना भी शामिल है।

रूस और जर्मनी ने परियोजना पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई : रूस ओर तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने वाले विधेयक को मंजूरी देने के बाद शुक्रवार को जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो से फोन पर बात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्गन ऑर्टागस ने कहा कि पोंपियो ने दोनों परियोजनाओं के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया है। हालांकि इसके बावजूद रूस और जर्मनी ने नार्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धताओं की फिर से पुष्टि की है। बता दें कि पिछले सप्ताह जर्मन-रूसी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जोर देकर कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए दोनों ही परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं और अगर विधेयक को मंजूरी मिलती है तो अमेरिका के खिलाफ जवाबी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

अमेरिका बनाएगा अपनी अंतरिक्ष सेना : रूस और चीन से 21वीं सदी में मिलने वाली रणनीतिक चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने रक्षा विभाग के तहत एक अंतरिक्ष सेना के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सेना की पांच अन्य शाखाओं की तरह काम करेगा। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीएए) 2020 पर दस्तखत के दौरान ट्रंप ने वहां मौजूद सैन्य अफसरों से कहा था कि भविष्य में अंतरिक्ष नया युद्धक्षेत्र बनेगा और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा।

रूस और तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने वाले राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीडीए)-2020 पर हस्ताक्षर करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस मौके पर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप (बाएं) और उपराष्ट्रपति माइक पेंस (दाएं) भी मौजूद रहे। एएफपी

पाकिस्तान में ईशनिंदा में मुस्लिम प्रोफेसर जुनैद को मौत की सजा

▸ फेसबुक पोस्ट लिखने पर हुई कार्रवाई, पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

▸ जुनैद के वकील राशिद रहमान की उनके दफ्तर में ही कर दी गई थी हत्या

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में ईशनिंदा संबंधी फेसबुक पोस्ट लिखने पर एक मुस्लिम प्रोफेसर को मौत की सजा सुनाई गई है। प्रोफेसर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। डॉन अखबार के अनुसार, पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर स्थित बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी (बीजेडयू) में अंग्रेजी के प्रोफेसर जुनैद हाफिज के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दाखिल किया गया था। पुलिस ने उन्हें 13 मार्च, 2013 को गिरफ्तार किया था। 2014 से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मुल्तान की सत्र अदालत के जज कासिफ कयूम ने शनिवार को जुनैद को मौत की सजा सुनाई। मई 2014 में जुनैद के वकील राशिद रहमान की उनके दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस साल के प्रारंभ में जुनैद के माता-पिता ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा से अपने बेटे के मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा पिछले छह साल से ईशनिंदा के झूठे आरोप में मुल्तान की सेंट्रल जेल में बंद है।

पाकिस्तान में ईशनिंदा काफी संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे मामलों में अक्सर ही हिंसा तक भड़क उठती है। इस्लाम की निंदा या अपमान करने का दोषी या यहां तक आरोपी पर भी हिंसक घटनाओं और हत्या का खतरा रहता है। हालांकि, अधिकार समूहों का कहना है निजी खुन्नस दूर करने की आड़ में अक्सर ईशनिंदा कानून का उल्लंघन किया जाता है।

236 हॉवित्जर तोप खरीदेगा पाक

नई दिल्ली, आइएएनएस : जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बनी तनाव की स्थिति के बीच पाकिस्तान ने चीन से 236 हॉवित्जर तोप खरीदने का फैसला किया है। इससे उसकी हमले की क्षमता में खासा इजाफा होगा।

पाकिस्तान ने एसएच-15 हॉवित्जर तोप का सौदा चाइना नॉर्दन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ किया है। इस सौदे के साथ ही पाकिस्तान को तोप के निर्माण की तकनीक भी मिलेगी। पाकिस्तान इस सौदे की पहली किश्त के रूप में दो करोड़ डॉलर की धनराशि का भुगतान कर चुका है। सूत्रों के अनुसार एक साल के भीतर ये तोपें प्राप्त कर पाकिस्तान इन्हें नियंत्रण रेखा के नजदीक तैनात करेगा। पता चला है कि इन तोपों से छोटे परमाणु बम भी दागे जा सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा छोटे आकार के परमाणु बम बनाने की काफी चर्चा है। ये सीमित इलाके में भयानक बर्बादी फैलाने वाले होते हैं। पाकिस्तानी सेना ने एचएस-15 तोप का इसी साल कराची में परीक्षण किया था। परीक्षण में सेना ने उसे उपयुक्त पाया और सरकार से खरीदने के लिए सिफारिश की थी। चीनी कंपनी पाकिस्तान में तोप बनाने का कारखाना स्थापित करने में भी सहयोग दे रही है। जबकि चीनी कंपनी टैक्सिला पाकिस्तान के मुख्य युद्धक टैंक 85-2 एपी में बदलाव कर रही है। 106 टैंकों की क्षमता में बढ़ोतरी की योजना है। पाकिस्तानी सेना के पास ऐसे कुल 268 टैंक हैं। 1990 में इनकी चीन से खरीद की गई थी।

प्रतीकात्मक

इमरान खान को सता रहा भारत के हमले का डर

▸ आशंकित पाक पीएम ने कहा, नागरिकता कानून के विरोध से बन रहे हालात

▸ ताबड़तोड़ ट्वीट कर मोदी सरकार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के एजेंडे पर चलने का लगाया आरोप

इस्लामाबाद, प्रेट्र : नागरिकता कानून के विरोध को ठंडा करने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान पर हमले जैसा कदम उठा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। यह बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही है।

लगातार कई ट्वीट कर इमरान ने कहा, भारत की मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र की स्थापना के एजेंडे पर चल रही है। नागरिकता कानून में बदलाव इसीलिए किया गया है। सेकुलर सोच वाले लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और अब यह बड़ा आंदोलन बन गया है। इमरान ने कहा कि भारत जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की टिप्पणी यही संकेत करती है। उल्लेखनीय है कि जनरल रावत ने बुधवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव कभी भी बढ़ सकता है, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।

जनरल रावत का बयान पाकिस्तानी सेना के बार-बार के संघर्षविराम उल्लंघन की बाबत आया था। जम्मू-कश्मीर से अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना बार-बार सीमापार से फायरिंग कर उकसावे की कोशिश कर रही है। ध्यान बांटकर आतंकियों को भारत में भेजना चाह रही है।

इमरान खान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेताया है कि भारत ने पाकिस्तानी धरती के भीतर अब कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान के पास उसका करारा जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। भारत घरेलू समस्या से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर सकता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी उसे रोके। इमरान इससे पहले भी भारत के नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि जनरल रावत ने सैन्य कार्रवाई का बयान देकर भारत की घरेलू समस्या से ध्यान हटाने का प्रयास किया है।

फ्रांसीसी सर्जन पर 349 बच्चों के यौन उत्पीड़न का संदेह

लोरिएंट, एएफपी : एक सेवानिवृत्त फ्रांसीसी सर्जन ने अपने 30 साल के सेवाकाल के दौरान कम से कम 349 बच्चों के साथ दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न किया होगा। फ्रांस में बाल यौन उत्पीड़न के अभी तक के सबसे बड़े मामले के अभियोजक ने यह जानकारी दी है। चार पीड़ित बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपित 68 वर्षीय जोएल ले स्कोउर्नेक के खिलाफ मार्च से सुनवाई शुरू होगी।

आरोपित सर्जन 30 वर्षों तक मध्य और पश्चिम के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत रहा। उसके खिलाफ आरोप में पूरे सेवाकाल को समेटा जा सकता है। उसके खिलाफ आरोपों में पड़ोस में रहने वाली एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के अलावा एक एक युवा रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म और दूसरे का यौन उत्पीड़न शामिल है।

एक बाल रोगी के यौन उत्पीड़न से उसका कृत्य सामने आया है। इस मामले में उसके खिलाफ आरोप लगने के बाद जांचकर्ताओं ने गोपनीय डायरियां बरामद कीं जिसमें ले स्कोउर्नेक के सैकड़ों बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य का पता चला।

चीन को आर्थिक मदद बंद करने की मांग

वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक मुख्यालय के सामने तुर्की नेशनल एवेकिंग मूवमेंट (ईटीएनएएम) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चीन के उइगर मुस्लिमों के इलाकों में चल रहे चाइनीज वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तत्काल बंद करने की मांग की। उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक इन सेंटर्स को 50 मिलियन डॉलर (करीब साढ़े तीन अरब रुपये) की आर्थिक मदद देता है। एएफपी

सीरिया पर आए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर चीन-रूस का वीटो

संयुक्त राष्ट्र, एएफपी : हिंसाग्रस्त सीरिया के चालीस लाख लोगों को मानवीय सहायता एक वर्ष के लिए बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके रोक दिया है। फिलहाल सीरिया में मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र के जांच केंद्रों से होकर पहुंचाई जाती है और इसके लिए बशर अल असद सरकार की अनुमति नहीं लेनी होती है।

दरअसल, मौजूदा सुविधा की समय-सीमा अगले वर्ष 10 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसी अवधि को बढ़ाए जाने के लिए जर्मनी, बेल्जियम और कुवैत ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को परिषद के 13 सदस्यों का समर्थन मिला था, लेकिन इस पर रूस और चीन ने वीटो कर इसे रोक दिया। बता दें कि इस संबंध में रूस ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जांच केंद्रों की संख्या को कम करके छह महीने के विस्तार की अनुमति देने की बात कही गई थी। हालांकि उसके प्रस्ताव को मात्र नौ वोट मिले। रूस, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी और प्रमुख समर्थक देश है।

बड़ा फैसला

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस फैसले से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहूदी देश के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बन गया है

फलस्तीन में युद्ध अपराधों की जांच करेगा आइसीसी

▸ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मुख्य अभियोजक ने किया एलान

▸ इजरायल ने दी तीखी प्रतिक्रिया तो अमेरिका ने भी की आलोचना

हेग, एएफपी : इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आइसीसी) की मुख्य अभियोजक फातोउ बेनसाउदा ने कहा कि वह फलस्तीन क्षेत्रों में हुए कथित युद्ध अपराधों की विस्तृत जांच शुरू करना चाहती हैं। उनके इस एलान पर इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी ने भी इसकी आलोचना की है। जबकि फलस्तीन ने इस कदम का स्वागत किया है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस फैसले से हेग स्थित आइसीसी यहूदी देश के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बन गया है। इजरायल साल 2002 में गठित इस अंतरराष्ट्रीय अदालत का हिस्सा बनने से इन्कार करता रहा है। इसके पहले शुक्रवार को आइसीसी की मुख्य अभियोजक फातोउ ने एक बयान में कहा, 'मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि फलस्तीन के हालात की जांच शुरू करने का वाजिब आधार है। मुझे लगता है कि पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी समेत वेस्ट बैंक में युद्ध अपराध किए गए या हो रहे हैं।' हालांकि उन्होंने कथित युद्ध अपराधों को अंजाम देने वालों का कोई ब्योरा नहीं दिया।

फातोउ ने बताया कि वह विस्तृत जांच शुरू करने से पहले आइसीसी से उस क्षेत्र की जानकारी लेंगी, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस जांच को शुरू करने के लिए जजों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आइसीसी से 2015 में जुड़ने वाले फलस्तीन ने जांच का अनुरोध कर रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, 'हम इजरायल को निशाना बनाने वाली किसी भी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि फलस्तीन संप्रभु देश नहीं है, इसलिए वह किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता।' इजरायल, अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है।

आइसीसी के जजों को गिरफ्तार करने की दी थी धमकी

इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की उस धमकी से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने पिछले साल कहा था कि इजरायल या अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो आइसीसी के जजों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

2015 में हुई थी प्रारंभिक जांच

आइसीसी की मुख्य अभियोजक फातोउ ने इजरायल और फलस्तीनी क्षेत्रों में हुए कथित युद्ध अपराधों की जनवरी 2015 में प्रारंभिक जांच शुरू की थी। 2014 में हुए गाजा युद्ध में फलस्तीन की तरफ 2251 लोगों की मौत हुई थी। इनमें ज्यादातर नागरिक थे। जबकि इजरायल में 74 मौत हुई थी। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद आइसीसी की विस्तृत जांच संभव नहीं हो पाई थी।

लंदन में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारी

लंदन, प्रेट्र : भारत में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ शनिवार को लंदन में 'पार्लियामेंट स्क्वायर' पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र और अन्य लोग एकत्र हुए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन 'भारतीय संविधान को बचाओ' के संदेश के साथ किया गया।

इसमें ब्रिटेन स्थित कई दक्षिण एशियाई संगठन जुटे। उनके हाथों में तिरंगा ध्वज था और तख्तियां थीं, जिन पर सीएए एवं एनआरसी वापस लेने की मांग की गई थी। इस बीच, शनिवार को ब्रिटेन में कई विश्वविद्यालय परिसरों में सिलसिलेवार प्रदर्शन हुए। बुधवार को ब्रिटेन भर से जुटे सैकड़ों लोगों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर तख्तियां और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की भारत सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिया जाए।

'अमेरिका के बेबुनियाद आरोपों से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ेगा'

▸ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर उत्तर कोरिया ने किया पलटवार

सियोल, रायटर : मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के अमेरिका के आरोपों पर उत्तर कोरिया ने पलटवार किया है। कहा कि इन घृणास्पद आरोपों से कोरियाई प्रायद्वीप में केवल तनाव बढ़ेगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान वहां की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए पर आया है।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका अगर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उत्तर कोरिया की सरकारी व्यवस्था को बदनाम करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की निंदा की है। कहा है कि वहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का सिलसिला दशकों से चल रहा है, जो निंदनीय है। संयुक्त राष्ट्र आमसभा में बुधवार को इस सिलसिले में दर्जनों देशों द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया जिसमें अमेरिका भी शामिल था। उत्तर कोरिया की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आई है जब उत्तर कोरिया मामलों के विशेष दूत स्टीफन बीगन ने उससे परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित वार्ता में फिर से शामिल होने का अनुरोध किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भी शुक्रवार को उम्मीद जताई कि अमेरिका और उत्तर कोरिया जल्द ही वार्ता की टेबल पर होंगे और उसे अपेक्षित सफलता मिलेगी।

उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की यूएन ने भी निंदा की थी। फाइल

ये भी जानिए
विराट कोहली का बाराबती स्टेडियम में बेहद खराब रिकॉर्ड रहा है। वह अभी तक यहां तीन वनडे और एक टी-20 में 34 ही रन बना पाए हैं। इसमें उन्होंने 3, 22, 1, 8 रन की पारी खेली हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज जीतने उतरेगा भारत

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज

कटक, प्रेट्र: आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को तीसरे वनडे में उतरेगी तो उसका इरादा वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का होगा। वेस्टइंडीज ने चेन्नई में पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन भारत ने विशाखानपत्तनम में दूसरा मैच उसी अंदाज में जीतकर वापसी की। कप्तान विराट कोहली खाता नहीं खोल सके लेकिन शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और कुलदीप यादव ने हैट्रिक लगाई। भारत ने दूसरा मैच 107 रन से जीता।

रोहित के निशाने पर जयसूर्या का रिकॉर्ड: दूसरे मैच में 159 रन बनाने वाले रोहित सलामी बल्लेबाज के तौर पर सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले सनत जयसूर्या के रिकॉर्ड से नौ रन पीछे हैं। केएल राहुल ने भी पहले विकेट की 220 रन की साझेदारी में शतक जमाया था। जून में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले से पारी का आगाज कर रहे राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह पक्की कर ली है। श्रेयस अय्यर और रिषभ पंत ने भी रन बनाए। गेंदबाजी में चोटिल दीपक चाहर की जगह तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है।

गलतियों से बचे भारतीय टीम : क्षेत्ररक्षण में भारत का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। अय्यर ने जरूर शिमरोन हेटमायर को शानदार थ्रो पर रन आउट किया लेकिन चाहर ने निकोलस पूरन और शाई होप का कैच टपकाया। कोहली ने मैच के बाद कहा था कि हमें कैच लपकने होंगे। अपनी गलतियों से पार पाना होगा। क्षेत्ररक्षण का लुत्फ उठाने की जरूरत है। बाराबती स्टेडियम की पिच भी विशाखापत्तनम की तरह बल्लेबाजों की मददगार होगी। हेटमायर और होप ने चेन्नई में भारतीय गेंदबाजों को दबाव में रखा था और दूसरे मैच में अय्यर का बेहतरीन थ्रो नहीं होता तो वह एक बार फिर बड़ी पारी खेल जाते।

हेटमायर, होप और कॉटरेल हैं फॉर्म में: आइपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने हेटमायर को 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा। उनके साथी शेल्डन कॉटरेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने 8.5 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं इस साल रोहित के बाद सर्वाधिक रन बना चुके होप पर किसी ने बोली नहीं लगाई और वह इस मैच में बड़ी पारी खेलकर अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे। कीरोन पोलार्ड की टीम ने पहले दो वनडे में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अब देखना है यहां दोनों कप्तान क्या करते हैं।

13 वर्ष से नहीं जीता है वेस्टइंडीज: यहां भी ओस को ध्यान में रखकर टीमें दूसरी पारी में गेंदबाजी से बचना चाहेंगी। वेस्टइंडीज टीम इस प्रयास में होगी कि भारत से 13 साल बाद कोई द्विपक्षीय सीरीज जीत सके। मार्च में ऑस्ट्रेलिया से द्विपक्षीय सीरीज हारी भारतीय टीम ने पिछले 15 साल में लगातार दो द्विपक्षीय सीरीज नहीं गंवाई हैं।

टीमें: भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्रा सिंह चहल, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, मुहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर।

वेस्टइंडीज : कीरोन पोलार्ड (कप्तान), सुनील अंबरीश, शाई होप, खैरी पियरे, रोस्टन चेस, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कॉटरेल, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमायर, इविन लुइस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, कीमो पॉल और हेडन वाल्श जूनियर।

मौजूदा भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण सर्वश्रेष्ठ : स्टेन

जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने मौजूदा समय में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी ईकाई बताया है। स्टेन को भी आइपीएल 2020 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर ने खरीदा है। ट्विटर पर एक यूजर ने पूछा कि मौजूदा समय में कौनसा गेंदबाजी आक्रमण सर्वश्रेष्ठ है तो स्टेन ने भारतीय टीम के पक्ष में अपना मत दिया। साथ ही उनसे जब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का नाम लिया। स्टेन को नीलामी में पहले दो बार किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, लेकिन बाद में बेंगलूर ने उन्हें दो करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर अपने साथ जोड़ा। उन्होंने पिछले सत्र में आरसीबी के लिए केवल दो ही मैच खेले थे।

2006 के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं हारी है टीम इंडिया। पिछली बार वेस्टइंडीज ने अपने घर में 2006 में भारत को पांच मैचों की सीरीज में 4-1 से हराया था

100 विकेट वनडे में लेने से एक विकेट दूर हैं भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप ने अभी तक 54 वनडे में 99 विकेट लिए हैं। 24 वर्षीय कुलदीप वनडे में 100 विकेट लेने वाले 22वें भारतीय बन जाएंगे, वहीं भारतीय स्पिनरों में वह आठवें गेंदबाज बनेंगे

100 विकेट सबसे तेज लेने के मामले में अभी भारतीय गेंदबाजों में मुहम्मद शमी सबसे आगे हैं। अगर कुलदीप इस मुकाबले में एक विकेट ले लेते हैं तो वह शमी के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे

56 रन बनाते ही वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सातवें नंबर पर आ जाएंगे विराट कोहली। कोहली के फिलहाल 11,524 रन हैं। वह 56 रन बनाते ही जैक कैलिस को पीछे छोड़ देंगे जिनके 11,579 रन हैं

24 मुकाबले जीते और मात्र नौ मुकाबले भारतीय टीम हारी जब भी कुलदीप यादव और युजवेंद्र सिंह चहल मैच खेलने एक साथ उतरे हैं

कटक में शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान कप्तान विराट कोहली ● एएफपी

2005 अप्रैल में भारतीय टीम ने पिछली बार घर में दो लगातार द्विपक्षीय सीरीज हारी थी। तब पाकिस्तान ने भारत को 4-2 से शिकस्त दी थी। इससे पहले वेस्टइंडीज उन्हें 4-3 से हरा चुका था। अगर वेस्टइंडीज यह मैच जीतता है तो टीम इंडिया 17 साल बाद घर में लगातार दूसरी वनडे सीरीज हारेगा

मैं शुरुआत में गैर जिम्मेदार था : अय्यर

कटक, प्रेट्र : भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने शनिवार को कहा कि अपने करियर की शुरुआत में वह इतने जिम्मेदार नहीं थे लेकिन अब अपने खेल को बखूबी समझते हैं। लंबे समय से भारतीय टीम की समस्या रहे बल्लेबाजी के चौथे नंबर पर अय्यर अपनी दावेदारी पुख्ता करते जा रहे हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने पहले दो वनडे में अर्धशतक जमाए। उन्होंने तीसरे वनडे से पहले कहा कि वह परिपक्वता और जिम्मेदारी से आता है। प्रथम श्रेणी करियर के दौर में मैं आक्रामक था और कभी जिम्मेदारी नहीं लेता था। उन्होंने कहा कि बाद में मुझे लगा कि उच्चतम स्तर पर खेलने के बाद परिपक्वता जरूरी है। मैं स्ट्राइक भी लगा सकता हूं और एक रन भी ले सकता हूं। मैं अपने खेल को बखूबी समझता हूं।

मैच का नतीजा हमारे लक्ष्य को नहीं भटकाएगा : सिमंस

कटक : वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस को लगता है कि टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शायद भारतीय टीम को तीसरे मुकाबले में हराने के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन मैच का नतीजा कैरेबियाई टीम के लक्ष्य को नहीं भटकने देगा। सिमंस वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं, जिन्हें दोबारा से वेस्टइंडीज का कोच बनाया गया है। वेस्टइंडीज की टीम ने चेन्नई में खेले गए पहले वनडे में शानदार खेल दिखाया था। सिमंस ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सभी लड़के जानते हैं कि रविवार को उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। हो सकता है कि हम जीत ना पाएं। कोच ने कहा कि कुछ चीजों को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और रविवार का मुकाबला हमारे लक्ष्य को नहीं भटकने देगा। हम टीम को एक सही दिशा देना चाहते हैं और हम इसमें कामयाब रहेंगे। हालांकि टीम के लिए सकारात्मक चीज यह है कि उनकी टीम का बल्लेबाज जो आइसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल है वह एक अच्छी फॉर्म में है। शाई होप और शिमरोन हेटमायर दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको अगर मैच जीतना है तो आपको 300, 320 तक स्कोर करना होता है, खासतौर पर भारतीय टीम के खिलाफ। ऐसे में आपको 320 या उससे ज्यादा का स्कोर करना ही पड़ेगा।

दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में धौनी, कोहली और रोहित

नई दिल्ली, जेएनएन: भारत के तीन धुरंधर बल्लेबाज पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धौनी, ओपनर रोहित शर्मा और विश्व के नंबर एक बल्लेबाज विराट कोहली को विजडन की दशक (2009-19) की वनडे टीम में जगह दी गई है।

विजडन ने 11 खिलाड़ियों की लिस्ट में यही तीन भारतीय शामिल हैं। रोहित को जहां ओपनर के तौर पर जगह मिली है तो विराट को तीसरे नंबर पर रखा गया है। फिलहाल भारतीय टीम से बाहर आराम फरमा रहे धौनी को विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। रोहित के साथ ओपनिंग में ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर शामिल हैं। बता दें कि रोहित ने वनडे करियर में अब तक 179 मैचों में 8186 रन बनाए हैं। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम 109 मैचों में 4884 रन हैं। कोहली ने एकादश में तीसरा स्थान पर हासिल किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को चौथे नंबर पर रखा गा है। कोहली के नाम 226 मैचों में 11040 रन और डिविलियर्स के नाम 6485 रन दर्ज हैं। इस लिस्ट में चौंकाने वाला नाम इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर का है। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन भी इस टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज लसिथ मलिंगा, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने एकादश में जगह पाई है।

विजडन एकादश : रोहित शर्मा, डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, जोश बटलर, एमएस धौनी, शाकिब अल हसन, लसिथ मलिंगा, मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बेल्ट, डेल स्टेन।

शांत और ज्यादा चतुर गेंदबाज हो गए हैं शमी

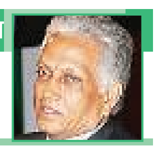

मोहिंदर अमरनाथ
रिवर्स स्वीप

रोहित ने जिस तरह विशाखापत्तनम में बल्लेबाजी की उसे देखना अलग ही है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बराबरी हासिल की जहां उसके सलामी बल्लेबाज ने एक और शानदार शतक लगाया। चूंकि अब यह सीरीज निर्णायक मुकाबले तक पहुंच चुकी है, ऐसे में यह स्पष्ट है कि वेस्टइंडीज को सीरीज जीतने का तभी मौका मिलेगा जब उनका लक्ष्य 300 से कम हो। पिछले मुकाबले में उसके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे थे और अगर तीसरे वनडे में उनकी जरूरत पड़ी तो उन्हें खासतौर से डेथ ओवरों में बेहतर करने की जरूरत होगी। पिछले मुकाबले में वे एक ही लाइन और गति के साथ बिना किसी विविधता के गेंदबाजी कर रहे थे। विशाखापत्तनम की तरह यहां भी विकेट से कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यह भी एक ठोस विकेट है।

वहीं भारत के पास खुश होने के कई कारण हैं। कुलदीप यादव की हैट्रिक एक खास मामला है। जब एक विशाल स्कोर का बचाव करना हो तो एक गेंदबाज के लिए चतुर और प्रयोगात्मक होना आसान होता है। यादव भारत की दो स्पिनर रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मुहम्मद शमी भी तारीफ के हकदार हैं, क्योंकि एक ओवर में उनकी दोहरी सफलता ने उनकी साझेदारी को रोकने का काम किया था। वास्तव में शमी कुछ महीने पहले जैसे गेंदबाज थे अब उससे बेहतर शांत और ज्यादा चतुर गेंदबाज हैं। ये टीम के लिए अच्छा संकेत है।

वेस्टइंडीज के लिए वास्तव में उनकी गेंदबाजी चिंता का विषय है। विशेष रूप से भारत की मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप के खिलाफ गति परिवर्तन और सही लेंथ को हासिल करना अहम है। उसके लिए सबसे अच्छा मौका यह होगा कि वे पहले बल्लेबाजी करें और अपने बिग हिटर्स बल्लेबाजों के दम पर एक विशाल स्कोर खड़ा करें या फिर पहले वनडे की तरह मजबूत साझेदारी करें। भारत को वैसा ही प्रदर्शन करना होगा जैसा उसने पिछले मैच में किया था। विराट कोहली ने ना तो पहले और ना ही दूसरे वनडे में रन बनाए। उनके लिए अच्छी लय में आने और सीरीज को अपने पक्ष में करने का अच्छा समय हो सकता है। यह संभवतः वनडे क्रिकेट में उनका पहला गोल्डन डक था और वह निश्चित रूप से बाराबती स्टेडियम में अपने खराब रिकॉर्ड से बचना चाहेंगे।

#WhatDrivesYou
EXIDE

सीमित ओवरों के क्रिकेट पर ही ध्यान दें राहुल

के श्रीकांत
कलम से

अच्छी टीमें दबदबे के साथ वापसी दर्ज कराती हैं और भारतीय टीम ने विशाखापत्तनम में ठीक ऐसा ही किया। टीम इंडिया ने बल्ले से निर्दयता के साथ प्रदर्शन किया तो गेंदबाजी और फील्डिंग विभाग भी अपनी भूमिका निभाने में सफल साबित हुआ। ये बेहतरीन प्रदर्शन था, जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था। इसका ये भी मतलब हुआ कि अब निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर दावेदार के तौर पर मैदान में उतरेगी। रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच हुई दोहरी शतकीय साझेदारी देखना मजेदार रहा। उम्मीद है कि ये जोड़ी सीमित ओवर प्रारूप के सभी मैचों में बनी रहे। दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे को पूरा करते हैं और दोनों ही उच्च स्तर का क्रिकेट खेलते हैं। यही वजह है कि इनके खिलाफ गेंदबाजी करना कभी भी आसान काम नहीं होता।

अगर आप रोहित शर्मा और केएल राहुल के स्कोरिंग क्षेत्रों को देखें तो समझ पाएंगे कि दोनों खिलाड़ियों के शॉट्स की रेंज कितनी अलग और कितनी विशाल है। जहां रोहित शर्मा पुल शॉट बढ़िया तरीके से खेलते हैं तो वहीं स्पिनरों के खिलाफ उनके सिर के ऊपर से शॉट खेलने को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी ओर, राहुल कट और फ्लिक अच्छा करते हैं। एक पूर्व ओपनर होने के नाते मैं इन दोनों खिलाड़ियों को लंबे समय तक साथ खेलते हुए देखना चाहता हूं। राहुल प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं कि तीनों प्रारूपों में किस तरह खेलें। टीम की भलाई के लिए उन्हें ये बात बताई जानी चाहिए कि थोड़े समय के लिए वह टेस्ट का मोह छोड़कर सीमित ओवर प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें पर्याप्त मौके दिए जाने चाहिए ताकि वह मैदान पर उतरकर अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकें।

कटक में भारतीय गेंदबाजों का भी टेस्ट होगा। ऐसे में एक बार फिर भार बल्लेबाजों पर ही होगा। पहले या बाद में बल्लेबाजी से अधिक अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी टीम बढ़िया बल्लेबाजी करेगी, सीरीज उसी के नाम होगी। दूसरी तरफ ये भारतीय स्पिनरों के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। विजयी टीम से छेड़छाड़ करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर केदार जाधव की जगह युजवेंद्रा सिंह चहल को शामिल किया जाता है तो ये खराब विचार नहीं है। खासतौर पर जब तब छठे नंबर पर जाधव को बल्लेबाजी के लिए अधिक मौके नहीं मिलते हैं। चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों से मुश्किल सवाल पूछ सकती है।

आज के मैच में ACC KAMAAL ka MOMENT कौन जीतेगा?
वोट करने के लिए, लॉग ऑन करें facebook.com/accind
ACC OFFICIAL PARTNER

एक नजर में

संधू 11वें स्थान पर

पटाया (थाइलैंड): भारतीय गोल्फर अजितेश संधू ने सत्र के आखिरी थाइलैंड मास्टर्स के तीसरे दौर में एक अंडर 70 का स्कोर करके संयुक्त 11वां स्थान हासिल किया। चंडीगढ़ के 31 वर्षीय इस गोल्फर ने तीन बर्डी लगाई और दो बोगी भी की। उनका कुल स्कोर 10 अंडर 203 रहा। वह नौ अन्य के साथ संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। अर्जुन अटवाल सात अंडर 64 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 21वें स्थान पर रहे। एसएस पी चौररसिया, ज्योति रंधावा और आदिल बेदी संयुक्त 47वें स्थान पर रहे। (प्रेट्र)

मार्टिनेज ने जीता खिताब

लास एंजिलिस: मेक्सिको के जूलियो सीजर मार्टिनेज ने निकारागुआ के क्रिस्टोफर रोसालेस को नौवें राउंड में रोककर विश्व मुक्केबाजी काउंसिल (डब्ल्यूबीसी) के फ्लाइवेट वर्ग का खिताब हासिल किया। 2015 में अपना पेशेवर पदार्पण छोड़ने के बाद मार्टिनेज ने लगातार 15 बाउट जीती हैं। हालांकि उन्हें डब्ल्यूबीसी खिताब जीतने के लिए दो बार प्रयास करना पड़ा। (एएफपी)

अलग दिखना चाहते हैं लैंपार्ड

लंदन: इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी के मैनेजर फ्रैंक लैंपार्ड का कहना है कि वह अपने पूर्व और टॉटनहम के मौजूदा मैनेजर जोस मौरिन्हो के क्लोन की तरह नहीं दिखना चाहते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में रविवार को चेल्सी और टॉटनहम की अहम भिड़ंत होनी है और इस मुकाबले से तय होगा कि लंदन के इन दोनों क्लबों में से कौन क्रिसमस की छुट्टियां शीर्ष चार में रहते मनाएगा। यह पहला मौका होगा जब लैंपार्ड और मौरिन्हो ईपीएल में आमने-सामने होंगे। मौरिन्हो चेल्सी के मैनेजर रह चुके हैं और वह लैंपार्ड को इस क्लब के सबसे सफल खिलाड़ी बनते देख चुके हैं। लैंपार्ड ने कहा कि मौरिन्हो एक अच्छे मैनेजर हैं लेकिन उनके मार्गदर्शन में मैंने कोई एक खास चीज नहीं सीखी और मैं किसी के क्लोन की तरह नहीं पेश आना चाहूंगा। (एएफपी)

अमेरिकी ओलंपियन भारत में

पुणे : अमेरिकी ओलंपियन जेनेट चेरोबोन-बावकॉम की अगुआई में करीब 20,000 धावक रविवार को यहां आयोजित होने वाले पुणे हाफ मैराथन में हिस्सा लेंगे। जेनेट इस हाफ मैराथन की ब्रांड एंबेसडर भी हैं। मैराथन का आयोजन शहर में बालवाड़ी स्टेडियम में सुबह सवा पांच बजे से होगा। (जेएनएन)

अगले सत्र की तारीख देख फ्रेंचाइजियों की नींद उड़ी

आइपीएल डायरी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) आइपीएल के अगले सत्र की शुरुआत 28 मार्च से करना चाहती है, लेकिन फ्रेंचाइजियों का कहना है कि इस दौरान दो बड़ी सीरीज हैं, जिसके कारण विदेशी खिलाड़ियों को आने में समस्या हो सकती है। यहां बताना जरूरी है कि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेंगे जबकि इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें दो टेस्ट मैच खेलेंगी।

एक फ्रेंचाइजी के सीनियर अधिकारी ने कहा कि आधिकारिक कैलेंडर अभी निकला नहीं है लेकिन वह उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं कि गवर्निंग काउंसिल अपने पुराने प्रारूप पर ही जाएगी, जिसमें डबल हेडर होते थे और लीग एक अप्रैल के पास से शुरू होती थी। अधिकारी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज का अंतिम टी-20 मैच 29 मार्च को खत्म होगा जबकि इंग्लैंड और श्रीलंका के दूसरे टेस्ट का आखिरी दिन 31 मार्च है। इस स्थिति में आप सत्र की शुरुआत अपने बड़े खिलाड़ियों के बिना करोगे और यह अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम एक अप्रैल से शुरू करते हैं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद है, आइपीएल गवर्निंग काउंसिल हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देगी। एक अन्य फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा कि नीलामी की शाम को बैठक के दौरान चार फ्रेंचाइजियों ने इस मुद्दे को उठाया है। अधिकारी ने कहा कि देखिए, यह ऐसी स्थिति है जो फ्रेंचाइजियों के पक्ष में नहीं जा रही है और इस मुद्दे पर चार से पांच टीमों के बीच चर्चा भी की गई थी। कोई भी बैकफुट पर शुरुआत नहीं करना चाहता, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। कैलेंडर के आने से पहले हमारे पास अभी कुछ सप्ताह बाकी हैं। हम अपील कर सकते हैं।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पिछले साल, हमारे खिलाड़ी अंत में चले गए थे और इस बार हम अपने शीर्ष-4 खिलाड़ियों के बिना सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। इस पर आइपीएल गवर्निंग काउंसिल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम अच्छी शुरुआत करना पसंद करेंगे और सत्र की शुरुआत में अच्छी लय हासिल करना चाहेंगे। आइपीएल के आने वाले सत्र की तारिखों पर फैसला गवर्निंग काउंसिल को ही लेना है कि वह मार्च 28 से लीग की शुरुआत करना चाहती है या एक अप्रैल से।

चेन्नई में धौनी और फ्लेमिंग से सीखने का मौका मिलेगा : कुर्रन

चेन्नई : इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुर्रन ने चेन्नई सुपरकिंग्स में चुने जाने को कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग के दिमाग से 'सीखने का मौका' बताया है। आइपीएल नीलामी में इंग्लैंड के सबसे महंगे खिलाड़ी बने करन को चेन्नई टीम ने साढ़े पांच करोड़ रुपये में खरीदा। चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लगी थी। कुर्रन ने अपनी नई टीम द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि चेन्नई आकर अपने नए साथियों से मिलने, कप्तान धौनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मिलने को बेताब हूं। मेरे लिए यह उनसे सीखने का सुनहरा मौका है और उम्मीद है कि हम ट्रॉफी जीतेंगे। कुर्रन पिछले सत्र में किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा थे जिन्होंने एक हैट्रिक भी लगाई थी। टीम ने उन्हें नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था।

ट्विटर पर भिड़े पार्थिव पटेल और डीन जोंस

नई दिल्ली : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर में आरोन फिंच के शामिल होने के बाद पार्थिव पटेल और डीन जोंस आपस में भिड़ गए। डीन जोंस ने ट्विटर पर लिखा कि पार्थिव खुशकिस्मत हैं कि उन्हें आने वाले आइपीएल में फिंच के साथ ओपनिंग करने का मौका मिलेगा। वह आपसे लंबे हैं। पार्थिव ने जवाब दिया कि मुझे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ काम करना पसंद हैं। आरोन फिंच भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में आपसे ज्यादा समय बिताते हैं डीन जोंस। शुक्र है भगवान का आप क्रिसमस पर तो घर जा रहे हैं।

तिवारी के चयनित नहीं होने पर भड़के मुरली कार्तिक

नई दिल्ली : पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक ने आइपीएल में मनोज तिवारी का चयन नहीं होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। गुरुवार को हुई नीलामी में तिवारी के अलावा प्रज्ञान ओझा और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ जैसे खिलाड़ियों को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। कार्तिक ने ट्वीट में लिखा कि मैं ज्यादा ट्वीट नहीं करता हूं, लेकिन पिछली नीलामी से मैं कुछ सोच रहा हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि मनोज तिवारी जैसे खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने क्यों नहीं चुना। इन खिलाड़ियों ने जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए खेला उनके लिए सबकुछ किया है। ऐसे ही कुछ ओझा और बद्रीनाथ भी हैं।

टायसन ने मानी सेरेना विलियम्स से हार

नई दिल्ली, जेएनएन : पूर्व हेवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन माइक टायसन और दिग्गज अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स के मुक्केबाजी सत्र के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

सेरेना साल के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस सिलसिले में वह टायसन के साथ एक मुक्केबाजी सत्र में हिस्सा लेने फ्लोरिडा के बोका रेटन में पहुंचीं जिसमें वह अपने हाथों के तालमेल बनाने के लिए अभ्यास किया। यह सेरेना की तैयारियों का हिस्सा है। सेरेना के अलावा टायसन ने भी इस अभ्यास सत्र के वीडियो और फोटो अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा किए। इस दौरान टायसन ने कैप्शन लिखा कि उन्हें सेरेना से मुक्केबाजी करने में डर लगता है। इस अभ्यास सत्र में अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी कोरी गॉफ भी पहुंचीं थीं।

अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने महान मुक्केबाज माइक टायसन के साथ मुक्केबाजी सत्र की यह फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है ● इंस्टाग्राम

दस्त के कारण टिशू पेपर के साथ विश्व कप में उतरे थे सचिन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: 2003 विश्व कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब जीतने से चूक गई। इस विश्व कप में तेंदुलकर ने 673 रन बनाए थे जो किसी भी खिलाड़ी का एक विश्व कप में सबसे अधिक रन का रिकॉर्ड है मगर क्या आपको पता है कि टूर्नामेंट के कुछ अहम मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर गंभीर रूप से बीमार थे।

दिग्गज बल्लेबाज तेंदुलकर की 2003 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 98 रन की शानदार पारी का हर भारतीय मुरीद है, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि इस मैच में खिंचाव की परेशानी का सामना करने वाले मास्टर ब्लास्टर ने गंभीर रूप से दस्त (डायरिया) से पीड़ित होने के बावजूद भी श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच में मैदान में उतरकर अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाला था। तेंदुलकर की वह पारी प्रशंसकों को याद है, लेकिन पाकिस्तान और फिर श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान इस भारतीय बल्लेबाज को जो परेशानी झेलनी पड़ी उसके बारे में कम लोगों को ही पता है। सचिन श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान गंभीर रूप से दस्त से जूझ रहे थे और उससे निपटने के लिए उन्हें टिशू पेपर का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने इस मैच में 97 रन बनाए थे, जिसे भारत ने 183 रन से जीता था।

मास्टर ब्लास्टर ने एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वह मैच मेरे करियर का एकमात्र ऐसा मुकाबला था जिसमें मैंने रनर लिया था। यह विश्व कप का मैच था और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझमें 500 किलोग्राम वजन बांध दिया हो। आप हमारे तत्कालीन फिजियो एंड्रयू लीपस से इस बारे में पूछ सकते हैं। मैं चोट से परेशान था। मैं तेजी से सिंगल ले रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था, लेकिन तभी मेरी नस खिंच गई। मैं खड़ा होना चाह रहा था लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। श्रीलंका से मैच से पहले, मैंने चोट से उबरने के लिए काफी दवाई ले ली थी। इसी वजह से मुझे अगले मुकाबले में पेट की समस्या हो गई। मैं अगले मैच में चोट की समस्या नहीं चाहता था। ऐसे में मैंने बहुत सारा नमक का पानी पी लिया और इसकी वजह से मुझे दस्त हो गए। तेंदुलकर ने कहा कि ये कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनका आप मैदान में सामना करते हो। यह कोई फर्क नहीं करता कि आप बल्लेबाजी कर सकते हो या नहीं। मैं हमेशा मैदान पर जाना चाहता था।

सचिन तेंदुलकर ● फाइल फोटो, ट्विटर

2003 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ दस्त से जूझ रहे थे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज

फुटबॉल डायरी | बुंडिशलीगा में होफेनहीम ने 2-1 से हराया, विजेता टीम के लिए एडमयान और क्रेमेरिक ने दागे गोल

शुरुआती बढ़त के बावजूद हारा डोर्टमंड

बर्लिन, एएफपी : सर्गिस एडमयान और आंद्रेज क्रेमेरिक द्वारा अंतिम लम्हों में किए गए दो गोल की बदौलत होफेनहीम ने जर्मन फुटबॉल लीग बुंडिशलीगा में बोरुसिया डोर्टमंड को 2-1 से हरा दिया। शुरुआती बढ़त लेने के बावजूद मिली इस हार से डोर्टमंड को तालिका में शीर्ष स्थान के करीब पहुंचने की उम्मीदों झटका लगा।

खेल के 16वें मिनट में मारियो गोट्जे ने गोल करके डोर्टमंड को शुरुआती बढ़त दिलाई। गोट्जे को इस महीने पहली बार शुरुआती लाइन-अप में जगह दी गई और जल्दी ही उन्हें इसका असर दिखाया। कप्तान मार्को रीउस के चोटिल होकर जनवरी तक बाहर होने की वजह से डोर्टमंड के मैनेजर लुसेन फावरे ने गोट्जे को आक्रमण पर लगाया। इसके बाद हाफ टाइम से छह मिनट पहले थॉर्गन हैजार्ड के पास डोर्टमंड को दोहरी बढ़त दिलाने का मौका मिला लेकिन वह विरोधी टीम के गोलकीपर को चकमा नहीं दे पाए। इसके बाद दूसरे हाफ में एडमयान (79वें मिनट) और क्रेमेरिक (87वें मिनट) ने आखिरी मिनटों में जल्दी-जल्दी दो गोल करके होफेनहीम को शानदार जीत दिलाई। इस हार पर डोर्टमंड के जूलियन ब्रांड्ट ने कहा कि इस मुकाबले के बाद मैं मरने नहीं जा रहा हूं लेकिन हर जीत से तकलीफ पहुंचती है।

बुंडिशलीगा फुटबॉल लीग में डोर्टमंड के खिलाफ गोल करने के बाद जश्न मनाते होफेनहीम के सर्गिस एडमयान ● एएफपी

नए क्लब से जुड़ने पर पोचेटिनो की निगाहें: हाल ही में टॉटनहम के मैनेजर के पद से हटाए गए मॉरिसियो पोचेटिनो ने कहा है कि वह प्रबंधन में आई अस्थिरता को अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी निगाहें एक नए क्लब के साथ डगआउट में वापसी करने पर है। एक साक्षात्कार में पोचेटिनो ने कहा कि टॉटनहम के साथ साढे पांच साल बहुत मुश्किल थे। सफर शानदार रहा था। जो हुआ उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए टॉटनहम के साथ जुड़ना सम्मान की बात थी।

रोमा ने फियोरेंटीना को हराया: इटालियन फुटबॉल लीग सीरी-ए में रोमा ने फियोरेंटीना को 4-1 से हराकर चैंपियंस लीग की पात्रता हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ाए। इस दौरान रोमा के एलेक्जेंडर कोलारोव ने फ्री किक के जरिये एक शानदार गोल किया। उनके अलावा रोमा की ओर से ईडन जेको, लोरेंजो पेलेग्रिनी और निकोलो जेनिओलो ने भी स्कोर किए। जेको ने इस दौरान मौजूदा सत्र का सातवां गोल दागा।

रैली चालक गौरव गिल ने पहले दिन दिखाई चमक

कोटयम, आइएएनएस : भारत के शीर्ष रैली चालक गौरव गिल ने शनिवार को चैंपियंस याच क्लब एफएमएससीआइ इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप के अंतिम राउंड के पहले दिन ट्रैक पर अपनी चमक दिखाई। गौरव ने छह सुपर स्टेजों में जीत हासिल की। उनकी इस सफलता के बाद आइएनआरसी रोमांचक समापन की ओर बढ़ता दिख रहा है। जेके टायर चालक गिल ने अपने साथी चालक मूसा शरीफ के साथ शानदार शुरुआत की।

मेरी नजर टी-20 विश्व कप पर है। इसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, उम्मीद है इसमें मैं अच्छा करुंगा।
– ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

मसूद, अली की रिकॉर्ड साझेदार, पाक मजबूत

दूसरा टेस्ट ▶ मेजबान टीम ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए 315 रन

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाक ने बनाए दो विकेट पर 395 रन

174 रन बनाए आबिद ने अपने करियर के दूसरे टेस्ट में। पहले टेस्ट में भी शतक लगाने वाले आबिद पाक के पहले और दुनिया के नौंवे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने पहले दो टेस्ट में शतक लगाए

278 रन की ओपनिंग साझेदारी की आबिद और मसूद ने। यह टेस्ट में पाक की ओर से पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। रिकॉर्ड आमिर सोहेल और एजाज अहमद के नाम है जिन्होंने 298 रन की साझेदारी की थी

02 सर्वश्रेष्ठ पहले विकेट की साझेदारी जो टेस्ट की तीसरी पारी में हुई हैं। उनमें से एक मसूद और अली के बीच रही। पहले नंबर पर बांग्लादेश के इमरुल कायेस और तमीम इकबाल हैं जिन्होंने पाक के खिलाफ 312 रन की साझेदारी की थी

278 रन की पहले विकेट के लिए साझेदारी टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा की गई सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 255 रन की साझेदारी पहले मैथ्यू हेडन और जस्टिन लेंगर ने श्रीलंका के खिलाफ की थी

कराची, एएफपी : आबिद अली (174) और शान मसूद (135) की सलामी जोड़ी की रिकॉर्ड साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने दो विकेट के नुकसान 395 रन बना लिए हैं। कप्तान अजहर अली 57 रन और बाबर आजम 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने इसी के साथ श्रीलंका पर 315 रनों की बढ़त ले ली है।

मसूद और अली ने पहले विकेट के लिए 278 रनों की साझेदारी की। यह पाकिस्तान के लिए पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस साझेदारी को लाहिरू कुमारा ने तोड़ा। उन्होंने मसूद को विश्व फर्नांडो के हाथों कैच कराया। मसूद ने अपनी पारी में 198 गेंदों का सामना किया और सात चौके तथा तीन छक्के लगाए।

कुमारा ने ही 355 के कुल स्कोर पर आबिद अली को आउट किया। आबिद ने 281 गेंदों की पारी में 21 चौके और एक छक्का लगाया। अली का यह करियर का दूसरा टेस्ट मैच है। उन्होंने रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट से खेल के लंबे प्रारूप में पदार्पण किया था और शतक जमाया था। इसी के साथ अली ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बराबरी कर ली है। वह पहले दो टेस्ट मैचों में शतक जमाने वाले कुल नौवें और पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले गांगुली, मुहम्मद अजहरुद्दीन, रोहित शर्मा, एलविन कालीचरण, जिम्मी निशाम भी ऐसा कर चुके हैं। हालांकि अजहरुद्दीन ने लगातार तीन टेस्ट में खत्म किया था।

मसूद और अली द्वारा दी गई शुरुआत को अजहर और आजम ने बनाए रखा है। इन दोनों के बीच अभी तक 40 रनों की साझेदारी हो चुकी है। अजहर 103 गेंदों का सामना कर चार चौके लगा चुके हैं जबकि आजम ने 42 गेंदों का सामना किया है और एक शतक जमाया है। पाकिस्तान अपनी पहली पारी में 191 रनों पर ही ढेर हो गई थी। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 271 रन बना उस पर 80 रनों की बढ़त ले ली थी।

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन शतक लगाने के बाद जश्न मनाते पाकिस्तानी बल्लेबाज आबिद अली। प्रेट्र

खेल का उत्साह...

टोक्यो ओलंपिक का उदघाटन समारोह जिस नए स्टेडियम में होगा। उसमें शनिवार को पहली बार मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान वे काफी उत्साह में नजर आए। एएफपी

धुएं के कारण एडिलेड स्ट्राइकर्स–सिडनी थंडर्स बीबीएल मैच रद

कैनबरा, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में जंगलों में लगी भयानक आग के कारण उठे धुएं के चलते बिग बैश लीग (बीबीएल) में यहां एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर्स के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के अनुसार, एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर्स के बीच होने वाला मैच शनिवार शाम को यहां मनुका ओवल मैदान पर खेला जाना था, लेकिन भारी धुएं के कारण मैच को रद करने का फैसला किया गया। अंपायरों ने माना कि कैनबरा का धुआं बेहद खतरनाक है और ऐसी स्थिति में मैच आगे नहीं हो सकता है।

न्यू साउथ वेल्स साउथ कोस्ट में लगी भनायक आग के कारण पूरा कैनबरा धुएं से ढका हुआ था। लेकिन स्थानीय समयानुसार छह बजकर 10 मिनट पर मैच शुरू होने के समय तक माहौल सही था। इसके बाद वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण मैच को करीब दो घंटे देरी से शुरू किया गया। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 20 ओवरों में पांच विकेट पर 161 रन का स्कोर बनाया। इसके बाद जब सिडनी थंडर्स बल्लेबाजी करने आई तो उसने 4.2 ओवरों में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। चार गेंदें और फेंकी जाती तो डकवर्थ लुइस नियम के तहत मैच का मैच का परिणाम निकल सकता था लेकिन उससे पहले ही अंपायर सैम नोगाच्सकी और पॉल विल्सन ने खेल को रोके जाने का फैसला किया। अंपायर विल्सन ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि थंडर्स मैच का परिणाम आने के लिए थंडर्स को चार गेंदों की जरूरत थी, लेकिन हम जोखिम नहीं ले सकते। यह वायु गुणवत्ता की बात थी और ऐसे हालात में खेल शुरू नहीं हो सकता।

आइओसी प्रमुख ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद

ओलंपिक डायरी

▶ संयुक्त राष्ट्र ओलंपिक संधि प्रस्ताव का सह प्रायोजन करने के लिए बाक ने दिया धन्यवाद

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के प्रमुख थॉमस बाक ने संयुक्त राष्ट्र ओलंपिक संधि प्रस्ताव का सह प्रायोजन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

प्रस्ताव के तहत हर तरह के वैमनस्य को भुलाकर टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स 2020 में खिलाड़ियों और दर्शकों की भागीदारी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। बाक ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, 'मैं संयुक्त राष्ट्र संधि प्रस्ताव का सह प्रायोजन करके ओलंपिक गेम्स को आपकी सरकार के सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।' यह प्रस्ताव नौ दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में स्वीकार किया गया था।

सर्फिंग के महान खिलाड़ी स्लेटर टोक्यो ओलंपिक में नहीं लेगें भाग

लास एंजिलिस : सर्फिंग के महान खिलाड़ी केली स्लेटर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे। स्लेटर को सर्फिंग की दुनिया का सबसे सफल खिलाड़ी माना जाता है। 47 वर्षीय स्लेटर अमेरिका की टीम में जगह बनाने के करीब थे लेकिन घुटने की चोट से वापसी करने वाले जॉन फ्लोरेंस की वजह से स्लेटर को जगह नहीं मिल पाई।

ओलंपिक में पहली बार सर्फिंग को इस बार शामिल किया गया है। स्लेटर 11 बार के विश्व चैंपियन हैं और वह विश्व खिताब जीतने वाले सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी भी हैं। सात साल की उम्र से सर्फिंग करने वाले स्लेटर ने कहा कि मैं इस खेल का ओलंपिक में बतौर दर्शक आनंद उठाऊंगा।

ओलंपिक के ट्रैक पर उतरे बोल्ट

टोक्यो : संन्यास ले चुके जमैका के महान फर्राटा धावक उसेन बोल्ट बेशक 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले रहे हों लेकिन शनिवार को उन्होंने ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टोक्यो ओलंपिक के लिए बने नए नेशनल स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर आयोजित 200 मीटर की एक प्रदर्शनी रिले दौड़ में बोल्ट पैरालंपिक एथलीटों के साथ दौड़ते नजर आए। करीब 60 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम में पहली बार सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया। ड्रम के साथ इस प्रदर्शनी मैच के लिए आए प्रतियोगियों का स्वागत किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा शोर बोल्ट के आने पर ही नहीं बल्कि जापान की रग्बी टीम की कप्तान माइकल लिच के आगमन पर हुआ। इस मौके पर बोल्ट ने कहा कि इतने सारे लोगों के बीच दौड़ना मेरे लिए यह शानदार अनुभव रहा। मैं खुश हूं क्योंकि मुझे ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिलेगा।

टोक्यो के लिए क्वालीफाई करने पर नटराज की निगाहें

नई दिल्ली : तैराकी में 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर बैकस्ट्रोक और 200 मीटर बैकस्ट्रोक के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी श्रीहरि नटराज ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है। वह इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'मैं फिलहाल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश में हूं। इसके बाद मेरा लक्ष्य एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक 2024 में पदक जीतना है।' नटराज ने यह भी कहा कि खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स अच्छी पहल है। पहले दो सत्र में भाग ले चुके नटराज फिलहाल गुवाहाटी में 10 से 22 जनवरी तक होने वाले इन खेलों की तैयारी में जुटे हैं। दो साल की उम्र से तैराकी करने वाले नटराज ने खेलो इंडिया के पहले सत्र में छह स्वर्ण और एक रजत जबकि दूसरे सत्र में सात स्वर्ण अपने नाम किए थे।

विविध

राम मंदिर निर्माण के लिए रामालय न्यास को जमीन सौंप दे केंद्र

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को रामालय न्यास को जमीन सौंप देनी चाहिए। राम मंदिर में सोने से बनी भगवान राम की प्रतिमा भी विराजमान होगी। शंकराचार्य ने उत्तराखंड सरकार के चारधाम प्रबंधन बोर्ड बनाने को धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बताया।

गांधीनगर में आयोजित भारत साधु समाज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण सहित अन्य धार्मिक व सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय प्रगट की। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अब सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए रामालय न्यास को जमीन सौंप देनी चाहिए। शंकराचार्य ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि रामालय न्यास में देश की चारों पीठ के शंकराचार्य, पांच वैष्णव आचार्य, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, आचार्य सभा व राम मंदिर के मुख्य पुजारी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण तक भगवान राम की स्वर्ण प्रतिमा भी बनकर तैयार हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत दिनों यह घोषणा भी की थी कि चार माह में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।

धार्मिक सम्मेलन में शंकराचार्य के अलावा देशभर से आए साधु संत, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया जिसमें देश के कई धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

तिहाड़ में दूसरे कैदियों से बात नहीं कर रहा सेंगर

जासं, नई दिल्ली : उन्नाव की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर तिहाड़ के जेल नंबर तीन में बंद है। उसे दो अन्य कैदियों के साथ सेल में रखा गया है।

शुक्रवार को अदालत की ओर से सजा दिए जाने के बाद से कुलदीप सेंगर के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थीं। जेल सूत्रों ने बताया कि वह जेल में आने के बाद भी रोता दिखा। अन्य कैदियों से भी वह बात नहीं कर रहा था। शुक्रवार को पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। जेल का खाना भी नहीं खाया था।

राज्यपाल धनखड़ के सामूहिक बहिष्कार को देखते हुए विवि ने रद किया दीक्षा समारोह

जागरण संवाददाता, कोलकाता

जगदीप धनखड़। फाइल

▶ बंगाल के जेयू में बिना समारोह प्रदान की जाएंगी डिग्रियां

▶ वामपंथी छात्र संगठनों की धमकी की वजह से प्रबंधन ने उठाया कदम

जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विशेष दीक्षा समारोह रद करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार 24 दिसंबर को दीक्षा समारोह के आयोजन के बिना ही छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएंगी।

विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से दीक्षा समारोह में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के सामूहिक बहिष्कार की तैयारियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस बारे में विवि की रजिस्ट्रार स्नेहामंजु बसु ने बताया कि 24 दिसंबर को अब एक सादे कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया है।

वामपंथी छात्र संगठनों की धमकी की वजह से विशेष दीक्षा समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे पहले छात्र संगठनों की ओर से विवि के छात्रों के वाट्सएप पर एक संदेश प्रचारित कर कहा गया कि आगामी 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह का आयोजन है। वहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उपस्थित होने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों के राज्यपाल के क्रियाकलापों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वह भाजपा व आरएसएस के प्रचारक के तौर पर फांसीवादी एजेंडा आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मैसेज में छात्रों से अनुरोध किया गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से राज्यपाल का सामूहिक बहिष्कार करने के साथ उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और छात्र काला बैच लगाकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ नारा लगाएंगे।

गौरतलब है कि इसी जादवपुर विश्वविद्यालय की छात्रा गीतश्री सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के हाथों डिग्री लेने से इन्कार कर सुर्खियां बटोरी थी।

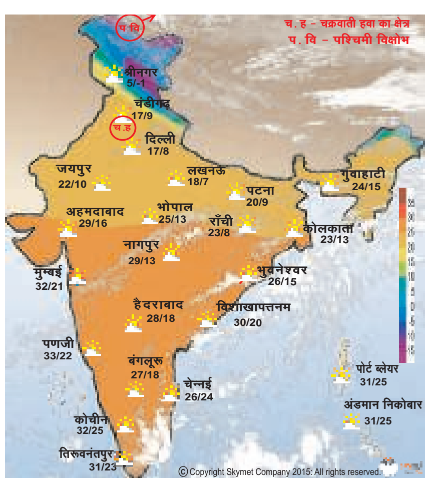

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बादल छाये रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात संभव है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा व कुहासां छाया रहेगा। आंशिक बादल छाये रहेंगे। दिन शीतल बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/22/आंबा	अहमदाबाद	27/10/आंबा
कोलकाता	23/13/आंबा	बड़ौदा	28/13/सा
चेन्नई	31/23/व	नागपुर	28/12/व
हैदराबाद	29/19/आंबा	इन्दौर	24/13/आंबा
बंगलूरू	27/18/आंबा	रांची	27/16/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/24/सा	पटना	23/17/आंबा
गुवाहाटी	22/15/आंबा	जमशेदपुर	31/18/व
गंगटोक	04/-7/आंबा	पुणे	30/22/आंबा

शाहबेरी के बिल्डर को मिली जमानत

जासं, ग्रेटर नोएडा : शाहबेरी के बिल्डर उस्मान मोहम्मद कुरैशी को जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है। पुलिस ने उस्मान के खिलाफ अवैध तरीके से फ्लैट बनाने व गलत जानकारी देकर लोगों को बेचने का आरोप लगाया था। आरोपित पिछले लगभग एक माह से जिला कारागार में बंद है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने आरोपित को पचास हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

पूर्व बार अध्यक्ष व उस्मान के अधिवक्ता प्रमेंद्र भाटी ने बताया प्राधिकरण द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने उस्मान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि उस्मान ने कृषि उपयोगी भूमि पर नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण किया। आरोपित ने अवैध रूप से बने फ्लैट, जमीन लोगों को झूठ बोलकर बेची कि यह प्राधिकरण से स्वीकृत है। यह भी आरोप लगाया था कि बनाए गए भवन असुरक्षित हैं।

ग्वालियर में लांसनायक ने साथी पर कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या की

नईदुनिया, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार छावनी परिषद स्थित गोल्फ कोर्स (ग्राउंड) में ड्यूटी पर तैनात दो लांसनायकों के बीच आपसी विवाद के बाद एक ने दूसरे की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। जिस जवान की जान गई, वह ओडिशा का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई। इसकी सूचना मुरार पुलिस थाने को शुक्रवार रात को दी गई। शनिवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

पुलिस के अनुसार गोल्फ कोर्स पर शुक्रवार को लांसनायक नारायण साहू (38) निवासी ओडिशा और लांसनायक भरत प्रजापति तैनात थे। उनमें पहले से कोई विवाद चल रहा था। उसे लेकर शुक्रवार को दोनों में फिर बहस हुई। इसी बीच लांसनायक भरत प्रजापति ने कुल्हाड़ी से नारायण पर हमला कर दिया। आसपास खड़े अन्य जवानों ने भरत को रोका और घटना की सूचना सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंभीररूप से घायल नारायण साहू को तत्काल सैन्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

▶ आर्मी गोल्फ कोर्स में तैनात दोनों में था पुराना विवाद

आर्मी एरिया में आरोपित का साथी से ही झगड़ा हुआ था। उसके बाद कुल्हाड़ी लगने से मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विवाद का कारण पता नही चल सका है।
–नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर

हत्या का केस दर्ज हिरासत में आरोपित

पुलिस ने मामले की जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हमले में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। आरोपित लांसनायक भरत प्रजापति को सेना ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद रविवार को सेना आरोपित को पुलिस को सौंप सकती है।

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 22 दिसंबर, 2019 से शनिवार 28 दिसंबर, 2019 तक — पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापार, नौकरी और उद्योग के कार्य में देरी, अर्थ साधन में प्रयास, पारिवारिक कार्य में प्रशंसा, दिनचर्या व्यस्त होगी, वाहन भवन का योग, संतान के लिए योजना, शिक्षा में एकाग्रता, शत्रुपक्ष से सावधान, प्रणय में सुख, धर्म में रुचि, राज्य पक्ष से सावधान, आय में सुधार, व्यय अधिक, शुभ अंक 4 ।

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
धन का योग सामान्य, लोगों से सहयोग, धन के आवागमन में सावधानी, भवन निर्माण योग, संतान से सहयोग, चयन में देरी, वाद-विवाद से बचें, प्रणय में अनबन, नए साथी का मिलन, रक्षा साधन कार्य में प्रगति, यंत्र विस्तार योजना, आय में सुधार, शुभ अंक 5 ।

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
अर्थ साधन में अवरोध, विदेश से समाचार, साहस की कमी, पारिवारिक सुख-शांति, भूमि-भवन का योग, संतान के लिए योजना, वाद-विवाद से बचें, खान-पान पर ध्यान दें, प्रणय में सुख, अनुबंध की प्राप्ति, निर्माण की रूपरेखा, व्यय अधिक, शुभ अंक 6 ।

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
व्यापार, उद्योग, नौकरी के कार्य में सहयोग, धन में अवरोध, साहस से कार्य करें, चिंता की समाप्ति, भवन सजावट का योग, चयन में देरी, शिक्षा में अवरोध, शत्रुपक्ष से सावधान, नेत्र विकार का योग, दांपत्य मे मतभेद, नए अनुबंध में देरी, वाहन में सावधानी व्यय अधिक, शुभ अंक 7

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
नौकरी, उद्योग, व्यापार के कार्य में सलाह से सफलता, अर्थ साधन में प्रयास, पराक्रम की कमी, साझेदारी में सावधानी, धन के आवागमन से सावधानी, भूमि-भवन विवाद की समाप्ति, चयन में अवरोध, अध्ययन अवरोध, शत्रुपक्ष प्रभावी, त्वचा-नेत्र विकार का योग, नए साथी से मिलन, शुभ अंक 8

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
अर्थ साधन ठीक, सलाह से निर्णय करें, विदेश समाचार, चिंता की समाप्ति, स्वजनों का सहयोग, भौतिक साधनों की वृद्धि, भावना पर नियंत्रण रखें, चयन में सफलता, दांपत्य में मधुरता, यात्रा का योग, अधिकारी से सहयोग, बैंक कार्य में सफलता, व्यय अधिक शुभ अंक 9

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
अर्थ साधन अच्छा, अर्थ कार्य करने वालों से सहयोग, दूसरों से सलाह से निर्णय करें, रचनात्मक कार्य का योग, भौतिक साधनों की वृद्धि, चयन में सफलता, वाद में विजय, दांपत्य सुख, अनुबंध की प्राप्ति, अधिकारी से सहयोग, आय में सुधार, व्यय पर नियंत्रण करें, शुभ अंक 1

वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थसाधन अच्छा, नए क्षेत्र में व्यापार योग, सामाजिक कार्य में सफलता, मन में अशांति, पारिवारिक चिंता, भौतिक साधनों का अनुबंध, यंत्र विस्तार योजना, अति विश्वास से बचें, व्यय अधिक, शुभ अंक 2

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, अर्थ साधन में प्रयास, सलाह से कार्य करें, चिंता की समाप्ति, भूमि-भवन योजना, संतान से सहयोग, खान-पान पर ध्यान दें, शत्रुपक्ष प्रभावी, प्रणय में सुख, वाहन में सावधानी, निर्माण योजना, राज्यपक्ष से सावधान, व्यय अधिक, शुभ अंक 4

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में अर्थ साधन अच्छा, धन के लेन-देन में सावधानी, चिंता का समाधान, विशेष व्यक्ति से मिलन, स्त्रीपक्ष से सहयोग, वाहन-भवन योग, संतान की चिंता, अध्ययन में एकाग्रता, मित्रों से सहयोग, प्रणय में मधुरता, यात्रा में सावधानी, व्यय अधिक, शुभ अंक 5

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
नौकरी, व्यापार, उद्योग के कार्य में अवरोध, धन साधन में प्रयास, नए कार्य से बचें, विदेश से समाचार, पारिवारिक चिंता, अध्ययन में एकाग्रता, चयन में देरी, दांपत्य में अनबन, धर्म में रुचि, स्थान परिवर्तन, अधिकारी से सहयोग, व्यर्थ की चिंता, शुभ अंक 6

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में अवरोध, धन में प्रयास, नए कार्य से बचें, विदेश से कार्य का योग, चिंता की समाप्ति, भूमि विवाद की समाप्ति, शिक्षा में एकाग्रता, चयन में सफलता, कुसंग से बचें, सिर तथा त्वचा पीड़ा का योग, नए साथी का मिलन, अधिकारी से अनबन, व्यय पर नियंत्रण, शुभ अंक 7

वी-2 रॉकेट निर्माण के आदेश पर हिटलर ने किए हस्ताक्षर

आज ही के दिन 1942 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वी-2 रॉकेट के बड़ी संख्या में उत्पादन के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह दुनिया का पहला तरल प्रणोदक रॉकेट वाहन और पहली लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ।

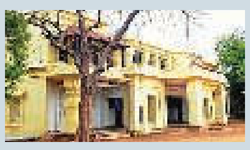

विश्व भारती आश्रम आज ही आया था अस्तित्व में

आज ही 1901 में रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में प्राचीन गुरुकुल पद्धति पर आधारित आश्रम शुरू किया। आज यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है। टैगोर ने विश्व भारती को लेकर कहा था कि यह भारत का प्रतिनिधित्व करती है और भारत की बौद्धिक संपदा सभी के लिए है।

गणित में डूबा एक भारतीय सितारा श्रीनिवास रामानुजन

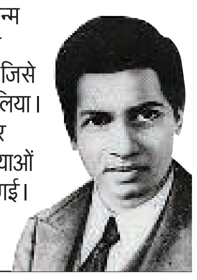

आज ही 1887 में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के छोटे से गांव इरोड में हुआ था। 1913 में उन्होंने कैंब्रिज के गणितज्ञ प्रो. हार्डी को प्रमेयों की लंबी सूची भेजी। जिसे पढ़ने के बाद हार्डी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को बुला लिया। 1918 में उन्हें कैंब्रिज फिलोसॉफिकल सोसायटी, रॉयल सोसायटी और ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया। गणित की करीब चार हजार समस्याओं का हल निकाला। अप्रैल 1920 को 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 2012 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई।

इधर-उधर की

सैन फ्रांसिस्को में गुम हुए कुत्ते की विमान से खोज

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी : एक महिला ने अपने गुम कुत्ते की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने नीली आंखों वाले छोटे ऑस्ट्रेलियाई शेफर्ड को विमान से खोजा और ढूंढने वाले शख्स को सात हजार डॉलर (करीब 4 लाख 97 हजार रुपये) का ईनाम देने की घोषणा की है। एमिली टालेरमो का कुत्ता एक ग्रॉसरी स्टोर के बाहर से गायब हो गया। एमिली ने कुत्ते को ढूंढने में विमान का इस्तेमाल किया। इस पर 12 सौ डॉलर (करीब 85 हजार रुपये) का खर्च आया। उसने विमान से एक बैनर लहराया जिसमें 5 साल के कुत्ते जैक्सन को ढूंढने के लिए बनाई एक वेबसाइट का पता था। साथ ही एमिली ने अपने दोस्तों के साथ जैक्सन की फोटो लगे पर्चे भी बांटे। एमिली ने कहा कि जो लोग पिछले सालों में मुझसे मिले हैं, वे इस कुत्ते को लेकर मेरे प्यार को जानते हैं। मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगी।

हार्ट अटैक के खतरे का अनुमान लगा सकती है एआइ तकनीक

प्रतीकात्मक

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : दिल के दौरे और हृदय से जुड़ी बीमारियों का अनुमान अब समय रहते लगाया जा सकता है, जिससे मरीजों की असमय मौत के खतरे को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिकित्सकीय परीक्षणों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से दिल के दौरे और हृदय संबंधी बीमारियों का बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लग सकता है।

कार्डियोवस्कुलर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन लिए शोधकर्ताओं ने मध्यम आयु वर्ग के उन प्रतिभागियों को शामिल किया, जिनमें हृदय संबंधी रोग होने का जोखिम अधिक था। अमेरिका के सीडर-सिनाई मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने दिल के दौरे और हृदय संबंधी बीमारियों का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। मशीन लर्निंग के जरिये ही कंप्यूटरों को बीमारियों के बारे में स्वतः संज्ञान लेने में सक्षम बनाया जाता है। इसके जरिये हृदय रोग के जोखिम वाले कारकों की पहचान भी आसानी से की जा सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'हृदय संबंधी रोग अचानक ही सामने नहीं आते हैं। लंबे समय तक अनियमित दिनचर्या और प्रदूषित वातावरण में रहने से हृदय से जुड़ी समस्याएं पनपती हैं। जब तक डॉक्टर इन बीमारियों के बारे में कोई अनुमान लगा पाते हैं तब तक रोग काफी बढ़ जाता है और कई बार मरीज की मौत तक हो जाती है। ऐसे में एआइ तकनीक काफी मददगार सिद्ध हो सकती है।'

किसानों को सशक्त बना सकती है हाइड्रोपोनिक खेती

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : बढ़ते शहरीकरण के कारण एक ओर खेती का रकबा सिकुड़ रहा है तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से भी फसल उत्पादन में चुनौतियां उभर रही हैं। इनसे निपटने और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए हाइड्रोपोनिक खेती किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आइएचबीटी), पालमपुर में विशेषज्ञों ने यह बात हाइड्रोपोनिक खेती पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही है।

हाइड्रोपोनिक खेती की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। इस पद्धति में मिट्टी के बजाय सिर्फ पानी या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच पौधों की खेती की जाती है। नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85 फीसद आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक खेती की जाती है। आइएचबीटी के वैज्ञानिक डॉ. भव्य भार्गव ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों को बताया कि हाइड्रोपोनिक पद्धति में पौधों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए जरूरी पोषक तत्व एवं खनिज पदार्थों से युक्त एक विशेष घोल का उपयोग किया जाता है। इस घोल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर और आयरन जैसे तत्वों को खास अनुपात में मिलाया जाता है। एक निश्चित अंतराल के बाद इस घोल की एक निर्धारित मात्रा का उपयोग पौधों को पोषण देने के लिए किया जाता है।

> स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है यह प्रणाली
>
> नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं पौधे

15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है हाइड्रोपोनिक खेती। साभार : आइएसडब्ल्यू

आधुनिक पद्धतियों को सीखना जरूरी : आइएचबीटी के निदेशक डॉ. संजय कुमार ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता की फसलों की खेती करने के लिए किसानों को तकनीक आधारित आधुनिक कृषि पद्धतियों को सीखना जरूरी हो गया है। हाइड्रोपोनिक कृषि उत्पादों की बड़े शहरों में काफी मांग है। युवा किसान पोषक तत्वों से समृद्ध मसाले, हर्बल और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन के लिए स्टार्टअप व्यवसाय के रूप में हाइड्रोपोनिक प्रणाली को अपना सकते हैं।

सीमित स्थानों पर होगी खेती : इस प्रणाली की एक खास बात यह है कि छोटे भूखंड या सीमित स्थान में भी खेती की जा सकती है। आइएचबीटी के एक अन्य वैज्ञानिक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि हाइड्रोपोनिक प्रणाली मौसम, जानवरों या किसी भी अन्य प्रकार के बाहरी जैविक या अजैविक कारकों से प्रभावित नहीं होती। हाइड्रोपोनिक खेती में पानी का किफायती उपयोग इसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है।

शुरुआती लागत है अधिक : वैज्ञानिकों ने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन भविष्य में यह किसानों को बेहतर लाभ प्रदान कर सकती है। आइएचबीटी के वैज्ञानिक कम लागत वाली हाइड्रोपोनिक प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे इसका लाभ छोटे किसानों को भी मिल सके।

पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जमी है 'लोहे की बर्फ'

लगाया पता ▸ लौह कणों से बनी परत से ढका है आंतरिक कोर

अमेरिका की टेक्सास और टेनेसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा

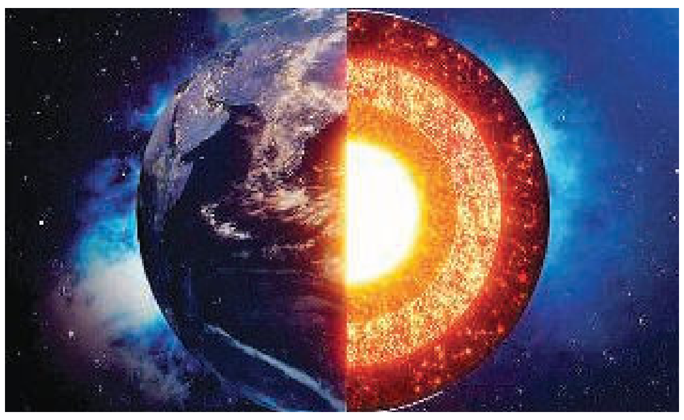

यह अध्ययन जेजीआर सॉलिड अर्थ नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। फाइल

ह्यूस्टन, प्रेट्र : पृथ्वी के सबसे भीतरी हिस्से यानी आंतरिक कोर में 'लोहे की बर्फ' जमी हुई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस कोर की ऊपरी परत में लोहे और निकल से बनी तरल परत है। इसी परत से आंतरिक कोर के बाहरी हिस्से में बर्फ की तरह लौह कण गिरते रहते हैं और ठोस परत का निर्माण करते हैं। भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण कर शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि आसमान से गिरते हिमकणों की अपेक्षा इन लौह कणों का भार अधिक होता है।

जेजीआर सॉलिड अर्थ नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि जैसे बादलों से हिमकण एकत्र होकर पृथ्वी पर गिरते हैं और उसके बाद ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही लौह कण भी पृथ्वी के बाहरी कोर वाले हिस्से से पिघलकर आंतरिक हिस्से में चले जाते हैं और पूरे हिस्से को ढक लेते हैं।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने कहा, 'इस अध्ययन के लिए उन्होंने भूकंपीय तरंगों के संकेतों का विश्लेषण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि भूकंपीय तरंगें जब अपने केंद्र से बाहरी कोर की ओर गुजरती थीं तो पुराने अनुमानों की अपेक्षा बहुत धीमी हो गई थीं, लेकिन जैसे ही तरंगें आंतरिक कोर से पूर्वी गोलार्ध की ओर गुजरीं तो उनकी गति अपेक्षाकृत तेज हो गई थी।' शोधकर्ताओं ने कहा कि इसका कारण यह है कि आंतरिक कोर के इस हिस्से में मौजूद लौह कणों की परत बहुत पतली है, जिसके कारण भूकंपीय तरंगें तेजी से प्रसारित हो जाती हैं, जबकि आंतरिक कोर के पश्चिमी भाग में इस परत की मोटाई ज्यादा है, इसलिए, भूकंपीय तरंगें पश्चिमी गोलार्ध में तीव्र गति से प्रसारित नहीं हो पाती हैं। अध्ययन में शामिल अमेरिका के टेनेसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता निक डायगट ने बताया कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में लौह कणों के जमा होने की प्रक्रिया बर्फबारी जैसी है।

तीन परतों में बंटी हुई है पृथ्वी

यूं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई परतों से बनी हुई है। सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस परत है, मध्यवर्ती मैंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य कोर तरल तथा आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है।

भूपर्पटी : यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी औसत गहराई 24 किमी तक है और यह गहराई 5 किमी से 70 किमी के बीच बदलती रहती है। समुद्रों के नीचे यह कम मोटी समुद्री बेसाल्टिक भूपर्पटी के रूप में है तो महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तार अधिक गहराई तक पाया जाता है।

मैंटल : मैंटल का विस्तार भूपर्पटी के बाद लगभग 2890 किमी की गहराई तक है। यहां संवहनीय धाराएं चलती हैं जिनके कारण स्थलमण्डल की प्लेटों में गति होती है।

क्रोड : यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। इसमें निकल तथा लोहे के कणों की प्रधानता होती है। यह लगभग 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका घनत्व 11-12 तक है तथा औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेमी है। इसका भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/3 है।

स्वागत के लिए तैयार है बर्फ का होटल

बर्फ से बना दुनिया का पहला होटल अपनी 30 वीं वर्षगांठ पर नए डिजाइन के कमरों और बर्फ पर की गई शानदार नक्काशीदार कलाकृतियों के साथ अपने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। स्वीडन के लैपलैंड में स्थित यह होटल सिर्फ सर्दी के मौसम में खुलता है। इसके कमरे, पलंग, बाथटब, थियेटर सभी बर्फ से तैयार किए गए हैं। इसके लिए 2.5 टन वजनी बर्फ के 1000 ब्लॉकों का उपयोग किया गया है। इसमें लाल, नीले, सफेद और पीले रंगों का अद्भुत प्रयोग किया गया है। इसके लिए बर्फ जमी हुई टॉर्न नदी से काटकर लाई जाती है। इस वर्ष होटल को नया रंग-रूप और डिजाइन करने के लिए 16 देशों के 33 आर्टिस्टों डिजाइनरों ने दिनरात काम किया। साभार : गार्जियन

शोध अनुसंधान

एआइ कर सकता है ब्लड कैंसर की बेहतर पहचान

एक अध्ययन में पाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद से ब्लड कैंसर के सबसे आम प्रकार एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया (एएमएल) की बेहतर पहचान हो सकती है। इस तरीके से ज्यादा विश्वसनीय नतीजा आ सकता है। आइसाइंस पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार, यह पद्धति रक्त में कोशिकाओं की जीन गतिविधियों के विश्लेषण पर आधारित है। एएमएल जानलेवा बीमारी है और इसका यथासंभव शीघ्र उपचार करना चाहिए। जर्मन सेंटर फॉर न्यूरोडीजेनेरेटिव डिजीज के शोधकर्ता जोचिम शुल्ट्ज ने बताया कि 105 अध्ययनों में इस्तेमाल किए गए 12 हजार से ज्यादा रक्त नमूनों पर गौर किया गया। इनमें से करीब 4100 रक्त नमूने एएमएल से पीड़ित रोगियों से एकत्र किए गए थे। -आइएएनएस

फैटी लिवर से बचाव कर सकता है प्रोटीन

शोधकर्ताओं ने यह पहली बार पाया है कि एसआइआरटी6 नामक प्रोटीन फैटी लिवर और लिवर डिजीज से बचाव कर सकता है। इस प्रोटीन की उम्र बढ़ने, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध, इंफ्लेमेशन और मेटाबोलिज्म जैसी कई जैविक प्रक्रियाओं के नियंत्रण में भूमिका होती है। लिवर कोशिकाओं में अत्यधिक फैट (वसा) जमा होने से फैटी लिवर और दूसरी बीमारियों का खतरा खड़ा हो सकता है। सेल रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पहली बार पाया कि लिवर फैट मेटाबोलिज्म की खपत और नियंत्रण में भी एसआइआरटी6 की अहम भूमिका होती है। इजरायल की बार-इलान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेम कोहेन ने कहा, 'एसआइआरटी6 प्रोटीन शरीर में मेटाबोलिक (चयापचय) प्रक्रियाओं के बीच संतुलन और समन्वय जैसा काम करता है। -एएनआइ

मां से विरक्त हुई मादा गोरिल्ला

अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के सबसे बड़े शहर ओमाहा में हेनरी डोरली जू के अपने बाड़े में वेस्टर्न लोलैंड मादा गोरिल्ला जूरी। इसका जन्म इसी वर्ष पांच मई को हुआ है। यह 15 वर्षीय बाम्बियो की पहली संतान है। जूरी अपनी मां का दूध नहीं पी सकी। जीवन रक्षा के लिए इसे जू-कीपर्स बोतल से फीडिंग करा रहे हैं। आमतौर पर इस प्रजाति के गोरिल्ला मध्य अफ्रीका में अंगोला, कैमरुन, कांगो आदि के तराई के इलाकों में पाए जाते हैं। यह वेस्टर्न गोरिल्ला की सबसे छोटी उपप्रजाति है। यह गोरिल्ला की ऐसी एकमात्र उपप्रजाति है, जिन्हें चिड़ियाघरों में रखा जा सकता है। इनके संरक्षण पर भी यहां काफी रिसर्च की जा रही है। एपी

ऑस्ट्रेलिया में दावानल

झुलसा देने वाली गर्मी के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर सिडनी से करीब 130 किमी दूर दक्षिण-पश्चिम बाल्मोरल में आग से हालात बेकाबू हो गए हैं। इतना ही नहीं, पूर्वी तटीय इलाके में तीन मिलियन हेक्टेयर (करीब 7.4 मिलियन एकड़) के जंगल आग से तबाह हो गए हैं, जो बेल्जियम जैसे देश के बराबर का इलाका है। न्यू साउथ वेल्स में करीब 800 घर जलकर नष्ट हो गए हैं। आग का असर सिडनी शहर और आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। यहां हवा में जहरीला धुआं तेजी से फैल रहा है। इससे लोगों को श्वांस संबंधी दिक्कतें होने लगी हैं। एएफपी

स्क्रीन शॉट

अक्षय कुमार नहीं कर रहे हैं अजित डोभाल पर बनने वाली फिल्म

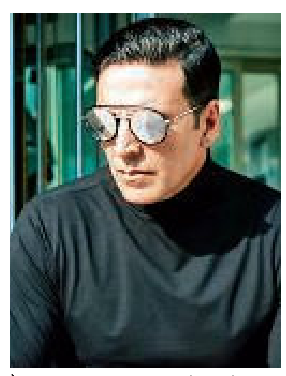

हिंदी सिनेमा में इन दिनों बायोपिक फिल्में बनाने में फिल्मकार खासी रुचि ले रहे हैं। कलाकार भी उन्हें हाथोंहाथ ले रहे हैं। अक्षय कुमार पैडमैन के नाम से विख्यात अरुणाचलम मुरुगनाथम की बायोपिक 'पैडमैन' कर चुके हैं। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें वह पृथ्वीराज की भूमिका निभा रहे हैं। बीते दिनों खबर आई थी वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर बनने वाली फिल्म कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में डोभाल की भूमिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनका मुरीद बना दिया था। इसके बाद 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहृत किए गए रोमानियाई राजनयिक लिविउ राडू को बचाने की सफल योजना बनाना हो या फिर गुलाम कश्मीर में घुसकर आतंकियों के कैंप को नष्ट करने का ऑपरेशन, डोभाल ने हर जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। फिल्मी गलियारों की खबरों में कहा गया था कि अक्षय कुमार अजित डोभाल की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म कर रहे हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने इससे साफ इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि वह ऐसी कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस खबर को अफवाह बताया है। अक्षय इन दिनों 'लक्ष्मीबम', 'पृथ्वीराज चौहान', 'सूर्यवंशी', 'बच्चन पांडे' और 'बेलबॉटम' कर रहे हैं। वहीं उनकी 'गुड न्यूज' 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। उसमें उनकी पत्नी की भूमिका में करीना कपूर खान नजर आएंगी। उनके साथ दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी प्रमुख भूमिका में हैं। कियारा को अक्षय कुमार ने ही अपनी प्रोडक्शन हाउस तले बनी फिल्म 'फगली' से लॉन्च किया था।

पापा बोनी के साथ जल्द काम कर सकती हैं जाह्नवी कपूर

श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर भले ही एक ही फिल्म पुरानी हों, लेकिन वर्ष 2020 में उनकी कई फिल्में रिलीज होंगी। वह 'घोस्ट स्टोरीज' से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखेंगी। उसके अलावा उनकी फिल्में 'कारगिल गर्ल', 'रूही अफ्जा', 'तख्त' और 'दोस्ताना 2' आएंगी। जाह्नवी लगातार बड़े बैनर और अनुभवी निर्देशकों के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म 'धड़क' से अपनी पहचान बना ली है। लेकिन जाह्नवी को अब भी लगता है कि अपने पापा बोनी कपूर के प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए उन्हें पहले वह हक कमाना होगा। वह कहती हैं कि जब मैं अपने पापा के साथ काम करूंगी तो वह कुछ स्पेशल ही होगा। जाह्नवी का कहना है कि जल्द ही वह अपने पापा के साथ काम कर सकती हैं। एक-दो कहानियां हैं, जिनमें दोनों की दिलचस्पी है। जैसे ही उस प्रोजेक्ट पर आगे काम शुरू होगा, वे साथ काम करेंगे। जाह्नवी कहती हैं कि उनके पिता बड़े दिल वाले निर्माता हैं। उनके पास जिस तरह की बुद्धिमत्ता है, वह बहुत कम लोगों के पास होती है। पहली फिल्म पापा के साथ न करने को लेकर जाह्नवी कहती हैं कि वह शुरुआत से ही बहुत स्पष्ट थीं कि पहली फिल्म उनके पापा बोनी कपूर के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेपोटिज्म को लेकर बहस जारी थी। पापा जिस तरह के प्रोजेक्ट में व्यस्त थे वे काफी अलग हैं।

...जब अमिताभ बच्चन ने पूछा कि यह बॉलीवुड क्या है?

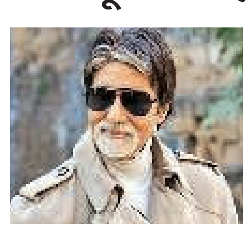

पत्रकारिता व एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे अमित खन्ना हिंदी सिनेमा के लिए बॉलीवुड शब्द का प्रयोग करने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। शुक्रवार को मुंबई में उनकी किताब 'वर्ड्स साउंड्स ऐंड इमेजेज ए हिस्ट्री ऑफ मीडिया ऐंड एंटरटेनमेंट इन इंडिया' के विमोचन समारोह में तमाम फिल्मी हस्तियां जुटीं। इस मौके पर जावेद अख्तर ने बताया कि वह 20-21 साल की उम्र में ही फिल्में लिखने लगे थे। उन्होंने बताया कि पहले फिल्म इंडस्ट्री में लोग हिंदी या उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे और गिने-चुने लोग ही अंग्रेजी बोलते थे। जावेद ने कहा, 'एक दिन मुझे एक निर्माता ने बताया कि देव आनंद साहब के यहां एक नया लड़का आया है, जो मुझसे भी युवा है और किसी भी मुद्दे पर बात कर सकता है। वह दिलीप कुमार की तरह अंग्रेजी बोलता है। मैं डर गया कि कौन है, जो मुझे इंडस्ट्री से बाहर करवा सकता है। वह अमित खन्ना थे। आज इंडस्ट्री में जो बदलाव आया है, अमित ने वर्षों पहले हमें बता दिया था।' बॉलीवुड शब्द लिखने के बारे में अमित ने कहा, 'एक बार अमिताभ बच्चन ने गुस्सा होकर मुझसे पूछा कि आप जो बॉलीवुड-बॉलीवुड करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैंने उन्हें समझाया कि बॉलीवुड एक ब्रांड की तरह है और दूसरे ब्रांड की तरह इस शब्द का भी कोई मतलब नहीं है। पहले हिंदी सिनेमा को किसी एक नाम से नहीं बुलाया जाता था।'

जो सपने देखते हैं... वो पंगा लेते हैं...

फिल्म 'पंगा' में कंगना रनोट का लुक रिलीज किया जा चुका है। फिल्म में उनके अलावा रिचा चड्ढा भी अहम भूमिका में हैं। रिचा ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर पोस्ट किया है, जिसमें वह और कंगना साथ बैठी हैं। कंगना सूट में नजर आ रही हैं, तो वहीं रिचा जींस-शर्ट और लेदर जैकेट पहने बैठी हैं। रिचा ने इस फोटो के साथ लिखा, 'जो सपने देखते हैं, वो पंगा लेते हैं। जया और मीनू, इनकी दोस्ती का कहानी हम सब से जुड़ी है।' फिल्म का ट्रेलर 23 दिसंबर को रिलीज होगा, जबकि फिल्म अगले वर्ष 24 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। फिल्म में रिचा और कंगना सहेलियां बनी हैं।

अध्ययन

बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं ने किया दावा, कहा- हरे-भरे क्षेत्र लोगों को शारीरिक गतिविधियों में रखते हैं व्यस्त

मोटापा कम करने में मददगार हैं हरित क्षेत्र

लंदन, आइएएनएस : यह तो सभी जानते हैं हरे-भरे वातावरण से मन तो प्रफुल्लित रहता है और ऐसे वातावरण के बीच व्यायाम करने से तन भी तंदुरुस्त रहता है। अब एक नए शोध से पता चला है कि बाग-बगीचों से 300 मीटर के दायरे में रहने वाली महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम वजनी होती हैं और उन्हें मोटापे की समस्या भी अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि वे शारीरिक गतिविधियों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं। हाल ही में स्पेन में हुए एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइजीन एंड इंवायरमेंटल हेल्थ में प्रकाशित हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने महिलाओं के मामले में हरे-भरे वातावरण (बाग-बगीचे, पार्क इत्यादि) का ज्यादा वजन और मोटापे के बीच एक संबंध पाया है, जबकि पुरुषों के मामले में किसी प्रकार का कोई संबंध देखने को नहीं मिला।

बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ से जुड़े और इस अध्ययन के शोधकर्ता मनोलिस कोगेविनास ने कहा कि यह अध्ययन हरित क्षेत्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताता है।

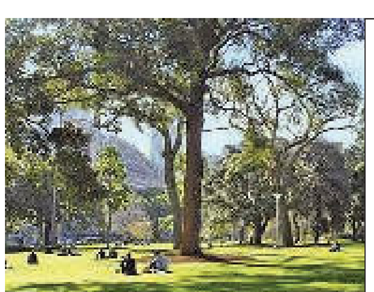

प्रतीकात्मक

प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखना भी है जरूरी

शोधकर्ताओं ने कहा कि बदलती जीवनशैली का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर पड़ता है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां के हरित क्षेत्र विकास के नाम पर 'कंक्रीट के जंगलों' में बदल गए हैं। यह बदलाव साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। यदि हमें देश की आबादी में स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ानी है तो हरित क्षेत्रों के साथ-साथ प्राकृतिक वातावरण को भी बनाए रखना होगा।

190 करोड़ लोग ज्यादा वजन की समस्या से हैं ग्रस्त : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक, विश्व में 190 करोड़ लोग ओवरवेट यानी ज्यादा वजन की समस्या से ग्रस्त हैं। इनमें 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें मोटापे के जोखिमों से बचाया जा सकता है।

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है हरित क्षेत्र : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने स्पेन के सात प्रांतों (अस्टुरिया, बार्सिलोना, कैंटाब्रिया, मैड्रिड, मर्सिया, नावर्रे और वेलेंसिया) के 2,354 लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन की प्रमुख लेखक क्रिस्टीना ओ कैलाघन-गॉर्डो ने कहा, 'अध्ययन के दौरान हमने पाया कि जो महिलाएं हरित क्षेत्रों के आसपास रहती थीं, पुरुषों के मुकाबले उनमें मोटापा कम पाया गया क्योंकि इन इलाकों की महिलाएं खुद को पुरुषों के बनिस्पत ज्यादा व्यस्त रखती हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।'